



विद्या भारती
उच्च शिक्षा संस्थान
Vidya Bharati
Uchcha Shiksha Sansthan



2023

प्रतिवेदन

अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम

NSIL 2023

अंतर संस्थागत विकास पर एक संवाद

अखिल भारतीय संस्थागत
नेतृत्व समागम

NSIL 2023

प्रकाशक

विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान

H-107 A, सेक्टर-12, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर

उत्तरप्रदेश- 201301

<http://www.vbuss.org>

भारत में प्रथम संस्करण- 2023

सर्वाधिकार सुरक्षित:-

इस पुस्तक में लेखकों द्वारा व्यक्त किए गए विचार व मत उनके व्यक्तिगत हैं तथा संदर्भित किये गए तथ्यों का यथासंभव सत्यापन किया गया है। अतः भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकाशन उत्तरदायी नहीं होगा।

इस पुस्तक को प्रकाशक के अनुमति के बिना किसी भी माध्यम से जैसे- एलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी अथवा रिकॉर्डिंग इत्यादि के स्वरूप में पुनरुत्पादित, संरक्षित व प्रेषित नहीं किया जा सकता।

आवरण व अभिन्यास- जागृति सिंह, अर्णव जैन

मुद्रक- भारत इंटरप्राइजेस

अखिल भारतीय संस्थागत
नेतृत्व समागम

NSIL 2023

विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान- एक परिचय

1952 से विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान /वीबीयूएसएस ने भारत के शैक्षणिक जगत के प्रत्येक आयामों पर गहरा प्रभाव डाला है। यह युवाओं को शिक्षित कर उनमें सांस्कृतिक, नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों को जगाने के द्वारा राष्ट्र के लिए एक सक्षम पीढ़ी का निर्माण करने की कल्पना करता है। विद्या भारती के पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियाँ भारतीय शैक्षिक दर्शन की तर्ज पर सामाजिक मूल्यों और भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर आधारित हैं जो ज्ञान, कौशल और प्रेरणा के माध्यम से छात्र के व्यक्तित्व को विकसित करती हैं।

विद्या भारती सरस्वती शिशु वाटिका, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का संचालन करती है। 25 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय तकनीकी और कुशल शिक्षकगण का निर्माण करने के लिए हैं। इनके अलावा, विद्या भारती द्वारा संचालित 40 डिग्री कॉलेज भी हैं। इस तरह से, विद्या भारती स्कूल शिक्षा प्रणाली के साथ-साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही है, और वीबीयूएसएस द्वारा किये गए कार्य विस्तार से समाज द्वारा स्वीकृत हो रहे हैं।

उच्च शिक्षा के आदर्श और गतिविधियों को निर्धारित करने के लक्ष्य के साथ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अवधारणाओं को साकार करने के लिए विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई थी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्थानों से संपर्क, संवाद और समन्वय स्थापित कर सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम करने की तत्काल आवश्यकता है। विद्या भारती इसलिए उत्कृष्टता के केंद्र बनाने का प्रयास करती है जो पारंपरिक और अपरंपरागत, प्राचीन और आधुनिक, ओरिएंटल और पाश्चात्य को जोड़ती है।

**अंतर संस्थागत विकास
पर एक संवाद**

प्रस्तावना

विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान (वीबीयूएसएस) ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के सहयोग से, “अंतर-संस्थागत विकास पर संवाद” पर दो-दिवसीय शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन को उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय संघ का समर्थन मिला।

एनईपी-2020 में उच्च शिक्षा में मौलिक बदलाव लाने के लिए साहसिक, प्रगतिशील, दूरगामी और व्यापक सुधारों की परिकल्पना की गई है। नीति के विकास के इस प्रक्षेपवक्र में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए, अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2023, का उद्देश्य भारत भर के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों, प्रतिकुलाधिपतियों, कुलपतियों और प्रमुख प्रोफेसरों को एक साथ लाना है ताकि वे सुधारों की संस्कृति को शामिल करने और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने संस्थानों में अपनाई गई नवीन प्रथाओं से संबंधित अपने विचारों को साझा कर पाएं।

पिछले कुछ महीनों के दौरान, एन एस आई एल 2023 के विचार की परिकल्पना वीबीयूएसएस अकादमिक परिषद के सदस्यों, कुलपतियों, और विभिन्न विश्वविद्यालयों और राज्यों के वरिष्ठ शिक्षाविदों की अनौपचारिक बैठकों के दौरान की गई थी। इन चर्चाओं में, उच्च संस्थान के नेतृत्वकर्ताओं के बीच एक ही छत के नीचे औपचारिक विचार-विमर्श करने के लिए एक आम सहमति बनी, जिनकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 की सिफारिशों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, ताकि वे अपनी संस्थागत प्रथाओं को साझा कर सकें और एक दूसरे के साथ रचनात्मक समाधानों का आदान-प्रदान कर सकें। उच्च शिक्षा संस्थानों के नेतृत्वकर्ताओं ने एनईपी 2020 में परिकल्पित सुधारों को लागू करने के लिए एक मजबूत और समन्वित प्रतिबद्धता व्यक्त की।

मैं मध्य प्रदेश सरकार, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की आयोजन समिति और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के सदस्यों को शिखर सम्मलेन के सफल समापन को सुनिश्चित करने के लिए सभी संस्थागत नेतृत्वकर्ताओं और अन्य हितधारकों को एक साथ लाने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

डॉ कैलाश चंद्र शर्मा
राष्ट्रीय अध्यक्ष
विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान

अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम(एन.एस.आई.एल) पर एक नज़र

आज के गतिशील समाज में प्रत्येक व्यक्ति के कामकाज के तरीके में लगातार बदलाव की आवश्यकता है, और शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन है। इस बदलाव के आलोक में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य युवा पीढ़ी में एक व्यवहारिक क्रांति की मशाल प्रज्वलित करना है, ताकि नए भारत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सके। एनईपी-2020 के तहत, उच्च शिक्षा परिदृश्य में कई प्रगतिशील उपाय पेश किए गए हैं, और भविष्य के लिए कई और उपायों की कल्पना की गई है। सुधारों की गति स्थिर रही है और उच्च शिक्षा प्रणालियों के नेतृत्वकर्ताओं की ओर से एक मजबूत प्रतिबद्धता देखी गई है। उच्च शिक्षा इस परिवर्तन को लाने में सहायक हो सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत का विकास, गतिशील समाज की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को लागू करने के लिए और अंतर-संस्थागत भागीदारी को बढ़ाने के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश के सहयोग से विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा अंतर-संस्थागत विकास पर संवाद आयोजित किया गया।

इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नए युग की समस्याओं के सरल समाधान और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का विकास करना भी था। इसने भारतीय शिक्षा प्रणाली को सीखने के लिए एक दृष्टिकोण तैयार करने का प्रयास किया, जिसमें टॉप-डाउन दृष्टिकोण को बॉटम-अप दृष्टिकोण के साथ जोड़ा गया और परिणाम-आधारित शिक्षा को प्रधानता दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन से संबंधित सर्वसम्मति-आधारित निर्णय लेने के लिए संस्थागत प्रतिनिधि एक साथ आए ताकि वे मैकाले की शिक्षा के बजाय भारतीय ज्ञान प्रणाली में निहित समाज के निर्माण के लिए एक उपयुक्त कार्य योजना तैयार कर सकें।

उच्च शिक्षा संस्थानों के नेताओं द्वारा एनईपी-2020 में परिकल्पित सुधारों के कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत और समन्वित प्रतिबद्धता बनाई गई थी। कक्षाओं को 'शिक्षण के क्षेत्र' से 'सीखने के स्थान' में बदलना; निर्णय लेने में नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण के साथ ऊपर से नीचे का संयोजन, उच्च शिक्षा संस्थानों की शिक्षा, संरचनाओं और प्रक्रियाओं में सहयोग; परिणामों के आधार पर प्रदर्शन का आकलन; मूल्यांकन की एक प्रणाली जो पारदर्शी है और सीखने वाले का आकलन करती है न कि शिक्षार्थी का; सामाजिक रूप से संवेदनशीलता को बढ़ावा देना और उत्साह के साथ काम करना, करुणा के साथ आगे बढ़ना और दृढ़ विश्वास के साथ हासिल करना, दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान इकट्ठे हुए उच्च शिक्षा संस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा की गई अन्य महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं थीं।

उपस्थित प्रतिनिधियों की कुल संख्या - 1298

प्रतिनिधि वक्ताओं की संख्या- 54 वक्ता

प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों की कुल संख्या - 23 राज्य

एमपी राज्य संस्थानों की संख्या - 107 (सरकारी) और 08 (निजी)

सत्र योजना

पहला दिन - 16 जनवरी 2023

समय	सत्र	वक्ताओं
10:30 am-12:30 pm	उद्घाटन	<p>डॉ. सुभाष सरकार, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार डॉ. मोहन यादव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार प्रो. एम. जगदीश कुमार, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डॉ. कैलाश चंद्र शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान (वीबीयूएसएस) प्रो. रेणु जैन, कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी), इंदौर प्रो. भरत शरण सिंह, अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय शुल्क नियामक आयोग</p>
1:30 pm- 2:45 pm	समानांतर सत्र 1	<p>समूह 1 कुलपतियों और निदेशकों के साथ बातचीत वक्ता प्रो. एम. जगदीश कुमार, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सत्र मॉडरेटर प्रो. प्रशांत गुप्ता, प्रोफेसर, भा.प्र.सं. नागपुर</p>
1:30 pm- 2:45 pm	समानांतर सत्र 1	<p>समूह 2 अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट: मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट वक्ता प्रो. एसके गाखर, पूर्व कुलपति, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, रेवाड़ी प्रो. आरपी तिवारी, वाइस चांसलर, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रो नवीन शेठ, पूर्व कुलपति, गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय</p>

समय	सत्र	वक्ताओं
1:30 pm- 2:45 pm	समानांतर सत्र 1	<p>समूह 3 बहुआयामी और समग्र शिक्षा वक्ता प्रो. अमी उपाध्याय, कुलपति, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद डॉ. गौरीशा जोशी, प्रोफेसर और निदेशक, शिक्षा और सामाजिक अध्ययन केंद्र, बेंगलुरु। प्रो. विभा सिंह चौहान, पूर्व प्राचार्य, किरोड़ीमल कॉलेज, नई दिल्ली</p>
1:30 pm- 2:45 pm	समानांतर सत्र 1	<p>समूह 4 उच्च शिक्षण संस्थानों में अभिनव प्रयोग वक्ता प्रो. पंकज मित्तल, महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ प्रोफेसर डीपी गोयल, निदेशक, आईआईएम शिलांग प्रो. बी.वी.आर. रेड्डी, निदेशक, एनआईटी कुरुक्षेत्र</p>
1:30 pm- 2:45 pm	समानांतर सत्र 1	<p>समूह 5 वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड आईसीटी वक्ता प्रो. नागेश्वर राव, कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय प्रो. बिनोद कुमार कनौजिया, निदेशक, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर</p>
3:15 pm- 4:30 pm	तकनीकी सत्र 1 एनईपी 2020 बहुविषयक और समग्र शिक्षा के आलोक में भारत में उच्च शिक्षा का भविष्य	<p>वक्ता प्रो. भूषण पटवर्धन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) डॉ. अश्विन फर्नांडिस, मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में QS Quacquarelli Symonds के क्षेत्रीय निर्देशक; QS IGAUGE रेटिंग सिस्टम के सीईओ संदीप शास्त्री, कुलपति, जागरण लेक यूनिवर्सिटी, भोपाल</p>

समय	सत्र	वक्ताओं
5:00 pm- 6:15 pm	तकनीकी सत्र- 2 भारतीय ज्ञान परम्परा, मूल्य और लोकाचार	वक्ता प्रो. शक्ति प्रसाद मिश्र , निवेदिता चेयर, रामकृष्ण मिशन, संस्कृति संस्थान, कोलकाता डॉ. नागेश भंडारी , अध्यक्ष, इंडस विश्वविद्यालय, अहमदाबाद प्रो. टी. वी. कट्टीमनी , वाइस चांसलर, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश सत्र अध्यक्ष प्रो. केएन सिंह , कुलपति, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया
6:30 pm - 7:45 pm	तकनीकी सत्र- 3 उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण	वक्ता श्री रयुही निशि , प्रथम सचिव (विज्ञान और प्रौद्योगिकी), भारत में जापान का दूतावास श्री यदु नाथ पौडेल , काउंसलर (सांस्कृतिक), भारत में नेपाल का दूतावास श्री बलुन्या बार्कर , शिक्षा अताशे, भारत में युगांडा दूतावास सत्र अध्यक्ष प्रो. भीमराय मेत्री , निदेशक, भा.प्र.सं. नागपुर

सत्र योजना

दूसरा दिन - 17th जनवरी 2023

समय	सत्र	वक्ताओं
9:30 am - 10:45 am	तकनीकी सत्र 4 रिसर्च एंड इनोवेशन	वक्ता प्रो. टी.जी. सीताराम , अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद डॉ. वीरेंद्र एस. चौहान , एमेरिटस सोशल साइंटिस्ट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता , कुलपति, डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर सत्र अध्यक्ष प्रो. वी. सुधाकर , प्रोफेसर, ईएफएलयू, हैदराबाद
11:15 am- 12:30 pm	तकनीकी सत्र- 5 नेतृत्व और शासन	वक्ता प्रो. सी राजकुमार , वाइस चांसलर, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत प्रो. योगेश सिंह , कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोफेसर एस वैद्यसुब्रमण्यम , कुलपति, शास्त्र विश्वविद्यालय सत्र अध्यक्ष प्रो. केबी दास , कुलपति, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय
1:30 pm- 2:45 pm	समानांतर सत्र 2 विचारों का आदान प्रदान	समूह 1 सत्र अध्यक्ष डॉ रेणु जैन , वी.सी , देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी), इंदौर

समय	सत्र	वक्ताओं
1:30 pm- 2:45 pm	समानांतर सत्र 2 विचारों का आदान प्रदान	समूह 2 सत्र अध्यक्ष प्रो. भरत शरण सिंह , अध्यक्ष, निजी शुल्क नियामक आयोग
1:30 pm- 2:45 pm	समानांतर सत्र 2 विचारों का आदान प्रदान	समूह 3 सत्र अध्यक्ष प्रो. पंकज अरोड़ा , निर्देशक, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफलांग लर्निंग, दिल्ली विश्वविद्यालय
1:30 pm- 2:45 pm	समानांतर सत्र 2 विचारों का आदान प्रदान	समूह 4 सत्र अध्यक्ष प्रो. रवींद्र कन्हारे , अध्यक्ष, प्रवेश और शुल्क नियामक समिति, मध्य प्रदेश
1:30 pm- 2:45 pm	समानांतर सत्र 2 विचारों का आदान प्रदान	समूह 5 सत्र अध्यक्ष प्रो. चंद्र चारु त्रिपाठी , निदेशक, एनआईटीटीआर, भोपाल

समय	सत्र	वक्ताओं
3:15 pm- 4:15 pm	विशेष व्याख्यान विषय- शिक्षा और राष्ट्रीय विकास	<p>वक्ता: डॉ कृष्ण गोपाल,सह सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ</p> <p>सत्र अध्यक्ष प्रो. के एन सिंह</p>
5 pm- 6 pm	समापन सत्र	<p>मुख्य अतिथि रमेश बैस, झारखंड के माननीय राज्यपाल</p> <p>विशिष्ट अतिथि डॉ मोहन यादव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार सुश्री उषा ठाकुर, माननीय पर्यटन मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार प्रो. टी.जी. सीताराम, अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)</p> <p>गरिमामय उपस्थिति प्रो. नरेंद्र कुमार तनेजा, राष्ट्रीय महासचिव, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान</p>

अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम के वक्ता

डॉ. रेणु जैन

कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी), इंदौर, एमपी

डॉ. रेणु जैन वर्तमान में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर की कुलपति हैं। वह 1985 तक जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में लेक्चरर रहीं तत्पश्चात् 1998 में प्रोफेसर बन गईं। उन्हें गणित में पीएचडी के लिए यूजीसी-जेआरएफ से सम्मानित किया गया, जिसे उन्होंने 1983 में पूरा किया। इंपीरियल कॉलेज, लंदन में एक वर्ष के लिए पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में काम करने के लिए उन्हें नेहरू शताब्दी ब्रिटिश (राष्ट्रमंडल) फैलोशिप से भी सम्मानित भी किया गया।

प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा

राष्ट्रीय अध्यक्ष, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान (वीबीयूएसएस)

प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा वर्तमान में वीबीयूएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं। उनके पास असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में विभिन्न क्षमताओं में 35 से अधिक वर्षों का शिक्षण अनुभव है। वे अपने बी.एससी. और एम.एससी पाठ्यक्रम के दौरान नीड-कम-मेरिट स्कॉलरशिप के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। उन्हें यूजीसी जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीएसआईआर सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिली है। उन्हें 21 से अधिक पीएचडी विद्वानों के पर्यवेक्षण का श्रेय प्राप्त है। उनके 60 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के साथ ही उनकी 4 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है।

प्रो. एम जगदीश कुमार

अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)

वर्तमान में प्रो. ममिडाला जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के 12वें कुलपति के रूप में भी कार्य किया है। वे राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के शासी निकाय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रोफेसर कुमार ने IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है।

डॉ. मोहन यादव

माननीय शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार

डॉ. मोहन यादव जुलाई 2020 को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। डॉ. यादव पीएचडी स्कॉलर हैं तथा उज्जैन दक्षिण सीट से दो बार विधायक चुने जा चुके हैं।

डॉ. सुभाष सरकार

माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार

डॉ. सुभाष सरकार 2019 में पश्चिम बंगाल के बांकुरा से लोकसभा के लिए चुने गए थे, वे वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। डॉ. सरकार ने भाजपा, पश्चिम बंगाल के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है, और अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा, कल्याणी के सदस्य रहे हैं।

प्रो. भरत शरण सिंह

अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय शुल्क नियामक आयोग

प्रो. सिंह मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग (भोपाल) के अध्यक्ष और जाने-माने जीवविज्ञानी हैं।

प्रो. मधुलिका कौशिक

कुलपति, उषा मार्टिन विश्वविद्यालय

प्रो मधुलिका कौशिक रांची स्थित प्रो. कौशिक उषा मार्टिन विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से प्रबंधन में एमबीए और पीएचडी के साथ, वह 30 से अधिक वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिनमें से उनके अकादमिक जीवन का 20 वर्ष ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) प्रणाली को समर्पित है।

प्रो. आर.पी. तिवारी

कुलपति, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी

प्रोफेसर आर.पी. तिवारी वर्तमान में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले, उन्होंने साढ़े पांच साल तक डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, के कुलपति के रूप में कार्य किया। वे यूजीसी के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्हें 2012 में जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, बंगलौर द्वारा भारतीय स्ट्रेटीग्राफी और जीवाश्म विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए एल. रामा राव जन्म शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

प्रो. नवीन सेठ

पूर्व कुलपति, गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय

प्रोफेसर सेठ ने गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया है। वे सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में फार्मसी संकाय के डीन रहे हैं। उन्होंने अहमदाबाद के एलएम कॉलेज ऑफ फार्मसी से फार्माकोग्नॉसी और हर्बल ड्रग्स टेक्नोलॉजी में एम.फार्मा और पीएचडी पूरी की।

प्रो. अमी उपाध्याय

कुलपति, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद

प्रोफेसर उपाध्याय, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद के वर्तमान कुलपति हैं। इस भूमिका में अपने विशिष्ट कार्यकाल के अलावा, उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए योजना और निगरानी बोर्ड और सूरत, गुजरात में स्थित विद्यादीप विश्वविद्यालय के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया है। उनके प्रभावशाली शोध रिकॉर्ड में 19 जर्नल लेख और 11 पुस्तक अध्यायों का प्रकाशन शामिल है। उनके पास सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से एम.फिल और पीएचडी दोनों हैं। प्रो. उपाध्याय को कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग फेलोशिप अवार्ड और 2022 के लिए गुजरात स्टेट लीडरशिप अवार्ड जैसे विभिन्न सम्मानित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

डॉ. गौरीशा जोशी

प्रोफेसर और निदेशक, शिक्षा और सामाजिक अध्ययन केंद्र, बेंगलुरु

डॉ. गौरीशा जोशी, सेंटर फॉर एजुकेशन एंड सोशल स्टडीज, बेंगलुरु में प्रोफेसर और निदेशक हैं। उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति के तकनीकी सचिवालय में मुख्य सलाहकार के रूप में काम किया है। उन्होंने बेंगलुरु स्थित गैर सरकारी संगठन सी-लैप्स के मानद सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है, और वे बेंगलोर विश्वविद्यालय के एमबीए विभाग में विजिटिंग फैकल्टी भी हैं।

प्रो. विभा सिंह चौहान

पूर्व प्राचार्य, किरोड़ीमल कॉलेज, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज की पूर्व प्राचार्या प्रोफेसर विभा सिंह चौहान 34 साल तक जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में लेक्चरर रही हैं। उनके पास अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री (ऑनर्स), अंग्रेजी में मास्टर और एम.फिल और तुलनात्मक साहित्य में पीएचडी है। प्रो. चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.एड, एम.एड और एलएलबी भी किया है। उन्होंने एट फेसेस ऑफ़ रिर्वेज, बियॉन्ड ब्लैक वाटर्स आदि जैसी पुस्तकों का लेखन और अनुवाद भी किया है।

प्रो. रवींद्र कान्हेरे

अध्यक्ष, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति, मध्यप्रदेश

प्रोफेसर रवींद्र कान्हेरे मध्य प्रदेश प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के अध्यक्ष हैं। वे भोज विश्वविद्यालय, भोपाल के पूर्व कुलपति और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय /इग्नू (IGNOU), नई दिल्ली के पूर्व कुलपति रह चुके हैं।

प्रो. बी.वी.आर. रेड्डी

निदेशक, एनआईटी कुरुक्षेत्र

प्रोफेसर बी.वी.आर. रेड्डी वर्तमान में एनआईटी कुरुक्षेत्र में निदेशक हैं। प्रोफेसर बी.वी.आर. रेड्डी ने पिछले 22 वर्षों से यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, GGSIPU, नई दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में काम किया है। उन्होंने GGSIP के केंद्रीकृत कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। वह IETE, IE में फेलो और अन्य पेशेवर निकायों जैसे IEEE, CSI और SEMCEI के सदस्य भी हैं। प्रो. रेड्डी राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के अनुरूप शैक्षिक सुधारों और मूल्य-आधारित शिक्षा में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, और एनआईटी कुरुक्षेत्र में एनईपी 2020 को लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

प्रो. पंकज मित्तल

महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ

प्रोफेसर पंकज मित्तल भारतीय विश्वविद्यालय संघ के महासचिव हैं। नीति नियोजन में उच्च शिक्षा में तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, वे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की मुख्य आयुक्त (गाइड्स) भी हैं। प्रो. मित्तल ने भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर के पहले नियमित कुलपति के रूप में भी काम किया है, और अभिनव प्रथाओं और सुधारों की एक श्रृंखला पेश की है।

प्रो. डी.पी. गोयल

निदेशक, आईआईएम शिलांग

प्रोफेसर डी.पी. गोयल आईआईएम शिलांग में निदेशक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित शिक्षाविद और शोधकर्ता हैं। उन्होंने एक दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और उन्हें शिक्षण और अनुसंधान में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने एमडीआई गुड़गांव, आईएमटी गाजियाबाद और थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला जैसे भारत के बेहतरीन संस्थानों में विभिन्न नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाई हैं। वह आरहस यूनिवर्सिटी, डेनमार्क में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। प्रो. गोयल राष्ट्रीय निकायों की विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे हैं और विभिन्न बिजनेस स्कूलों और विश्वविद्यालयों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी हैं।

प्रो. नागेश्वर राव

कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

प्रोफेसर राव इग्नू के कुलपति हैं तथा उन्होंने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (यूओयू), हल्द्वानी और अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य किया है। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डी.फिल और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, कोलकाता से आईसीडब्ल्यूए प्राप्त किया है। वह भारतीय लेखा संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं तथा उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने लगभग आठ पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें 'भारत में सार्वजनिक उद्यमों का प्रशासन' और 'संचार कौशल' शामिल हैं।

प्रो. बिनोद कुमार कनौजिया

निदेशक, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर

प्रोफेसर कनौजिया मुख्य रूप से कम्प्यूटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और बायोमेडिकल टेलीमेट्री के शोधकार्य में सम्मिलित हैं। इसके साथ ही, उन्होंने कई पत्र-पत्रिकाओं में विभिन्न शोधपत्र प्रकाशित किए हैं तथा विभिन्न डॉक्टरेट विद्वानों का पर्यवेक्षण किया है। प्रोफेसर बिनोद कुमार कनौजिया ने केएनआईटी (KNIT), सुल्तानपुर, यूपी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक पूरा किया है। उसके बाद, उन्होंने आईआईटी बीएचयू, वाराणसी, भारत से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में M.Tech और पीएचडी की पढ़ाई की।

श्री बलुन्या बार्कर

शिक्षा संलग्नक, भारत में युगांडा दूतावास

श्री बार्कर भारत में युगांडा दूतावास से शिक्षा संलग्नक हैं।

प्रो. भूषण पटवर्धन

अध्यक्ष, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक)

प्रोफेसर भूषण पटवर्धन नैक के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वह शीर्ष-उद्धृत बायोमैडिकल वैज्ञानिकों में से एक हैं, जो नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया के फेलो हैं। उन्होंने यूजीसी के उपाध्यक्ष और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारत सरकार के अतिरिक्त प्रभार के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्थागत प्रशासन में 40 से अधिक वर्षों के कार्य अनुभव के साथ, उन्होंने कई विश्वविद्यालयों के बोर्डों में काम किया है। वह आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सीएसआईआर, डीएसटी, आदि की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समितियों के सदस्य हैं।

डॉ. अश्विन फर्नांडिस

मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय निदेशक, QS Quacquarelli सायमंड्स, सीईओ, क्यूएस आईगेज रेटिंग सिस्टम

वर्तमान में, डॉ. फर्नांडिस क्यूएस आई-गेज के सीईओ हैं तथा क्षेत्रीय निदेशक (मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया) भी हैं। उन्होंने QS से जुड़ी कई परियोजनाओं पर भी काम किया है। डॉ अश्विन फर्नांडिस ने गोवा विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद, उन्होंने Ulyanovsk State University से एमबीए और एमिटी विश्वविद्यालय से पीएचडी की पढ़ाई पूरी की।

प्रो. संदीप शास्त्री

कुलपति, जागरण लेक विश्वविद्यालय, भोपाल

प्रोफेसर संदीप शास्त्री जागरण लेक यूनिवर्सिटी भोपाल के कुलपति हैं। उन्होंने प्रो वाइस चांसलर, जैन यूनिवर्सिटी, बेंगलूर और सेंटर फॉर रिसर्च इन सोशल साइंसेज एंड लैंग्वेज (CERSSE) के निर्देशक के रूप में कार्य किया है। वह पैसिफिक रिम देशों में यूएनडीपी की राजनीतिक पार्टी सुधार परियोजना, नेपाल में अपनी शासन परियोजना पर विश्व बैंक आदि के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सलाहकार हैं। उनके पास चुनाव अध्ययन, संघवाद, शिक्षण में नवाचार आदि विषयों में चार दशकों से अधिक का शिक्षण और अनुसंधान आदि का अनुभव है और एक ही क्षेत्र में कई अंतरराष्ट्रीय शोध निकायों से जुड़े हुए हैं। संपादित पुस्तकों में उन्हें 13 पुस्तकों और 51 से अधिक अध्यायों का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने शोध पत्रिकाओं में 90 से अधिक लेखों और समाचार पत्रों में लगभग 350 OpEd का भी योगदान दिया है।

प्रो. शक्ति प्रसाद मिश्र

निवेदिता चैयर, रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, कोलकाता

प्रोफेसर शक्ति प्रसाद मिश्रा एक उच्च सम्मानित शिक्षाविद् हैं तथा वर्तमान में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर में प्रतिष्ठित निवेदिता चैयर पर हैं।

प्रो. टी.वी कट्टीमनी

आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, कुलपति

प्रोफेसर टी.वी. कट्टीमनी साहित्य और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। एक आलोचक और अनुवादक के रूप में अपने योगदान के लिए विख्यात, उन्होंने हिंदी से कन्नड़, कन्नड़ से हिंदी, गुजराती से कन्नड़ और अंग्रेजी से हिंदी में विभिन्न साहित्यिक और गैर-साहित्यिक कार्यों का अनुवाद किया है। CTUAP के कुलपति के रूप में कार्य करने से पहले, उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्य प्रदेश) के कुलपति के रूप में भी कार्य किया। उन्हें कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार: उच्च शिक्षा के लिए उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए कर्नाटक में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

डॉ. नागेश भंडारी

अध्यक्ष, सिंधु विश्वविद्यालय, अहमदाबाद

डॉ नागेश भंडारी सिंधु विश्वविद्यालय, अहमदाबाद के अध्यक्ष हैं। वह विश्व स्तर पर प्रशंसित स्पाइन सेंटर 'रिहैबिलिटेशन क्रानकेनहॉस', जर्मनी से स्पाइन सर्जरी में विशेषज्ञता वाले पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने नवीन उपकरण प्रणाली विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अंततः अपने चुने हुए क्षेत्र में लागत प्रभावी उपचार प्रक्रियाओं को जोड़ा है।

प्रो. केएन सिंह

कुलपति, दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गया

दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएसबी), गया के तीसरे कुलपति प्रो. कामेश्वर नाथ सिंह के पास 32 वर्षों का समृद्ध पेशेवर अनुभव है और उन्होंने कई पीएचडी छात्रों का पर्यवेक्षण किया है। सीयूएसबी में शामिल होने से पहले, प्रो. सिंह उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के कुलपति और प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज थे।

श्री रयुही निशि

प्रथम सचिव (विज्ञान और प्रौद्योगिकी), भारत में जापान के दूतावास

श्री निशि भारत में जापान के दूतावास से जुड़े प्रथम विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव हैं।

श्री यदु नाथ पौडेल

काउंसलर (सांस्कृतिक), भारत में नेपाल का दूतावास

श्री यदु नाथ पौडेल लंबे समय से भारत-नेपाल मैत्री और संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। यदु नाथ नेपाल के 3 जिलों में मुख्य जिला अधिकारी भी थे तथा कई विभागों में विविध भूमिकाएँ निभाते हुए पर्याप्त अवधि के लिए सरकारी सेवा से भी जुड़े रहे हैं।

प्रो. टी जी सीताराम

अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)

प्रोफेसर सीताराम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वह 3 साल 5 महिनें (जुलाई 2019 से दिसंबर 2022) तक के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, असम के निदेशक रहे। उन्होंने अपनी पीएचडी के तुरंत बाद वाटरलू विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में कार्य किया तथा 1992-94 में टेक्सास विश्वविद्यालय, ऑस्टिन, टेक्सास (यूएसए) में काम किया। वह सीआईटी, कोकराझार में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष और उत्तर पूर्व क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

डॉ. वीरेंद्र एस. चौहान

एमेरिटस सोशल साइंटिस्ट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी (आईसीजीईबी)

डॉ चौहान एमेरिटस सोशल साइंटिस्ट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी (आईसीजीईबी) में एक एमेरिटस सोशल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज, डीयू और आईआईटी कानपुर सहित विभिन्न संस्थानों में काम किया है। उन्होंने 2017-18 में यूजीसी के अध्यक्ष, आईसीजीईबी नई दिल्ली के निदेशक के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने जे.सी. बोस फेलो, डीएसटी- भारत सरकार और ईसी अध्यक्ष, नैक के रूप में भी काम किया है। वह वैज्ञानिक और मानव संसाधन विकास के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित हैं।

प्रो. नीलिमा गुप्ता

कुलपति, डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता डॉ. हरीशसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर की कुलपति हैं। उन्होंने महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी में योजना और निगरानी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया है। वह गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में यूजीसी नामांकित भी रह चुकी हैं। उन्होंने I-NSA, डीएसटी और सीएसआईआर में शोध वैज्ञानिक के रूप में भी काम किया है तथा 1.8 करोड़ से अधिक राशि तक की कई शोध परियोजनाओं में कार्य किया है।

प्रो. एसके गाखर

पूर्व कुलपति, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, रेवाड़ी

प्रोफेसर सुरेंद्र गाखड़ इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, रेवाड़ी के कुलपति के पद से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने 2019 में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी के संस्थापक कुलपति और श्री श्री विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी काम किया है। उन्होंने यूसी इरविन में बायोटेक्नोलॉजी ओवरसीज एसोसिएट के रूप में भी काम किया है। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से विकासात्मक जीव विज्ञान में पीएचडी पूरी की है।

प्रो. वी. सुधाकर

प्रोफेसर, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (EFLU), हैदराबाद

प्रोफेसर वी. सुधाकर EFLU, हैदराबाद में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने कई परियोजनाओं और लेखों पर काम किया है तथा नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप, ICPR फेलोशिप, बेस्ट सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड (IARE-2020), आदि जैसे कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

प्रो. सी राज कुमार

कुलपति, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत

प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार, रोड्स स्कॉलर, भारत में ओ.पी. जिंदल ग्लोबल (इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) (जेजीयू) के संस्थापक कुलपति हैं। प्रोफेसर कुमार एक कुशल कानूनी विद्वान हैं, जो मानवाधिकार और विकास, तुलनात्मक संवैधानिक कानून, आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा आदि में काम करते हैं। प्रोफेसर कुमार के पास ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हांगकांग विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और लोयोला कॉलेज से शैक्षणिक योग्यता है। उन्होंने हांगकांग के सिटी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ में एक संकाय सदस्य के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने कई वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया।

प्रो. योगेश सिंह

कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रोफेसर योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (तत्कालीन नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सहित प्रमुख प्रतिष्ठित संस्थानों में कुलपति के रूप में उनका एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड और अनुभव है। प्रो. सिंह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) के एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र (IUC) सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (इनफ्लिबनेट) केंद्र, गांधीनगर के शासी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं।

प्रो. एस वैद्यसुब्रमण्यम

कुलपति, शास्त्र विश्वविद्यालय

प्रोफेसर वैद्यसुब्रमण्यम शास्त्र विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यरत रहे हैं। उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन लिमिटेड, मद्रास में क्षेत्रीय बिक्री कार्यकारी के रूप में भी काम किया है। प्रो. वैद्यसुब्रमण्यम ने सीमेंस लिमिटेड में विभिन्न कार्यकारी परियोजनाओं पर भी काम किया है, जहाँ उन्होंने 'एसएपी को लागू करने की अनूठी मूल्य रणनीति' पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की।

प्रो. बी.आर. शर्मा

कुलपति, श्री श्री विश्वविद्यालय

प्रोफेसर शर्मा श्री श्री विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। वह 'योग शिक्षा और अनुसंधान' में 38 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले शिक्षाविद हैं। वह अभी भी WHO की वैश्विक 'बी हेल्दी, बी मोबाइल' (BHBM) पहल के हिस्से के रूप में "एमयोग एप्लिकेशन" विकास के लिए सहकर्मि समीक्षक योग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वह वर्तमान में एक प्रसिद्ध योग पत्रिका, योग मीमांसा के प्रबंध संपादक और विभिन्न समितियों के अध्यक्ष हैं। उनको 13 पुस्तकें और 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित करने की उपलब्धि प्राप्त हैं।

प्रो. आलोक कुमार चक्रवाल

कुलपति, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर

प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्तमान कुलपति हैं और सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में वाणिज्य और व्यवसाय प्रशासन के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं।

प्रो. गोपाल पाठक

कुलपति, सरला बिड़ला विश्वविद्यालय, रांची

प्रोफेसर पाठक एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं तथा वर्तमान में रांची, झारखंड में सरला बिड़ला विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। वह झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। उन्होंने बीआईटी मेशरा में डीन और सिविल विभाग के प्रमुख के रूप में प्रशासनिक पदों को सुशोभित किया है।

प्रो. पंकज अरोड़ा

निदेशक, आजीवन शिक्षण संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रोफेसर पंकज अरोड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफलॉन्ग लर्निंग, दिल्ली विश्वविद्यालय के निदेशक हैं। वह 2015 में CIE में शिक्षा के प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए और 2019 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के डीन बने। प्रो. अरोड़ा शिकागो, यूएसए में प्रकाशित होने वाले द जर्नल ऑफ इंटरनेशनल टीचर एजुकेशन एंड टीचिंग के सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। उन्होंने चार पुस्तकें, 15 लेख अनुक्रमित / सहकर्मी-समीक्षित पत्रिकाओं में और 50 से अधिक सम्मेलन प्रस्तुतियों को प्रकाशित किया। उन्होंने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से पीएचडी की है।

प्रो. आलोक कुमार राय

कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय

प्रोफेसर आलोक कुमार राय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रबंधन के प्रोफेसर हैं तथा वर्तमान में अपने दूसरे कार्यकाल में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। वह आगरा में डॉ. बी.आर.अंबेडकर विश्वविद्यालय, वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय तथा लखनऊ में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति (अतिरिक्त प्रभार) रह चुके हैं।

प्रो. अखिलेश कुमार पाण्डेय

कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय

प्रोफेसर अखिलेश कुमार पाण्डेय विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के सेवारत कुलपति हैं। इससे पूर्व वे जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं।

प्रो. पी.एस. शुक्ला

वाइस चांसलर, नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग

प्रोफेसर प्रभा शंकर शुक्ला उत्तर-पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय (एनईएचयू) के कुलपति हैं। प्रोफेसर शुक्ल पूर्व में जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। वे 29 वर्षों से अधिक से अध्यापन और अनुसंधान कर रहे हैं तथा उन्होंने 42 शोध पत्र, 50 लेख, 17 पुस्तक अध्याय और 5 पुस्तकें और नियमावली प्रकाशित की है।

प्रो. गंगा प्रसाद प्रसेन

कुलपति, त्रिपुरा विश्वविद्यालय

प्रोफेसर गंगा प्रसाद 2020 से त्रिपुरा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। पहले उन्होंने मणिपुर विश्वविद्यालय के डीन के रूप में कार्य किया। उन्होंने मणिपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय, इंपाल में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के डीन और वाणिज्य के प्रोफेसर के रूप में काम किया है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी से एमकॉम और पीएचडी की पढ़ाई पूरी की तथा उनके पास स्नातकोत्तर स्तर पर 31 साल का शिक्षण व शोध का अनुभव है। आपके पास मणिपुर विश्वविद्यालय, इंपाल में प्रोफेसर के रूप में 14 साल का अनुभव है।

प्रो. के बी दास

कुलपति, झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

प्रोफेसर क्षितिज भूषण दास वर्तमान में झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने झारखंड के केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति की भूमिका निभाने से पहले इग्नू, नई दिल्ली और केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ओडिशा के प्रो-वाइस चांसलर के रूप में कार्य किया। वह एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च (ICSSR), नई दिल्ली के नेशनल फेलो हैं। वह ICSSR के प्रख्यात सामाजिक वैज्ञानिकों के कॉलेजियम के सदस्य और ERC-ICSSR की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में एक प्रतिष्ठित पद पर हैं। वह नवकृष्ण चौधरी सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, भुवनेश्वर की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी हैं। उन्होंने पूर्व प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग के प्रमुख और उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में वाणिज्य और प्रबंधन संकाय के डीन के रूप में भी कार्य किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उसी विश्वविद्यालय के कॉलेज विकास परिषद में रजिस्ट्रार और निदेशक पदों पर कार्य किया है।

प्रो. (डॉ.) विनीता के. सलूजा

कुलपति, मंगलायतन विश्वविद्यालय

प्रोफेसर सलूजा जनवरी 2021 से मंगलायतन विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। इस पद को संभालने से पहले, वह एक सहायक प्रोफेसर थीं और फिर माता गुजरी महिला महाविद्यालय, मरहाताल, जबलपुर में संस्थापक प्राचार्य थीं। अपने पेशेवर करियर में, वह IIT, जबलपुर में विजिटिंग प्रोफेसर और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में लेक्चरर भी रही हैं।

प्रो. राघवेंद्र पी. तिवारी

वाइस चांसलर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, बटिंडा

प्रोफेसर राघवेंद्र पी. तिवारी पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बटिंडा के कुलपति हैं। उन्होंने डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर म.प्र. में कुलपति के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने मिजोरम विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग में प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है।

डॉ. कृष्ण गोपाल

सह सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

डॉ. कृष्ण गोपाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयुक्त महासचिव हैं। वह उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले हैं; यूपी के विभिन्न स्थानों में संघ का कार्य देखने के बाद, कृष्ण गोपाल आरएसएस के कार्य विस्तार के लिए उत्तर-पूर्व चले गए। उन्होंने उत्तर पूर्व में नौ वर्षों तक क्षेत्रीय प्रचारक (क्षेत्रीय संगठक) के रूप में कार्य किया। इसके बाद 2012 में उन्हें संयुक्त महासचिव नियुक्त किया गया। डॉ. गोपाल ने आगरा विश्वविद्यालय से पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर करने के बाद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।

प्रो. के. एन. सिंह

कुलपति, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया

प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह केंद्रीय दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय (CUSB), गया के तीसरे कुलपति हैं। सीयूएसबी में शामिल होने से पहले, प्रो. सिंह उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज और प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज के कुलपति रह चुके हैं।

श्री रमेश बैस

झारखंड के माननीय राज्यपाल

श्री रमेश बैस झारखण्ड के राज्यपाल हैं। उन्होंने जुलाई 2019 से जुलाई 2021 तक त्रिपुरा के 18वें राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। वह सात बार लोकसभा के लिए चुने गए और 2019 तक इस पद पर रहे। उन्होंने 1978 में रायपुर में नगर निगम में पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। उन्होंने 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्य करने सहित कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर कार्य किया।

शुश्री उषा ठाकुर

माननीय पर्यटन मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार

शुश्री उषा ठाकुर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास इतिहास में मास्टर डिग्री है और कविता और भारतीय साहित्य में उनकी बहुत रुचि है।

प्रो. नरेंद्र कुमार तनेजा

राष्ट्रीय महासचिव, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान (वीबीयूएसएस)

प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा वीबीयूएसएस के राष्ट्रीय महासचिव और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली और भारतीय आर्थिक संघ के वार्षिक सदस्य हैं। वह 30 से अधिक वर्षों के शिक्षण और 25 वर्षों से अधिक शोध अनुभव के साथ एक उच्च अनुभवी शिक्षक और शोधकर्ता हैं। उन्होंने कई व्याख्यान दिए हैं और विभिन्न राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में शोधपत्र प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में दो राष्ट्रीय सेमिनारों का निर्देशन किया।

प्रो. एस. पी. बंसल,

कुलपति, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला

प्रोफेसर (डॉ.) सत प्रकाश बंसल ने 28 जुलाई 2021 को हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला में कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस प्रतिष्ठित कार्यभार के अलावा, वे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के कुलपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। वह हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर के पूर्व कुलपति रह चुके हैं; इंदिरा गांधी राज्य विश्वविद्यालय, रेवाड़ी; भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत और महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश के संस्थापक कुलपति रह चुके हैं।

प्रो. सरोज शर्मा

अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), नोएडा

प्रोफेसर शर्मा एनआईओएस, नोएडा के अध्यक्ष हैं। उनके पास एमएससी.(वनस्पति विज्ञान), समाजशास्त्र में एम.ए., एम.एड., एमबीए, एम.फिल, और शिक्षा में पीएचडी सहित कई शैक्षणिक डिग्रियां हैं। वे कई शैक्षिक संघों के सक्रिय सदस्य हैं तथा युनीसेफ, यूनेस्को, एनसीईआरटी और आईसीएसएसआर जैसे संगठनों के लिए विभिन्न परियोजनाओं में भाग लेती हैं।

प्रो. प्रशांत गुप्ता

प्रोफेसर, आईआईएम नागपुर

प्रोफेसर प्रशांत गुप्ता वित्त में विशेषज्ञता के साथ भा.प्र.सं. नागपुर में प्रोफेसर हैं। वे प्रशासनिक पदों पर कार्य कर चुके हैं तथा आइवी बिजनेस स्कूल, कनाडा में एक प्रशिक्षित संकाय सदस्य थे। वह भारतीय मानक ब्यूरो में लेखा मानक बोर्ड (ASB) और 'सस्टेनेबल फाइनेंस' पर समिति सहित प्रतिष्ठित समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। प्रोफेसर प्रशांत गुप्ता ने बी.कॉम, एलएलबी, एमएमएस (फाइनेंस) और पीएचडी (फाइनेंस) की पढ़ाई की है। उद्योग और शिक्षाविदों में लगभग 25 वर्षों के अनुभव के साथ, उन्होंने लगभग 40 कंपनियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

प्रो. अरुण भटनागर, आईआरएस

महानिदेशक, आईआईएसटी-आईआईपी-आईआईएमआर

प्रोफेसर अरुण भटनागर इंदौर शैक्षिक संस्थानों के समूह के महानिदेशक हैं। उन्होंने भारतीय वित्त मंत्रालय के साथ प्रधान आयकर आयुक्त के रूप में भी काम किया। वह राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (आईआरएस प्रशिक्षुओं और वरिष्ठ नौकरशाहों को प्रशिक्षण देने के लिए शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान) के महानिदेशक भी रह चुके हैं। वह 1983 बैच के वरिष्ठ नौकरशाह हैं, जिनके पास 45 वर्षों का समग्र अनुभव है। उन्होंने 1975 में अर्थशास्त्र में सहायक प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों और सरकारों के साथ-साथ संस्थान के प्रबंधित संकाय और बुनियादी ढांचे के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों का नेतृत्व और समन्वय किया है। उन्होंने आयकर आयुक्त के रूप में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई), बैंगलोर का नेतृत्व किया था।

प्रो. चंद्र चारु त्रिपाठी

निदेशक, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल (NITTTR), भोपाल

प्रोफेसर सी.सी. त्रिपाठी प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। प्रो त्रिपाठी, NITTTR, भोपाल के निदेशक और एक अनुभवी प्रोफेसर व प्रशासक हैं। वह यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (UIET) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व निदेशक हैं, जो 1600 से अधिक छात्रों, 90 से अधिक फैकल्टी और 100 से अधिक स्टाफ सदस्यों के साथ निदेशक के रूप में एक स्वायत्त इंजीनियरिंग संस्थान है।

सत्र 1: उद्घाटन

वक्ता

- डॉ. सुभाष सरकार, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार
- डॉ. मोहन यादव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार
- प्रो. एम. जगदीश कुमार, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
- प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान (वीबीयूएसएस)
- डॉ. रेणु जैन, कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी), इंदौर
- प्रो. भरत शरण सिंह, अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय शुल्क नियामक आयोग



संक्षेप

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सभागृह में विद्या भारती व देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 16 जनवरी 2023 को यह संस्थागत नेतृत्व समागम का आयोजन किया गया। सत्र में कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। उद्घाटन सत्र शिक्षा के महत्व और भारत में जमीनी स्तर पर शिक्षा के प्रचार में विभिन्न सरकारी संस्थानों की भूमिका पर केंद्रित था। इस सत्र में नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत शैक्षिक संस्थानों के बहु-विषयक और समग्र विकास की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठों के माध्यम से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की प्रासंगिकता और अनुसंधान बुनियादी ढांचे के निर्माण पर चर्चा भी की गई। प्रख्यात वक्ताओं ने प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक नीतियों के विकास और शिक्षा प्रणाली की संरचना पर भी प्रकाश डाला।

राज्य शिक्षा मंत्री डॉ सुभाष सरकार एवं उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश डॉ मोहन यादव इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ कैलाश चंद्र शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अध्यक्ष, प्रोफेसर एम् जगदीश कुमार व प्राइवेट यूनिवर्सिटी फी रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष प्रो. भरत शरण सिंह और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. रेणु जैन ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

उद्घाटन सत्र की शुरुआत विश्वविद्यालय के 'कुल गीत' के साथ हुई, जिसने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लिए गर्व की भावना को प्रतिध्वनित किया। दीप प्रज्ज्वलन के बाद दीप मंत्र और सरस्वती वंदना गाई गयी। डॉ. रेणु जैन ने सभी सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन किया और शिखर सम्मेलन में सभी का स्वागत किया। सम्मान के बाद उन्होंने सभा को संबोधित किया।

डॉ रेणु जैन

कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय

डॉ रेणु जैन ने सभी अतिथियों का स्वागत कर अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने 21वीं सदी में भारत के लिए एक मजबूत नींव रखने में एनईपी 2020 के महत्व पर जोर दिया तथा भारत को आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनने में इसकी क्षमता पर जोर दिया। जिस तरह से डीएवी ने शिक्षा के साथ मूल मूल्यों पर ध्यान केंद्रित किया, उसे A+ नैक रेटिंग प्राप्त करने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि इस अमृत काल में भारत शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनने की क्षमता रखता है तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जैसी नीतियों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि, अब आकाश भी भारत के लिए सीमा नहीं है, क्योंकि काले बादल छंट गए हैं। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है जिसमें हमें G20 की अध्यक्षता मिलना एक सफल कदम है। इस समागम की सफल मंगलकामना करते हुए डॉ रेणु जैन जी ने अपने उद्बोधन को विराम दिया।



डॉ रेणु जैन



डॉ कैलाश चंद्र शर्मा

डॉ कैलाश चंद्र शर्मा

राष्ट्रीय अध्यक्ष, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान

डॉ कैलाश चंद्र शर्मा ने शिखर सम्मेलन में सभी का स्वागत करते हुए अपने उद्बोधन की शुरुआत की तथा एनएसआईएल के आयोजन के लिए विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान और डीएवी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने डीएवी को A+ नैक ग्रेड मिलने पर बधाई दी। उन्होंने 35 लाख से अधिक छात्रों और 3 लाख से अधिक शिक्षकों के साथ 12,000 से अधिक केंद्रों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए वीबीयूएसएस की भूमिका पर जोर दिया। उनकी राय में, संस्थानों को शिक्षा के माध्यम से छात्रों के भीतर राष्ट्रवादी भावना जगाने की आवश्यकता है। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली पर ब्रिटिश राज के स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डाला, जिसके दुष्परिणाम दीर्घकाल में देखे गए। उन्होंने जिन तीन चुनौतियों का उल्लेख किया वे इस प्रकार थीं (i) दिशा की कमी, (ii) निवेश का निम्न स्तर और (iii) जवाबदेही न तय होना ।

अब सर्वोच्च अधिकारी जवाबदेही लेकर शिक्षा नीति को दिशा दे रहे हैं। उन्होंने एनईपी 2020 की विशेषताओं के बारे में भी बताया जिसमें बहुविषयक, समग्र शिक्षा और भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) शामिल हैं। उनका मानना है कि, हितधारकों के बीच इच्छा पैदा करने की आवश्यकता है, और यह उनका नेटवर्क और सहयोग है जो सिस्टम को मजबूत करने में मदद करेगा।

प्रो. एम. जगदीश कुमार

अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

प्रोफेसर जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माननीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने सामाजिक-शैक्षणिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण घटक के रूप में छात्रों की बढ़ती भूमिका पर जोर देकर अपने सम्बोधन की शुरुआत की। उनका मानना है कि छात्र शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक की तरह कार्य करते हैं। उन्होंने G20 अध्यक्षता हासिल करने में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रकाश डाला, जिसे उन्होंने भारत के इतिहास में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर माना। प्रो. कुमार ने प्रमुख आंकड़े पेश करते हुए G20 के महत्व पर जोर दिया, और बताया कि इसमें वैश्विक आबादी का 60%, विश्व व्यापार का 74%, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 85% और पेटेंट का 70% शामिल है। उन्होंने इस पर भी ध्यान केंद्रित किया कि 8-9 वर्षों की अवधि में अवसंरचनात्मक सुधार हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत भू-राजनीतिक गड़बड़ी, आपूर्ति श्रृंखला में चूक, आर्थिक बैकलॉग और पर्यावरणीय मुद्दों जैसी कई समस्याओं से ग्रसित रहा है। हालाँकि, इन कमियों को दूर करने के लिए, उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि भारत केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से पीछे तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बन गया। इसके अलावा, कुल स्टार्टअप्स में से 47% महिलाओं द्वारा स्थापित किए गए हैं। अगले तीन से पांच वर्षों में स्टार्टअप्स का भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 4-5% योगदान करने का अनुमान है।



अपने विचारों को व्यक्त करते हुए, उन्होंने एनईपी 2020 के महत्व को समझाया। नीति का मुख्य जोर लोगों के लिए विकल्पों के विस्तार के साथ-साथ छात्रों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने पर है, इस प्रकार यह संस्था-केंद्रित नहीं, छात्र-केंद्रित है। उन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम यूनिवर्सिटी कनेक्ट की स्थापना का भी उल्लेख किया और कामकाजी पेशेवरों के साथ-साथ संस्थानों के आधारभूत संरचना, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की आवश्यकता पर अपनी चिंता व्यक्त की। प्रो. जगदीश ने कहा कि कौशल विकास पर नीति के जोर से शिक्षा के प्रति हमारे दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता होगी। अवसंरचना विकास के संबंध में, उन्होंने अनुसंधान अवसंरचना, विशेष रूप से महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि कई संस्थान अपने शैक्षिक प्रतिष्ठानों में एनईपी के कार्यान्वयन के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में धन की कमी का उल्लेख करती हैं। उन्होंने शैक्षणिक क्रेडिट बैंक की अवधारणा को स्पष्ट किया और उसकी क्षमता को उजागर करते हुए बताया कि इससे छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों को क्रेडिट पॉइंट अर्जित करने में सहायता मिलती है, जो अंततः समग्र विकास को सुविधाजनक बनाता है और छात्रों को UGC मान्यता प्राप्त कॉलेज और विश्वविद्यालयों से उनकी इच्छित माइनर और मेजर डिग्री हासिल करने में सक्षम बनाता है।

वक्ता ने शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए एक बहुआयामी और समग्र दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। समग्र शिक्षा की व्याख्या करने के लिए उन्होंने कहा कि यह एक चौथाई शिक्षक के मार्गदर्शन, एक चौथाई सहकर्मी शिक्षा, एक चौथाई अनुभव और एक चौथाई स्वाध्याय का संयोजन है। तंत्र में सुधार के लिए, उन्होंने शिक्षण कर्मचारियों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया, इस प्रकार उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम विकसित करने के प्रस्ताव की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने एक अच्छे शिक्षार्थी के गुणों का भी वर्णन किया जिसमें अध्ययन करना, याद रखना और आलोचनात्मक सोच शामिल है। यदि किसी व्यक्ति में ये तीन गुण हों तो वह एक अच्छा शिक्षार्थी हो सकता है। प्रो. जगदीश ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क स्कीम (NCRF) के बारे में भी बताया, जो अपने आप में पहला व अनोखा फ्रेमवर्क है, जिसका उद्देश्य भारत में शैक्षणिक शिक्षा और कौशल को एकीकृत करना है।

एनसीआरएफ, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए लागू एक एकीकृत क्रेडिट संचय और हस्तांतरण ढांचा है। उन्होंने छात्रों के लिए बहु-प्रवेश व बहु-निकास प्रणाली पर भी जोर दिया, जो उन्हें अपने पाठ्यक्रम को छोड़ने और इसे बाद के चरण में फिर से शुरू करने की अनुमति देता है। उन्होंने छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों तक पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया, साथ ही विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में कैंपस स्थापित करने के संभावित लाभों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के विकास से भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों और यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के बीच अधिक सहयोग की सुविधा मिलेगी।

प्रोफेसर ने सभा को माननीय पीएम मोदी द्वारा संबोधित पंच प्राण के बारे में भी बताया जो इस प्रकार हैं:

- बढ़ते हुए भारत की निर्माण शक्ति और निर्धारित दृढ़ता के साथ बढ़ें।
- गुलामी के किसी भी निशानी से छुटकारा पाएं।
- भारत के गौरवशाली इतिहास पर गर्व करें।
- एकता की शक्ति।
- नागरिकों के कर्तव्य, जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कर्तव्य।

अपने ज्ञानपूर्ण सत्र को समाप्त करते हुए, उन्होंने भारत के सभी विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा और जीवन कौशलों को छात्रों और अभ्यासकर्ताओं में बढ़ावा देने के लिए यूजीसी की भूमिका पर जोर दिया।

डॉ मोहन यादव

माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार

डॉ मोहन यादव जी ने अपने संबोधन की शुरुआत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मध्यप्रदेश के प्रयासों की सराहना करते हुए की। उन्होंने कहा कि ऐसे कठिन समय में, जब देश पूरी तरह से लॉकडाउन में था, और सभी शैक्षणिक संस्थान बंद थे, मध्य प्रदेश (एमपी) शिक्षा सरकार ने 23 लोगों की एक एक्शन टास्क फोर्स बनाई। टास्क फोर्स की सबसे बड़ी चिंता यह तय करना था कि परीक्षा आयोजित की जाए या अपने सभी छात्रों को सामान्य पदोन्नति दी जाए। फिर तय हुआ कि जनरल प्रमोशन देने की बजाय बच्चों की ऑनलाइन परीक्षा कराई जाए और एनईपी 2020 को पूरी ताकत से लागू किया जाए। माननीय मंत्री को उद्धृत करते हुए, “मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मध्य प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों ने आगे बढ़कर इस निर्णय में सरकार का समर्थन किया। और मध्य प्रदेश उन पहले राज्यों में से एक था जिसने पहली लहर के दौरान बोर्ड के छात्रों और स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का विचार प्रस्तावित किया और अपनी पहल में सफल भी रहा।” उन्होंने आगे कहा कि एम.पी. शिक्षा प्रणाली को कोविड के समय शिक्षा से संबंधित विभिन्न संस्थाओं के साथ एक छत की आवश्यकता है, ताकि वे एक दूसरे के ज्ञान का उपयोग करके शिक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना कर सकें।



डॉ मोहन यादव

डॉ. मोहन यादव ने विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान (वीबीयूएसएस) का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्या भारती जिस तरह शांतिपूर्वक शिक्षा नीति को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए नए आयोजन कर रही है, वह अति सराहनीय है। उन्होंने इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले और एनईपी 2020 को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों और उनके गणमान्य लोगों को धन्यवाद देते हुए अपने संबोधन का समापन किया और कहा, "आज के शिखर सम्मेलन में, हम सभी चर्चाओं और विचार-विमर्श के साथ आगे बढ़ेंगे जो विचारों और रणनीतियों के "अमृत मंथन" में परिणामित होगा"।

डॉ सुभाष सरकार

माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार

डॉ सरकार ने अपने सत्र की शुरुआत महारानी अहिल्याभाई होल्कर के संक्षिप्त परिचय के साथ की, जिन्होंने शैक्षिक महत्व के विभिन्न स्थलों को पुनर्जीवित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वह धार्मिक स्थलों की एक महान संरक्षिका थीं। उन्होंने मन की शक्ति में अपने प्रमुख विश्वास पर जोर दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि जब इस शक्ति को सही दिशा में लागू किया जाता है तो हर कोई अपने जीवन को उन्नत कर सकता है क्योंकि यह मानव के पास सबसे मजबूत और सबसे उपयोगी शक्तियों में से एक है। यह व्यवहार और दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है और क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने स्वामी विवेकानंद को उद्धृत किया और कहा, "शिक्षा बस एक बहुत सी तथ्यों से भरी हुई मनोवृत्ति नहीं है। अपने मन पर संपूर्ण कुशलता प्राप्त करना ही शिक्षा का आदर्श है।" उन्होंने जोर दिया कि नालंदा, तक्षशिला आदि में पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। डॉ सुभाष का प्रमुख मत था कि "वसुधैव कुटुम्बकम्" का मकसद हर क्षेत्र में भारत के सकारात्मक विकास का एक कारक रहा है। जैसा कि भारत ने दिसंबर, 2022 के महीने में G20 प्रेसीडेंसी प्राप्त की, पीएम मोदी ने कहा कि यह "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" के नारे के साथ एकता को और बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। उन्होंने पीएम मोदी द्वारा सामने रखे गए उन उद्देश्यों को रेखांकित किया, जिन्हें आजादी के "अमृत काल" के दौरान हासिल किया जाना तय है।



शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत सूचीबद्ध उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- छात्रों को प्रत्येक विषय का एक निश्चित स्तर तक ज्ञान होना चाहिए।
- भारतीय ज्ञान प्रणाली (Indian Knowledge System) एआईसीटीई, नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के तहत एक अभिनव प्रकोष्ठ है। यह आईकेएस के सभी पहलुओं पर अंतःविषय अनुसंधान को बढ़ावा देने और आगे के शोध और सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए आईकेएस को संरक्षित और प्रसारित करने के लिए स्थापित किया गया है। यह कला और साहित्य, कृषि, बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, प्रबंधन, अर्थशास्त्र आदि के क्षेत्र में हमारे देश की समृद्ध विरासत और पारंपरिक ज्ञान को फैलाने में सक्रिय रूप से संलग्न होगा।
- उन्होंने छात्रों को ऐतिहासिक ज्ञान रखने पर भी जोर दिया, न कि राजाओं और उनके राज्यों के बारे में, बल्कि भारतीय परंपराओं, इसकी समृद्ध संस्कृति और विरासत, इसकी उत्पत्ति और अस्तित्व के बारे में।
- छात्रों के सीखने के लिए एक समग्र अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास आवश्यक है।
- आजादी के अमृत महोत्सव के साथ आगे बढ़ते हुए, आजादी के 100वें वर्ष में ज्ञान की शताब्दी मनाना।
- विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे दीर्घावधि में लगातार उनकी मदद करने के लिए स्वयं को उन्नत करें।

धन्यवाद प्रस्ताव

प्रो. भरत शरण सिंह

अध्यक्ष, प्राइवेट यूनिवर्सिटी फी रेगुलेटरी कमीशन

प्रो. भरत ने सभी वक्ताओं एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस अवसर पर चल रही चर्चा पर प्रकाश डाला और कुछ तर्क जोड़े। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को बदलने से छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा, जिसका इस क्षेत्र के समग्र विकास पर सकारात्मक प्रभाव होगा।

उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के विचार को उद्धृत किया कि युवाओं में इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की क्षमता है। उन्होंने श्रोताओं को एनएसआईएल जैसे शिखर सम्मेलनों के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि यह ऐसे शिखर सम्मेलन हैं जो प्रगति के लिए उपयुक्त नेतृत्व प्रदान करते हैं। विकास के लिए वीबीयूएसएस और डीएवीवी के प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने एक बार फिर इस शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए सभी को धन्यवाद दिया।

समानांतर सत्र 1

समूह 1: कुलपतियों और निदेशकों के साथ बातचीत

सत्र मॉडरेटर: प्रो. प्रशांत गुप्ता, प्रो. भारतीय प्रबंधन संस्थान नागपुर

वक्ता: प्रो. एम जगदीश कुमार, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग



प्रोफेसर प्रशांत गुप्ता द्वारा संचालित इस सत्र में यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार भी शामिल थे। यह अनूठा और संवादात्मक अनुभव उच्चतर शिक्षण संस्थानों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से रचा गया था। सत्र का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों के लिए एक मंच प्रदान करना था ताकि वे अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकें और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान कर सकें, जिसका उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा की स्थिति को सुधारने में मदद करना था।

प्रोफेसर कुमार ने अपने उद्घाटन भाषण में नई शिक्षा नीति (एनईपी) के तीन प्रमुख अवयवों- समग्र शिक्षा, बहुविषयक और शिक्षा में नम्यता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने श्रोताओं को अपने संस्थानों में इन विचारों को अपनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया कि छात्रों को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करे। उन्होंने शिक्षा में कई प्रवेश और निकास विकल्पों के महत्व पर भी प्रकाश डाला, क्योंकि इससे छात्रों को अपनी रुचियों और जुनून को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक नम्यता मिलेगी।

इस सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण विषय था कि कई संस्थानों में अधिकांश अवसंरचना की समस्या आती है। ऐसी संस्थाओं के प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्र ने आईटी संसाधनों, अपर्याप्त कक्षाओं, इंटरनेट और कंप्यूटर तक पहुंच की कमी जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी के बारे में गंभीर चिंताएं जताईं। उन्होंने अपनी दुखद अनुभूति के द्वारा बताया कि एक कॉलेज जिसमें तीन कमरे तक हैं, पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, और इंटरनेट या कंप्यूटर का कोई पहुंच नहीं है, वहां संपूर्ण शिक्षा, बहुविद्यात्मकता और शिक्षा में लचीलापन जैसी विचारों की कोई वैधता नहीं दिखती है। इन चिंताओं पर एक धैर्यपूर्ण और विचारशील प्रतिक्रिया देने के लिए, प्रोफेसर जगदीश ने अपने अनुभवों के बारे में बात की और बताया कि वे इन संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों को कैसे समझते हैं। उन्होंने श्रोतागण को आश्वासन दिया कि यूजीसी इन मुद्दों का संज्ञान लेगा और राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय जैसी पहल निकट भविष्य में इन चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगी।

आगे बढ़ते हुए, गुरुग्राम विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष ने चिंता जताई कि छोटे विश्वविद्यालय नैक (नैक) ग्रेडिंग के बिना यूजीसी दिशानिर्देश के अनुभाग 12-B के तहत सरकारी सहायता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जो एक लंबी प्रक्रिया है। इसके जवाब में, प्रोफेसर कुमार ने बताया कि नैक ग्रेडिंग वास्तव में कॉलेजों की पहचान करने में एक महत्वपूर्ण कारक है और 12-B के तहत प्रावधान संस्थाओं को प्रमाणित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने शिक्षक-प्रशिक्षण की आवश्यकता को उजागर किया और संस्थानों को अनुसंधान और नवाचारी शिक्षण पद्धतियों में निवेश करने की प्रोत्साहन किया, जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा।

सत्र के दौरान, संस्थाओं के बीच शैक्षणिक संसाधनों की पहुँच की मुद्दा उठाया गया, जिसमें इन संसाधनों को एक बड़े छात्र जनसंख्या के लिए उपलब्ध कैसे कराया जाए इस पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रोफेसर कुमार ने एक आगामी परियोजना के बारे में जानकारी दी जिसके माध्यम से छात्र और शिक्षक सदस्यता आधारित मॉडल के माध्यम से एक विशाल पुस्तकालय एक मामूली कीमत पर उपलब्ध होगी। इस परियोजना की उम्मीद है कि छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक संसाधनों की पहुँच मिलेगी, जो उनके शिक्षण अनुभव को सुधारने में मदद करेगी।

संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट/सीयूईटी) की वैधता पर भी चर्चा की गई, खासकर नीट (NEET) और आईआईटी-जेईई (JEE) जैसी परीक्षाओं के संदर्भ में। प्रोफेसर कुमार ने एक सामान्य परीक्षण के महत्व पर बल दिया जो सभी छात्रों के लिए एक समान अवसर प्रदान करेगा और विभिन्न शिक्षा बोर्डों के बीच असमानताओं को कम करेगा। उन्होंने प्रवेश मानदंडों पर संस्थानों की स्वायत्तता की आवश्यकता पर भी जोर दिया और छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने में शिक्षक प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला।

सत्र एक सकारात्मक नोट पर समाप्त हुआ, जिसमें प्रोफेसर कुमार ने सभी को ईमेल द्वारा उनसे संपर्क करने के लिए आमंत्रित किया, यदि उनके कोई और प्रश्न हैं। उन्होंने देश में उच्च शिक्षा के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करने के महत्व पर भी जोर दिया और दर्शकों से आग्रह किया कि वे भारत में शिक्षा की स्थिति में सुधार किस प्रकार करें, इस पर चर्चा जारी रखें।

समानांतर सत्र-1

समूह 2: एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट : एकाधिक प्रवेश और एकाधिक निकास

वक्ता: प्रो. एस.के. गाखर, पूर्व कुलपति, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, रेवाड़ी

प्रो. आरपी तिवारी, वाइस चांसलर, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी

प्रो नवीन शेठ, पूर्व कुलपति, गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय

प्रो. एसके गाखर

पूर्व कुलपति, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, रेवाड़ी

प्रोफेसर एस.के. गाखर ने अपने सत्र की शुरुआत वीडियोएसएस और डीएवीवी को धन्यवाद देकर किया जो उन्हें छात्रों के लिए अकादमिक क्रेडिट बैंक और एंटी और एग्जिट की सुविधा के बारे में अपनी विचारों को रखने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अपना सत्र अकादमिक क्रेडिट बैंक की अवधारणा को समझाते हुए शुरू किया। उन्होंने बताया कि एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट/एबीसी एक वर्चुअल प्लेट फॉर्म है जहां छात्र किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में उनके शैक्षणिक सफर के दौरान जुटाए गए क्रेडिट को एकत्र कर सकते हैं और उन्हें भुना सकते हैं। यह बहुविकल्पीकरण और छात्र-केंद्रित शिक्षा और अन्तरविषयक दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और यूजीसी भारतीय उच्च शिक्षा में एबीसी को एक गेम-चेंजर बनाने का उद्देश्य रखते हैं। छात्रों को अपनी क्रेडिट सूचना तक पहुंचने के लिए एक अद्वितीय आईडी और पासवर्ड के साथ अकाउंट खोलने की जरूरत होगी और डिजिटल पोर्टल पर विवरण और क्रेडिट जमा करने की आवश्यकता है। शैक्षणिक क्रेडिट की वैधता सात वर्ष होगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शैक्षणिक एवं अन्तर्विषयक दृष्टिकोण प्रदान करना है। हालांकि, इस कार्यक्रम को व्यवस्थात्मक चुनौतियों, सीमित सीटों और हितों के विरोध का सामना भी करना पड़ता है। शैक्षणिक चुनौतियों में शैक्षणिक गुणवत्ता, मानकीकरण और संस्थाओं के बीच क्रेडिट के ट्रांसफर का भी समावेश है। प्रो. गाखर ने लोगों की जरूरत के बारे में भी बताया और बड़ी पंजीकरण का संचालन करने से जुड़ी चुनौतियों को भी उठाया। अंततः, उन्होंने अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता और उच्च शिक्षा प्रणाली में शिक्षण स्थानों की संख्या को संचालित करने के महत्व को भी जोर दिया।

प्रो. आर.पी. तिवारी

कुलपति, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय

प्रो. आर.पी. तिवारी ने पैनल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भाषण की शुरुआत की और यह कहकर जारी रखा कि प्रो. गाखर ने एनईपी के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि कई प्रवेश-निकास विकल्पों को कवर किया।

उन्होंने आगे बताया कि कैसे एनईपी 2020 पिछले संस्करणों से दो प्रमुख तरीकों से अलग है: यह छात्र-केंद्रित और भारत-केंद्रित है। यह भारत-केंद्रित है क्योंकि यह मातृभाषा में सीखने के साथ-साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली और इसका उपयोग करने के तरीके के बारे में सीखने पर केंद्रित है।

उन्होंने एनईपी 2020 में किए गए दो बड़े बदलावों की ओर इशारा किया जो इसे और अधिक छात्र-केंद्रित बनाते हैं: क्रेडिट का एक अकादमिक बैंक और कई प्रवेश/निकास बिंदु। उन्होंने कहा कि प्रो. गाखर ने प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की और वह उन्हें जोड़ना चाहेंगे। उन्होंने क्रेडिट बैंक पर चर्चा की, जिसमें छात्र को एक डिजी लॉकर खाता खोलना होगा, जिसमें विश्वविद्यालय/संस्थान छात्र द्वारा लिए जाने वाले प्रत्येक पाठ्यक्रम के पूरा होने पर अपने क्रेडिट अंक स्थानांतरित करेंगे। यह छात्रों को विभिन्न संस्थानों के साथ काम करने की अनुमति देता है ताकि वे उन पाठ्यक्रमों के आधार पर अपनी डिग्री पूरी कर सकें जिन्हें वे लेना चाहते हैं- यह छात्रों के लिए सीखने के पारिस्थितिकी तंत्र को भी बदलता है।



एकाधिक प्रवेश-निकास बिंदु छात्रों को अपने पाठ्यक्रम और संस्थान चुनने की अनुमति देते हैं। यहां तक कि अगर छात्र अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पाठ्यक्रम पूरा करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें उन पाठ्यक्रमों के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा जो उन्होंने पहले ही पूरा कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों को उनके पहले वर्ष में अधिक कौशल-आधारित पाठ्यक्रम दिए जाने चाहिए ताकि वे शिक्षा प्रणाली छोड़ने पर भी अपने कौशल का उपयोग कर सकें। परिणाम स्वरूप, उन्होंने हर साल समान क्रेडिट स्कोर के साथ अतिरिक्त कौशल निर्माण कार्यक्रम पेश करने पर जोर दिया। उन्होंने अपने भाषण को कुछ मुख्य बिंदुओं के साथ समाप्त किया। यदि उत्तर पुस्तिकाओं में डिजी लॉकर नंबर का उल्लेख किया गया है, तो विषय के क्रेडिट अंक खाते में तुरंत जोड़ दिए जाएंगे।

प्रो. नवीन शेट

पूर्व कुलपति, गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय

प्रो. नवीन ने यह कहते हुए अपना भाषण शुरू किया कि भारत का सकल नामांकन अनुपात 26% है (उच्च शिक्षा में केवल 26% प्रवेश के साथ) और एनईपी के कार्यान्वयन के कारण 2035 तक इसके 50% होने की उम्मीद है। स्पीकर ने इस बात पर जोर दिया कि 70% एनईपी कार्यान्वयन कार्य के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार हैं और उनसे तदनुसार कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों ने अपने शासी निकायों या उनके पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एनईपी को धीरे-धीरे लागू करना शुरू किया। उन्होंने विश्वविद्यालयों से संस्थागत पंजीकरण प्रणाली में पंजीकरण करने और अपने छात्रों के प्रमाण पत्र अपलोड करने का आग्रह किया। छात्र डिजी लॉकर खातों पर छात्रों के लिए कुछ शिक्षा सत्र भी होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि कई प्रवेश-निकास बिंदु और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन कुछ विषयों के दो अलग-अलग सेमेस्टर में दो भाग होते हैं, जिससे छात्रों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करना मुश्किल हो जाता है।

उन्होंने यह कहकर अपना भाषण समाप्त किया कि कई प्रवेश-निकास बिंदु एबीसी से जुड़े हुए हैं और दोनों को शैक्षणिक संस्थानों द्वारा समानांतर रूप से किया जाना चाहिए।

समानांतर सत्र 1

समूह 3: बहुविषयक और समग्र शिक्षा

वक्ता: प्रो. अमी उपाध्याय, कुलपति, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद
डॉ. गौरीशा जोशी, प्रोफेसर और निदेशक, शिक्षा और सामाजिक अध्ययन केंद्र, बेंगलुरु
प्रो. विभा सिंह चौहान, पूर्व प्राचार्य, किरोड़ीमल कॉलेज, नई दिल्ली



प्रो. अमी उपाध्याय

डॉ. गौरीशा जोशी

प्रो. विभा सिंह चौहान

प्रो अमी उपाध्याय

कुलपति, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ओपन विश्वविद्यालय, अहमदाबाद

प्रो. अमी ने 'अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम: अंतर-संस्थागत विकास पर एक संवाद' के आयोजन के लिए वीबीयूएसएस और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को धन्यवाद दिया। उन्होंने इसे नई शिक्षा नीति 2020 और इसके क्रियान्वयन पर चर्चा करने का एक बेहतरीन मंच बताया। उन्होंने वक्ताओं की भी प्रशंसा की और एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में उनके दृष्टिकोण और तर्कों का समर्थन किया। प्रो. अमी ने एनईपी 2020 को एक कठोर ढांचे के रूप में वर्णित किया, जिसे छात्रों और संस्थानों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर, वह यह भी दावा करती हैं कि एनईपी को एक सरलीकृत रूप में तैयार किया गया है और सभी इसे समझ सकते हैं।

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ओपन विश्वविद्यालय, अहमदाबाद के कुलपति के रूप में, प्रो. अमी ने अपने संस्थान में दूरस्थ शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला, जो एक ओपन विश्वविद्यालय है। उन्होंने नई शिक्षा नीति, 2020 के संबंध में दूरस्थ शिक्षा की प्रासंगिकता पर जोर दिया और शिक्षा में अधिक पहुंच और समावेश को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

अपने व्याख्यान में आगे बढ़ते हुए उन्होंने उद्धृत किया, "एनईपी 2020 पहली शिक्षा नीति रही है जो मूल रूप से छात्र-केंद्रित रही है"। अपनी बात को बढ़ाते हुए और दर्शकों को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) की अवधारणा से परिचित कराना जो छात्रों के लिए "अंधेरे में प्रकाश" के अवसर के रूप में जाता है- उन्होंने बताया कि यह एक वर्चुअल/डिजिटल स्टोर हाउस है जिसमें भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के व्यक्तिगत छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट की जानकारी होती है और जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से एबीसी के महत्व को भी समझाया:

- छात्रों के व्यक्तिगत खातों में संग्रहीत क्रेडिट छात्रों को उनके अकादमिक/करियर विकल्पों के मामले में स्वतंत्रता का एक बड़ा दायरा प्रदान करेगा।
- छात्र किसी भी वर्ष/सेमेस्टर से अपने संस्थान को छोड़ने में सक्षम होंगे और पात्र होने पर प्रमाण पत्र/डिप्लोमा के साथ अब तक अर्जित क्रेडिट का आदान-प्रदान कर सकेंगे। वे क्रेडिट को भुनाने और उसी संस्थान या अपनी पसंद के किसी अन्य संस्थान में उसी समय या भविष्य में किसी अन्य समय पर फिर से शामिल होने में सक्षम होंगे और वर्ष/सेमेस्टर से अपनी शिक्षा लंबित रूप में जारी रखेंगे।

- यदि कोई छात्र किसी भी कारण से पाठ्यक्रम/संस्थान को छोड़ने का फैसला करता है तो यह उसकी उच्च शिक्षा पर खर्च किए गए समय को व्यर्थ नहीं जाने देगा।
- यह योजना पैसे कमाने के मकसद से छात्रों को उनकी मर्जी के खिलाफ अपने पाठ्यक्रमों में नामांकित रखने के लिए कुछ संस्थानों द्वारा अपनाई गई जबरदस्ती प्रणाली को खत्म कर देगी।

उन्होंने SWAYAM, NPTEL, V-Lab जैसे ई-शिक्षा माध्यमों और उनके पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाली अन्य योजनाओं पर भी प्रकाश डाला, जो अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी, लेकिन ध्यान में लाया कि पाठ्यक्रम सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं हैं जो उपलब्ध भाषाओं के लिए जाने जाने वाले लोगों तक पहुंच को सीमित करते हैं।

प्रो. अमी ने डिजिटल विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी समर्थन किया जो पूरी तरह से डिजिटल मोड के माध्यम से कार्य करते हैं। वर्तमान में, भारत में दो डिजिटल विश्वविद्यालय हैं- केरल का डिजिटल विश्वविद्यालय और जोधपुर, राजस्थान में स्थापित डिजिटल विश्वविद्यालय।

अपने भाषण को समाप्त करते हुए, उन्होंने गुजरात में जनजातीय क्षेत्रों को परिचय दिया और बताया कि कैसे उनकी जातीय संस्कृति भाषा, साहित्य, पिटोरा चित्रकारी के रूप में हैं। उन्होंने इन विषयों को क्रेडिट फ्रेमवर्क में रूपांतरित करके संस्कृति को बढ़ावा देने और उसे जीवित रखने के लिए जागरूक किया।

डॉ. गौरीशा जोशी

प्रोफेसर और निदेशक, सेंटर फॉर एजुकेशन एंड सोशल स्टडीज, बेंगलुरु

सेंटर फॉर एजुकेशन एंड सोशल स्टडीज के निर्देशक डॉ. गौरीशा जोशी ने बुद्धिजीवियों की सभा को अपने विनम्र शब्दों से बधाई दी। उन्होंने छात्रों की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों के महत्व का उल्लेख किया क्योंकि वे विभिन्न क्षेत्रों और सरोकारों के बारे में सीखते हैं और विषयों का प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करते हैं जो उन्हें भविष्य में मदद करेगा।

उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव प्रस्तुत किया जहां उन्होंने कई शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि का दौरा किया और छात्रों को विभिन्न विषय क्षेत्रों में खुद को समृद्ध करते देखा। उन्होंने अपने संस्थान का उदाहरण भी दिया जहां वाणिज्य और प्रबंधन शाखा के छात्र अपनी सुविधा और रुचि के अनुसार विषयों को ढालते हैं। "कौशल विकास कार्यक्रम" छात्रों और प्रोफेसरों दोनों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने "टी शेड प्रोफेशन" की एक महत्वपूर्ण और नई अवधारणा का विवरण किया। यह एक ऐसा दृष्टिकोण नहीं है जो वर्णमाला टी से शुरू होता है, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक रूप है जहां टी के क्षैतिज ढाल कोर क्षेत्र के अलावा कुशलता और व्यवसाय समेत अन्य क्षेत्रों के बारे में बात करता है, जबकि लंबवत रेखा बहुविज्ञान क्षेत्र की गहन अध्ययन को दर्शाती है। इसलिए, टी शेड कौशल उन विशेष प्रकार के गुणों को संदर्भित करते हैं जो किसी कर्मचारी को मूल्यवान बनाते हैं। टी शेड व्यक्ति विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्ट ज्ञान और कौशल रखता है और सहयोगी तरीके से दूसरों के साथ काम करने में अच्छा होता है।

टी-आकार के पेशेवरों की शुरुआत के साथ, प्रोफेसर ने सत्र को सत्र के विषय के साथ जोड़ा जो बहुविषयक और समग्र शिक्षा थी। मल्टीडिसिप्लिनारिटी की अवधारणा की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि यह पुराने समय से मौजूद है और इसे पहले "लिबरल आर्ट्स" कहा जाता था। हालांकि, आधुनिक समय में, इसे सीखने की हर बारीकियों को जानने के रूप में माना जाता है, जिसके बारे में वक्ता ने तर्क दिया कि इसकी उत्पत्ति को छोड़े बिना अनुशासन में निहित होना चाहिए। अपनी प्रस्तुति के दौरान, प्रोफेसर जोशी ने वास्तविकता का दौरा करने के साधन के रूप में अनुशासन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन ने विश्वविद्यालयों को अपने स्वयं के कार्यक्रम और पोर्टफोलियो विकसित करने के लिए प्रेरित किया है, जो बहुविषयक और समग्र शिक्षा की अवधारणा को बाधित कर सकता है। यह स्वीकार करते हुए कि बहु-अनुशासन का विकल्प नहीं है, उन्होंने यह भी कहा कि अनुशासन केवल सामग्री के बारे में नहीं बल्कि सोच के बारे में भी है। इसके अलावा, उन्होंने छात्रों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने तर्क दिया कि एआई छात्रों को कम सक्षम बना सकता है क्योंकि वे समाधान के लिए प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, जिससे उन्हें शोध करने और अपने दम पर उत्तर खोजने में कम प्रयास करना पड़ता है। इसका प्रतिकार करने के लिए, प्रोफेसर जोशी ने करके सीखने के महत्व पर जोर दिया और संस्थानों को मैनुअल और डिजिटल शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों प्रदान करने में पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि अन्य संस्थानों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया जा सके।

इसके साथ, वह निष्कर्ष पर पहुंचे और उद्धृत किया, "नीति तभी प्रभावी और कुशल होगी जब इसे क्रियान्वित किया जाएगा"।

प्रो. विभा सिंह चौहान

पूर्व प्रधानाध्यापिका, किरोड़ीमल कॉलेज, नई दिल्ली

किरोड़ीमल कॉलेज, नई दिल्ली की पूर्व प्राचार्या प्रो. विभा सिंह चौहान ने नई शिक्षा नीति 2020 पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करने के लिए वीडियोएसएस और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त किया। नई शिक्षा नीति पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने यह बताया कि "एनईपी एक दृष्टिकोण है और वहाँ पहुंचना एक मिशन है। यह एक नीति है जो मजबूत बेस रूट से तैयार की गई है, इसलिए यह नीति जड़हीन नहीं है।" उन्होंने यह भी बताया कि कैसे एनईपी 2020 एक दूरदर्शी नीति है, हालांकि इसे वर्तमान में लागू किया गया है, इसकी जड़ें अतीत में हैं। उन्होंने चौंसठ कलाओं और चौदह विद्याओं से प्रेरणा ली, जिन्हें भगवान कृष्ण ने सिर्फ चौंसठ दिनों में अभ्यस्त किया था, भारतीय संस्कृति में इन कलाओं और विज्ञान के महत्व को उजागर किया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया जहां उन्होंने आठ चीजें ली हैं जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

- डीएससी- अनुशासन विशिष्ट पाठ्यक्रम
- डीएसई- अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक
- जीई- जनरल ऐच्छिक
- एईसी- क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम
- आईएल- आठवीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का पूल
- एसईसी- स्किल एनहांसमेंट कोर्स
- IAPC- इंटरशिप शिक्षता प्रोजेक्ट। सामुदायिक पहुँच
- VAC- वैल्यू एडिशन कोर्स

प्रोफेसर ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एनईपी 2020 के सफल कार्यान्वयन में मदद करने वाले आठ कारकों की व्याख्या की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 21 वीं सदी के छात्र, विशेष रूप से 15 से 25 वर्ष की आयु के छात्र, सुपर स्पेशलाइजेशन पर केंद्रित हैं। एनईपी अंडरग्रेजुएट्स के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि यह उन्हें मूल्यवान क्रेडिट अर्जित करने में सक्षम बनाता है जो उनकी बड़ी कंपनियों के लिए योगदान कर सकते हैं। इसके अलावा, एनईपी छात्रों को अपनी डिग्री को अस्थायी रूप से बंद करने और बाद में उसे आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापन के साथ फिर से शुरू करने की सुविधा भी देता है। उनकी प्रस्तुति छात्रों, प्रोफेसरों और उन सभी विशिष्ट व्यावसायिकों के लिए जो उपस्थित थे, उपयोगी और जानकारीपूर्ण थी।

अगली स्लाइड में उन्होंने बताया कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले सेमेस्टर के छात्रों के लिए वैल्यू एडिशन कोर्स शुरू करने पर काम कर रही है। कुछ नए कार्यक्रमों में अकादमिक प्रगति भी होगी। "पहले सेमेस्टर में शुरू किए गए 24 पाठ्यक्रमों को दूसरे सेमेस्टर में फिर से पेश किया जाएगा। छात्रों को केवल एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा क्योंकि उनके पास चुनने के लिए अन्य 23 पाठ्यक्रम होंगे। उन्होंने बताया कि कुछ पाठ्यक्रमों में अकादमिक प्रगति के साथ-साथ कठिनाई का स्तर भी बढ़ाया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर पहली सेमेस्टर में वैदिक गणित पेश किया जाता है, तो दूसरे सेमेस्टर में वैदिक गणित-2 पेश किया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों के अलग-अलग लर्निंग ऑब्जेक्टिव और आउटकम होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कॉलेज क्लस्टर योजना भी तैयार की है, जिसके तहत DU अपने चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के तहत अपने विभिन्न विषयों में से अधिकतम विषयों का एक क्लस्टर बनाने की योजना बना रहा है। इन शब्दों से, वह अपने सत्र को समाप्त किया।



समानांतर सत्र 1

समूह 4: उच्च शिक्षा संस्थानों में अभिनव प्रयोग

वक्ता: प्रो. बी.वी.आर. रेड्डी, निर्देशक, एनआईटी कुरुक्षेत्र
प्रो. पंकज मित्तल, महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ
प्रो. डीपी गोयल, निदेशक, आईआईएम शिलांग



प्रो. बी.वी.आर. रेड्डी

प्रो. पंकज मित्तल

प्रो. डीपी गोयल

प्रो. बी.वी.आर. रेड्डी

निर्देशक, एन.आई.टी. कुरुक्षेत्र

प्रोफेसर बी.वी.आर. रेड्डी ने अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2023 के समानांतर सत्र समूह 4 को इसके उद्देश्य को रेखांकित करते हुए शुरू किया। उन्होंने बताया कि सत्र का उद्देश्य देश भर के शैक्षणिक संस्थानों की नवीन प्रथाओं का पता लगाना है और कैसे ये अनुभव नई शिक्षा नीति को मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में उल्लिखित लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है।

प्रो.रेड्डी ने एनईपी 2020 के महत्व के बारे में बात की और बताया कि कैसे यह आने वाले समय का दस्तावेज है जो देश की शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लाने जा रहा है जिसका फल आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। प्रोफेसर रेड्डी ने बताया कि लंबे समय से छात्र उन परिवर्तनों की मांग कर रहे हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो उन्हें 21वीं सदी में सफल होने के लिए उपकरणों से लैस करेगा। आजादी के बाद कई नीतियां आई हैं, लेकिन हम सभी एकत्र उन्हें मूल्यांकन या लागू करने में कितने सक्षम रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए नई शिक्षा नीति में दस्तावेजों के निर्माण पर बहुत जोर दिया गया है और अब 3 साल के बाद हर संस्थान ने समय सीमित प्रयास किए हैं जो दृश्यमान हैं। उन्होंने परिवर्तन प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनपुट उनसे प्राप्त किया जाता है, जो सच्चे हितधारक हैं। एक बहु-विषयक और समग्र दृष्टिकोण का उपयोग करके, मूल्य-आधारित शिक्षा प्रदान करने और उद्यमशीलता क्षमताओं के निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए।

उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में तकनीक के बढ़ते महत्व का और बताया और बताया कि अब अधिक से अधिक संस्थानों को नवीनतम तकनीकी तरीकों से लैस होने की जरूरत है और अपने कर्मचारियों को 21वीं सदी की आवश्यक योग्यता और प्रशिक्षण से संपन्न करने के लिए पुनः-कुशलता और उन्नत करने की आवश्यकता है। उन्होंने NIT कुरुक्षेत्र का उदाहरण दिया, जो तकनीक क्षेत्र में नौकरी की बाजार को मानते हुए अपने पाठ्यक्रम को नवीनात्मक बहुविषयक दृष्टिकोण के अनुरूप बदलकर उद्यमी योग्यता को मुख्य थीम के रूप में शिक्षित कर रहा है।

प्रो. पंकज मित्तल,

प्रधान सचिव, भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ

प्रोफेसर पंकज मित्तल ने सभी से यह पूछना शुरू किया कि क्या वे हिंदी भाषा के साथ सहज हैं क्योंकि वह हिंदी में अपने विचार व्यक्त करना चाहती थीं, जो उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा को महत्व देने का उनका तरीका था। उन्होंने अपने सत्र की शुरुआत एक छोटे से उदाहरण से की जहां वह एक ग्रामीण महिला विश्वविद्यालय में गई थीं। उन्होंने कहा कि वह वहाँ जो प्रमुख मुद्दा देख सकती थी, वह यह था कि शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षण पद्धति केवल "पुस्तक से पढ़ना" थी, जहाँ छात्रों और शिक्षकों के बीच कोई संपर्क नहीं था। इस तरह के अभ्यास शिक्षक-छात्र संबंध में बाधा डालते हैं जो शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उन्होंने अपनी संस्था की अभिनव पुस्तक, "डिस्कवर क्वेश्चन" के बारे में बताया, जिसमें उनके दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला थी। प्रश्न इस अर्थ में तैयार किए गए थे कि बच्चे "सोचने के लिए मजबूर" थे। छात्रों को एक बार में एक ही प्रश्न का उत्तर खोजने को कहा गया। और अपने जवाब स्कूल द्वारा बनाए गए कॉमन ड्रॉपबॉक्स में डालें। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि "न केवल छात्रों बल्कि शिक्षकों ने भी इस मजेदार सीखने की गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लिया"। इसके तुरंत बाद, कक्षाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए संस्थानों के शिक्षकों ने उन अवधारणाओं के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया, जो छात्रों के बीच रचनात्मक नवाचारों को बढ़ावा देती हैं।

प्रोफेसर मित्तल ने 'चैट जीपीटी' के बढ़ते प्रभाव/अनुगम को लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि Chat GPT के आविष्कार के साथ, हम शिक्षकों को कक्षाओं में शिक्षकों की भागीदारी और नई शिक्षण विधियों के विकास की आवश्यकता के लिए नए नवाचारों के साथ आने की जरूरत है। उन्होंने Chat GPT के नकारात्मक प्रभावों की ओर इशारा किया कि यह बच्चों के विकास को कैसे प्रतिबंधित करता है और कक्षा में अध्ययन के बीच एआई अध्ययन और कक्षा में अध्ययन के बीच मुख्य अंतर है। एआई व्यक्तिगत अध्ययन प्रदान नहीं कर सकता जो कक्षा में होता है। जैसा कि हर बच्चा अलग होता है, कक्षा में सीखना उन्हें व्यक्तिगत शिक्षण और सीखने के तरीके प्रदान करता है। उन्होंने कक्षाओं में "मिश्रित शिक्षा" की अवधारणा का सुझाव दिया जो एआई और कक्षा सीखने को एक साथ मिलाएगा। उन्होंने इस नोट पर समाप्त किया कि बहुत जल्द शिक्षक की भूमिका पूरी तरह से बदलने वाली है और हमें इस बदलाव के लिए तेजी से अनुकूलन करने और कक्षा में सीखने को रचनात्मक और आकर्षक बनाने के लिए नए समाधानों के साथ आने की जरूरत है।

प्रो. डी.पी. गोयल

निर्देशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलॉंग

शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रोफेसर डी.पी. गोयल ने गणमान्य श्रोतागण के साथ बातचीत में शामिल होने के अवसर के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्वीकार किया कि आज के डिजिटल युग में, छात्रों को इंटरनेट पर अपनी जरूरत की सभी जानकारी आसानी से मिल जाती है, जिससे शिक्षकों और अभिभावकों पर उनकी निर्भरता कम हो गई है। उन्होंने तर्क दिया कि यह सवाल उठता है कि शिक्षण संस्थान कैसे छात्रों को कक्षाओं में वापस ला सकते हैं और शिक्षा को रोचक बना सकते हैं।

प्रोफेसर गोयल ने इस प्रौद्योगिकी युग में शिक्षा क्षेत्र को बदलने के लिए नवीन और रचनात्मक विचारों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बर्बाद करने का समय नहीं है और आज की दुनिया के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए साधन और पाठ्यक्रम को बदलने का सुझाव दिया। उन्होंने आईआईएम शिलांग की "आकर्षक कक्षाओं" की अवधारणा का उदाहरण दिया, जहां छात्र सक्रिय भागीदार होते हैं और शिक्षक सूत्रधार के रूप में कार्य करते हैं। कक्षा से एक दिन पहले पीपीटी वितरित करने से शिक्षकों और छात्रों के बीच जुड़ाव और विश्वास को बढ़ावा मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप कक्षा में अधिक संवाद बढ़ता है।

प्रोफेसर गोयल ने "फन लर्निंग" प्रक्रियाओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जैसे कि व्यावहारिक परियोजना-आधारित शिक्षा और छात्रों और समाज के बीच सहयोग। उन्होंने "छात्रों के लिए जमीनी स्तर पर सीखने के तरीके - गांव में 20 दिन" दृष्टिकोण पर चर्चा की, जो छात्रों को अपनी जड़ों से जुड़ने और विनम्रता विकसित करने में मदद करता है। उन्होंने 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही भावना से लागू करने और संस्थानों और हितधारकों द्वारा प्रस्तुत अवसरों को जब्त करने की आवश्यकता पर बल देते हुए निष्कर्ष निकाला।



समानांतर सत्र 1

समूह 5: वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और आईसीटी

वक्ता: प्रो. नागेश्वर राव: वाइस चांस, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

प्रो. बिनोद कुमार कनौजिया: निदेशक, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर



प्रो. नागेश्वर राव



प्रो. बिनोद कुमार कनौजिया

प्रो. नागेश्वर राव

कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

प्रोफेसर राव ने आभासी/वर्चुअल विश्वविद्यालयों की स्थापना पर चर्चा करते हुए अपने सम्बोधन की शुरुआत की और इसे हासिल करने के तीन तरीके बताए। इसके बाद उन्होंने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) दृष्टिकोण पर विस्तार से बताया, जिसमें शिक्षकों और छात्रों के बीच आभासी बातचीत और प्रिंट सामग्री का वितरण शामिल है। उन्होंने "स्व-शिक्षण सामग्री" और "पाठ्यपुस्तक अधिगम" के बीच के अंतर पर प्रकाश डाला और सुझाव दिया कि "स्व-शिक्षण सामग्री" की विधि पर विचार किया जा सकता है और वर्चुअल शिक्षा के मोड में ठीक तरीके से उपयोग किया जा सकता है।

2017 में, यूजीसी ने नियम तैयार किए जिसमें किस प्रकार सामग्री वितरित की जाएगी, सामग्री प्रबंधित की जाएगी और अन्य संबंधित पहलुओं को स्थापित किया गया। इसके बाद प्रोफेसर ने हाल ही में नैक मान्यता पर चर्चा की, जो 2021 में हुई थी। उन्होंने "हब एंड स्पोक" मॉडल का भी वर्णन किया, जहां डिजिटल विश्वविद्यालय केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करते हैं जबकि अन्य विश्वविद्यालय प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं।

प्रोफेसर राव ने पाठ्यक्रम आधारित प्रमाणपत्र और पाठ्यक्रम आधारित पंजीकरण के बीच अंतर को उभारा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हाल ही में आए बदलाव के बारे में चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से छात्रों के लिए बहु-अनुशासनात्मक वातावरण बनाने के मामले में पाठ्यक्रम-आधारित दृष्टिकोण के लाभों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वयं पोर्टल की शुरुआत की गई थी, जो सॉफ्ट कॉपी में सामग्री प्रदान करने, वीडियो के माध्यम से शिक्षण, चर्चा मंच और मूल्यांकन के "चार चतुर्थांश दृष्टिकोण" का पालन करता है। डिजिटल शिक्षा के लिए एक व्यापक और अभिनव दृष्टिकोण लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। स्वयं 3000 पाठ्यक्रम प्रदान करता है जहां योग्यता और आयु छात्रों के लिए बाधा नहीं है, और स्वयं प्रभा चैनल डिश टीवी पर 34 चैनल प्रदान करता है, जो शिक्षा का एक अभिनव तरीका प्रदान करता है।

प्रोफेसर राव ने अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर भी चर्चा की, जहां सिस्टम एक बैंक की तरह कार्य करता है और प्रत्येक पासिंग कोर्स के साथ क्रेडिट अर्जित किया जाता है। उन्होंने जापान की नवाचार प्रणाली के साथ तुलना की और सुझाव दिया कि आभासी विश्वविद्यालय हमारे देश में समान स्तर की गुणवत्ता, पहुंच और कल्पना ला सकते हैं।

प्रो. बिनोद कुमार कनौजिया

निर्देशक, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जलंधर

अपने सम्बोधन में प्रोफेसर कनौजिया इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे विभिन्न पहलों के बावजूद, उच्च जनसंख्या के कारण मानव संसाधन के लिए लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग इस संबंध में एक ऐसा नेटवर्क तैयार करने के लिए अत्यंत अनिवार्य है जो अधिकांश लोगों के लिए सुलभ हो। यह सर्वविदित है कि आईसीटी एक अवधारणा है लेकिन इसकी कार्यप्रणाली को समझने का तरीका अधिक प्रासंगिक है जिसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। शिक्षकों को एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जो छात्रों को आकर्षित करे और चैनलाइज़ करे, इसलिए यह पारंपरिक शिक्षाशास्त्र के बजाय विभिन्न आईसीटी और ऑनलाइन तरीकों का उपयोग करके पर्यावरण के बारे में अधिक है। इस प्रकार का 'स्टूडेंट वेब' का निर्माण करना महत्वपूर्ण है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन विधियों तक पहुंच प्राप्त हो सके।

उन्होंने भारत से शिक्षा प्राप्त करने वाली विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ के बारे में बात करके भारतीय बौद्धिक संपदा की महानता पर भी प्रकाश डाला। प्रोफेसर कनौजिया के अनुसार सबसे अच्छा तरीका वह है जिसमें संदेह समाशोधन और चर्चा शामिल है और जहां छात्रों को काम करने के लिए विभिन्न असाइनमेंट दिए जाते हैं ताकि शिक्षकों द्वारा इसे क्रॉस-चेक किया जा सके। इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए इसे वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में शामिल किया जा सकता है।

उनका मानना है कि नई शिक्षा नीति छात्र-हितैषी है और ऐसा वर्चुअल लर्निंग फ्रेमवर्क भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए, इस तरह से मॉड्यूल डिजाइन करना जो छात्र की आवश्यकताओं के अनुकूल हो, एक ऐसी पहल है जो इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। डिजिटल उपकरणों की कमी है जो फिर से एक संरचनात्मक समस्या बन जाती है जिसे ऑनलाइन ढांचे की उपस्थिति से मिटा दिया जाता है। मूल्यांकन भी एक चुनौती है, इसलिए उचित निगरानी पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रोफेसरों को पदोन्नति के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली कैसे प्रवेश करती है, इसकी संरचना उन पर निर्भर करती है। प्रोफेसर ने सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपने सम्बोधन को समाप्त किया।

तकनीकी सत्र 1

थीम: एनईपी 2020 बहुविषयक और समग्र शिक्षा के आलोक में भारत में उच्च शिक्षा का भविष्य

सत्र अध्यक्ष : प्रो. संदीप शास्त्री, कुलपति, जागरण लेक यूनिवर्सिटी, भोपाल

वक्ता: प्रो. भूषण पटवर्धन: अध्यक्ष, नैक

डॉ. अश्विन फर्नांडीस: मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में Quacquarelli Symonds (QS) के क्षेत्रीय निदेशक, QS IGAUGE रेटिंग सिस्टम के CEO]



प्रो. भूषण पटवर्धन



डॉ. अश्विन फर्नांडीस

प्रो. भूषण पटवर्धन

अध्यक्ष, नैक

प्रो. पटवर्धन ने एनईपी दस्तावेज़ के महत्व का उल्लेख करते हुए अपने सम्बोधन की शुरुआत की क्योंकि वे मानते हैं कि यह अपनी तरह का इकलौता है और भारतीयों के बीच गर्व की भावना का उजागर करता है। यह मातृभाषा में सीखने के मार्ग प्रदान करता है। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को बधाई दी क्योंकि मध्य प्रदेश में एक संस्थान ने हिंदी में चिकित्सा शिक्षा देना शुरू किया है। उन्होंने उल्लेख किया कि विषय के ज्ञान को अंग्रेजी के ज्ञान से समान नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि शीर्ष चिकित्सा संस्थानों वाले देश अंग्रेजी में नहीं बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देते हैं। नालंदा और तक्षशिला के समय से ही भारत बहुविषयक शिक्षा का केंद्र रहा है। और हमें भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वह पतंजलि स्कूल ऑफ नॉलेज को भी स्वीकार करते हैं क्योंकि इसने मनोविज्ञान का अध्ययन तब भी किया था जब पश्चिमी विज्ञानों ने इस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था। भारत को अभी एनईपी को एक उपहार के रूप में मानना चाहिए। संस्कृत को 'ज्ञान' भाषा के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है, साथ ही आईकेएस के पुनर्व्याख्यान से भारत को उच्च शिक्षा और समग्र विकास के संदर्भ में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

डॉ. अश्विन फर्नांडीस

मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में QS Quacquarelli Symonds के क्षेत्रीय निदेशक;
QS IGAUGE रेटिंग सिस्टम के सीईओ

डॉ अश्विन फर्नांडीस ने भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में "ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी - २०२०" शीर्षक से एक प्रस्तुति साझा की। उन्होंने कहा कि भारतीयों को एनईपी की उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए और भारत में एनईपी की भविष्य की संभावनाओं को देखना चाहिए। प्रस्तुति की शुरुआत 'वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत' से हुई, जिसमें भारत की शैक्षिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। इसने अन्य देशों के साथ-साथ देश की जीडीपी वृद्धि की तुलना में भारत की उन्नति दर को प्रदर्शित किया। डॉ. अश्विन ने अपनी प्रस्तुति में यह भी कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश 2047 तक 40 ट्रिलियन डॉलर के पड़ाव तक पहुंच जाए, तो हमें उच्च शिक्षा में निवेश करना होगा।

अपनी प्रस्तुति के साथ आगे बढ़ते हुए, उन्होंने 'राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को संभालने में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका' पर अपनी राय रखी। अपनी बात का समर्थन करने के लिए, डॉ. अश्विन ने कुछ आंकड़े साझा करते हुए दिखाया कि उच्च शिक्षा के उद्देश्य से भारत छोड़ने वाले पांच लाख से अधिक छात्रों की तुलना में हर साल केवल 40 से 50 हजार छात्र ही वापस लौटते हैं। नतीजतन, एक अंतर्वाह के बजाय, उच्च शिक्षा से एक अरब डॉलर का बहिर्वाह होता है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024 में यह आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।

डॉ. अश्विन ने आगे कहा कि भारत अधिकांश अन्य देशों की तुलना में शिक्षा पर अधिक खर्च करता है, फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है और हासिल किये जा सकते हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि, "भारतीय छात्र विदेश जाने का चुनाव क्यों करते हैं?" अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने कुछ संभावनाएँ बताईं:

- पारंपरिक पाठ्यक्रमों की तुलना में अधिक विकल्प उपलब्ध हैं
- अभिगम्यता
- बेहतर शोध के अवसर
- अप्रवासन
- कैरियर विकास

इन मुद्दों का समाधान करने के लिए, उन्होंने यह बल दिया कि भारत को निम्नलिखित विकल्पों पर काम करने की आवश्यकता है:

- शोध की गुणवत्ता
- नए कोर्स का परिचय
- सुसज्जित संस्थान
- बेहतर अवसंरचना

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि रैंकिंग एक ड्राइविंग कारक है जो तेजी से लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करेगा। नतीजतन, भारतीय कॉलेजों को विदेशी छात्रों की भर्ती के लिए अपनी विश्वव्यापी रैंकिंग बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही स्वदेशी छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालयों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

अंत में, डॉ. अश्विन फर्नांडीस ने कहा कि भारत अपनी शैक्षिक प्रगति में एक स्थिर मार्ग पर है, क्योंकि 2022 में, भारत ने अन्य एशियाई देशों को पीछे छोड़ दिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में अनुकूल वृद्धि देखी। वे कहते हैं, "एनईपी शिक्षा प्रणाली को हुए नुकसान के वर्षों के पुनर्निर्माण का प्रयास कर रही है और भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने के लिए शिक्षा में एक आवश्यक भूमिका निभाएगी।"

तकनीकी सत्र- 2

थीम: भारतीय ज्ञान परम्परा, मूल्य और लोकाचार

सत्र अध्यक्ष : प्रो. के.एन. सिंह, कुलपति, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया

वक्ता: प्रो. शक्ति प्रसाद मिश्रा, निवेदिता चेयर, रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, कोलकाता
प्रो. टी. वी. कट्टीमनी, वाइस चांसलर, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश
डॉ. नागेश भंडारी, अध्यक्ष, इंडस विश्वविद्यालय, अहमदाबाद



प्रो. शक्ति प्रसाद मिश्र

निवेदिता चेयर, रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, कोलकाता

प्रोफेसर मिश्र ने कहा कि 21वीं सदी भारत की है। अपने डिजिटल, हर्बल और आध्यात्मिक कौशल के साथ भारत एक महाशक्ति और नवाचार का वैश्विक केंद्र बन सकता है। अनूठे भारतीय ज्ञान प्रणाली, मूल्यों और लोकाचार के साथ, हमें पूरे विश्व को दिव्य मानना चाहिए। उन्होंने अपने सम्बोधन में भारत का मिली जी-20 की अध्यक्षता के बारे में भी बात की और कहा कि इस में “एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य” का नारा दिया गया है जो भारतीय परंपरा कि झलक का दर्शाता है। भारत यह स्वीकार कर रहा है कि वसुधैव कुटुम्बकम् का विचार दुनिया को एक संस्कृति के मूल्यों के साथ जोड़ने में उपयोगी होगा। प्राचीन भारतीय ज्ञान की मूल विशेषताओं को फिर से स्थापित करके भारत विश्वगुरु के रूप में अपनी पदवी स्थापित कर सकता है।

प्रो. टी.वी कट्टीमनी

कुलपति, आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय

प्रोफेसर कट्टीमनी ने अपने विचारों को गणमान्यजनों के सामने प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करने के लिए संगठन को धन्यवाद देते हुए अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने ज्ञान और परंपरा के बीच संबंध स्थापित करके अपने व्याख्यान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि कैसे परंपराएं और लोकाचार छात्रों में विषय ज्ञान विकसित करने और उन्हें भारतीय संस्कृति और परंपराओं से अधिक जुड़ा हुआ महसूस कराने में मदद करते हैं। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयानों में से एक को उद्धृत किया जहां उन्होंने उल्लेख किया कि तकनीकी प्रयोगशालाओं को हर छात्र तक पहुंचना चाहिए, अर्थात "लैब टू लैंड, लैंड टू लैब"। यह देश और शिक्षा प्रणाली को सिर्फ नतीजों के लिए सिद्धांत पुस्तकें रटने से ज्यादा अनुसंधान-अभिप्राय केंद्रित बनाएगा। उन्होंने इस अवधारणा को समझाने पर ध्यान केंद्रित किया कि पहले के समय में भी छात्र प्राथमिक स्तर से ही शोध करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे और तत्काल परिणाम प्राप्त करने में बहुत अधिक नहीं अटकते थे। इस प्रकार छात्रों के अनुसंधान कौशल को बढ़ाने पर काम करने की आवश्यकता है।

उन्होंने भारत की संस्कृति और परंपरा के विकास और संरक्षण में महिलाओं की प्रमुख भूमिका के बारे में भी बताया। "उनमें से कई हरित क्रांति के साथ-साथ श्वेत क्रांति का अभिन्न अंग रहे हैं", उन्होंने कहा।

पारंपरिक लोकाचार और संस्कृति के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे आदिवासियों ने भारत के निर्माण में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। उन्होंने उस समय से भी आदिवासियों के अस्तित्व की बात की जब धर्म की संरचना स्थापित भी नहीं हुई थी। वे हमेशा इस विश्वास में रहे हैं कि उन्हें अधिक मिलना चाहिए और कम होने से काम नहीं चलेगा। पुराने समय में जब GDP का कोई रिकॉर्ड या गणना नहीं थी, तब भी भारत प्रगतिशील ट्रैक पर था। प्रोफेसर ने विद्वानों के समूह को "गार्बोलॉजी" के सिद्धांत से परिचित कराया जो जापान में उत्पन्न हुआ था और विलियम रेथ्जे ने पेश किया था। इस सिद्धांत में एक देश की संस्कृति का अध्ययन कचरे की विश्लेषण द्वारा किया जाता है।

प्रोफेसर कट्टीमनी ने फिर उन गलत धारणाओं पर गहराई से गए-जो आदिवासी लोगों को "जंगली" के रूप में दर्शाते हुए उन्हें पिछड़ा माना जाता है। हालांकि, उन्होंने "जंगली कुलोपति की जंगली कथा" जैसी किताब का उद्धरण दिया, जो "जंगली" का अर्थ शुद्ध, स्वच्छ, स्वावलंबी और साथी विकास की प्रवृत्ति वाला होता है। उन्होंने फिर "उबुन्टू" की अवधारणा पेश की, जो भारत में धार्मिक अवधारणा के रूप में मानी जाती है और आदिवासी समुदायों की अनूठी गुणवत्ता को उजागर किया, जो केवल वही खाते हैं जो उन्हें चाहिए और किसी भी संसाधन को बर्बाद नहीं करते हैं। उनकी खपत के इस तरीके को दूसरे समुदायों को सीखना चाहिए।

उपसंहार में प्रोफेसर कट्टीमनी ने बताया कि अमृत काल की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य स्वावलंबन और विकास है, जो केवल सहयोग, अवसंरचना के साझा करने और पुरानी प्रथाओं को छोड़ने के माध्यम से ही संभव होगा। उन्होंने आदिवासी और पिछड़े वर्गों को उठाने और उनके योगदानों को मान्यता देने की महत्त्वता पर भी जोर दिया। अंत में उन्होंने उन आयोजकों का धन्यवाद दिया जिन्होंने उन्हें संगोष्ठी में अपने दृष्टिकोण साझा करने का अवसर दिया।

डॉ. नागेश भंडारी

अध्यक्ष, सिंधु विश्वविद्यालय, अहमदाबाद

डॉ. नागेश भंडारी ने बीते कई वर्षों के दौरान भारतीय ज्ञान प्रणालियों के खंडन पर चर्चा करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा, "हम अपने देश की हज़ारों साल पुरानी परंपराओं और संस्कृतियों को भूल गए हैं। मुगल वर्चस्व और औपनिवेशिक युग सहित कई कारणों से हम अपनी परंपराओं से अलग हो गए हैं, जिसने भारतीय परंपराओं और शिक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।" वे आग्रह करते हैं कि आने वाली पीढ़ियों और भारत के लाभ के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली को उपनिवेश से मुक्त करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी प्रभाव के कारण भारतीय ज्ञान प्रणालियों की जड़ों की खोज से अधिक उनकी विरासत और ज्ञान प्रणालियों पर जोर दिया जाता है। हमें भारतीय दर्शन के साथ हमारी पाठ्यक्रम बहुतायत सम्मिलित करना चाहिए और इतिहास, विज्ञान, संस्कृति आदि तमाम विषयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) के कार्यान्वयन के लिए संभावित रणनीतियों पर चर्चा करते हुए उन्होंने तीन महत्वपूर्ण कदम निर्धारित किए:

- जागरूकता पैदा करना
- शिक्षकों को जोड़ना
- वार्ता, व्याख्यान आदि बनाना।

उपस्थित लोगों को आईकेएस के मिशन के बारे में बताते हुए, डॉ. नागेश ने टिप्पणी की, "इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए समाज के हर हिस्से के लिए काम करना महत्वपूर्ण है।" आईकेएस के व्यावहारिक उपयोग पर अधिक विचार-विमर्श के बाद, उनके अनुसार, संस्था ने वीडियो व्याख्यान एकत्र करना और उन्हें अपनी साइटों पर पोस्ट करना शुरू किया। शिक्षकों ने उन अवधारणाओं के बारे में बच्चों को शिक्षित करना और इन वीडियो के परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम विकसित करना शुरू किया। उन्होंने आगे कहा कि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन से उनकी पहल को और भी अधिक मदद मिलेगी। आईकेएस के व्यावहारिक निहितार्थों में संगीत, कला और नृत्य जैसे विशेष सत्र भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि विषय-विशिष्ट पाठ्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई गई और मॉड्यूल का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय परंपराओं के प्रति छात्रों के दृष्टिकोण में बदलाव आया। डॉ. नागेश ने दावा किया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के इन पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या 4000 से अधिक हो गई है।



तकनीकी सत्र- 3

थीम: उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण

सत्र अध्यक्ष: प्रो. भीमराय मेत्री: निदेशक, भा.प्र.सं. नागपुर

वक्ता: श्री रियूही निशि, प्रथम सचिव (विज्ञान और प्रौद्योगिकी), भारत में जापान के दूतावास,
श्री बलुन्या बार्कर, शिक्षा अताशे, भारत में युगांडा के दूतावास,
श्री यदु नाथ पौडेल: काउंसलर (सांस्कृतिक), भारत में नेपाल के दूतावास



श्री रियूही निशि

श्री बलुन्या बार्कर,

श्री यदु नाथ पौडेल

श्री रयूही निशि

प्रथम सचिव (विज्ञान और प्रौद्योगिकी), भारत में जापान के दूतावास

तीसरे तकनीकी सत्र में सभा को संबोधित करने वाले पहले वक्ता श्री रयूही निशि थे।

उन्होंने भारत के प्रति अपने प्रेम के बारे में सभी को बताकर अपना सम्बोधन शुरू किया। अपनी प्रस्तुति में, उन्होंने अपनी भारत यात्रा के सभी तस्वीरें दिखायीं जब वे एक विश्वविद्यालय के छात्र थे। जापान में वर्षों तक काम करने के बाद, उन्हें भारत में नियुक्त किया गया था और वास्तव में भारत में जापान के दूतावास से एक निवासी सचिव के रूप में भारत वापस आकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उनकी प्रस्तुति का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग के संदर्भ में भारत-जापान संबंधों को उजागर करना था। उन्होंने सर्वप्रथम जापान की समृद्ध संस्कृति की जानकारी दी। उन्होंने जापान से बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रकाश डालते हुए जापान की सॉफ्ट पावर और आर्थिक शक्ति पर जोर दिया। जापान अपने व्यंजनों, एनीमे, विभिन्न मंदिरों आदि के लिए प्रसिद्ध है। श्री निशि ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि भारत और जापान में शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग के प्रयासों की बड़ी कमी क्यों है।

जापान का लक्ष्य शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयास में विदेशों से 30 लाख से अधिक छात्रों का स्वागत करना है। उनके अनुसार जापान एक ऐसा देश है जो विज्ञान के क्षेत्र में कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ तकनीकी कौशल और अनुसंधान के लिए जाना जाता है, और भारतीय और जापानी छात्रों और संकाय के बीच सहयोग इसे और भी उच्च स्तर तक ले जाएगा। श्री निशि ने भारतीय छात्रों को ट्यूशन या कक्षाओं के माध्यम से जापानी भाषा सीखने की पहल करने और जापान में कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने श्रोताओं को JASSO, सकुरा साइंस प्रोग्राम और JSPS स्कॉलरशिप जैसे कार्यक्रमों के बारे में भी बताया, जो विदेशों से छात्रों के लिए जापान में अध्ययन करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन हैं। उन्होंने अंत में जापान और भारत के विषय पर समझ और शोध की कमी और दुनिया की बेहतर समझ के लिए अन्य देशों की संस्कृति और रीति-रिवाजों के अध्ययन और समझ के महत्व पर चर्चा की।

उन्होंने अपनी हताशा और भ्रम व्यक्त किया और उल्लेख किया कि अक्सर लोगों में अन्य संस्कृतियों और देशों के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती है। वे यह भी उल्लेख करते हैं कि जापान की संस्कृति की भारत से तुलना करना उत्पादक नहीं है और अंततः, अन्य संस्कृतियों को सीखना और समझना समग्र ज्ञान और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने जापानी भाषा में सभी को धन्यवाद देते हुए और संस्थागत नेताओं से छात्रों को जापान में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके अपना भाषण समाप्त किया।

श्री बलुन्या बार्कर

शिक्षा अताशे, भारत में युगांडा के दूतावास

श्री बलुन्या बार्कर द्वारा दिया गया व्याख्यान उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और वैश्विक विकास में इसकी भूमिका से संबंधित था। अपनी टिप्पणी में, उन्होंने बताया कि पैनलिस्ट में विविधता एक मंच पर एकजुट थी और "एक व्यक्ति, एक स्थान" पर बल दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयकरण उच्च शिक्षा को उच्च शिक्षा के उद्देश्य, कार्यों और वितरण में एक अंतरराष्ट्रीय, अंतर-सांस्कृतिक, वैश्विक आयाम को एकीकृत करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। बलुन्या जी ने संकेत दिया कि विभिन्न देशों के छात्रों, पाठ्यक्रमों और शिक्षकों के आदान-प्रदान से इस पहल को शुरू करने वाले राष्ट्रों ने अधिक लाभ देखा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने छात्रवृत्ति देना शुरू कर दिया है। भारतीय विश्वविद्यालय विदेशों में भी विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, और कई छात्र इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि लगभग 1500 युगांडा के छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों में हैं और भारतीय प्रोफेसर युगांडा के संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खान-पान और सांस्कृतिक विषमताओं जैसी इसकी चुनौतियों को उजागर करते हुए, यह आंतरिक-करण वैश्विक प्रतिस्पर्धा और नेटवर्क सहयोग को बढ़ाता है। संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न देशों के विभिन्न प्रोफेसरों द्वारा किए गए संयुक्त शोध को वित्तपोषित कर रहे हैं। इन हस्तक्षेपों ने कम आय वाले देशों के शिक्षाविदों की मदद की। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत सरकार सक्रिय है और भारतीय संस्थानों द्वारा प्रचारित पाठ्यक्रमों से यह स्पष्ट है कि भारत अगले दशक में दुनिया से आगे निकल जायेगा।

उन्होंने यह कहकर निष्कर्ष निकाला कि ऑनलाइन कक्षाओं के कारण शिक्षा राष्ट्र की सीमाओं से बंधी नहीं है; और भारत सरकार बुद्धिमानी से इस कार्यक्रम का उपयोग अन्य देशों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने के लिए कर रही है।

श्री यदु नाथ पौडेल

काउंसलर (सांस्कृतिक), भारत में नेपाल के दूतावास

नेपाल दूतावास के श्री पौडेल ने 5 प्रमुख मानदंडों के बारे में बात की, जिस पर उनका सत्र स्तंभित था। वे पांच मानदंड नीचे सूचीबद्ध हैं:

- घरेलू शिक्षा नीति
- संसाधनों का सतत उपयोग
- एनईपी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लाभ
- नेपाल का संदर्भ और उसकी भूमिका
- सामान्य प्रसंग

सबसे पहले, उन्होंने भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में हाल के विकास के बारे में बात की, जो अपने पाठ्यक्रम, शिक्षा की गुणवत्ता और QS रैंकिंग को ध्यान में रखते हुए प्रसिद्ध विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों की स्थापना के लिए तत्पर हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ाने के लिए संकाय और छात्र-विनिमय (student exchange) और प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित करके भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। भारत के संकाय अपने अनुभवों और मॉड्यूल और शिक्षण के तरीकों को नेपाल के संकाय के साथ और इसके विपरीत साझा कर सकते हैं। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य भारत में आधुनिक शिक्षा में सुधार करना और अन्य देशों के साथ शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

यदुनाथ जी ने संस्थानों के बीच साझेदारी की क्षमता और अनुसंधान और राष्ट्रीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लाभों पर प्रकाश डाला। स्पीकर ने उच्च शिक्षा के लिए दूसरे देशों में नेपाली छात्रों के प्रवास और विदेशी छात्रों के लिए अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए भारत की आवश्यकता पर भी चर्चा की। दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को विकसित करने का एक अन्य तरीका अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी हो सकता है, अर्थात् दो पड़ोसियों की विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करना जो राष्ट्र के समग्र विकास में भी मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत नेपाली छात्रों के लिए एक बड़ा केंद्र है, इसलिए भारत को छात्रों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए जैसे उन्हें उपयुक्त छात्रवृत्ति प्रदान करना ताकि वे भारत में आसानी से अध्ययन कर सकें। अपने भाषण का समापन करते हुए, उन्होंने उल्लेख किया कि भारत और नेपाल के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं और निश्चित रूप से आगे भी रहेंगे और वे भारत सरकार की भूमिका को प्रोत्साहित करेंगे कि वे नेपाली छात्रों को एक अभिन्न अंग बनने में सहायता करने के लिए उन्हें मूल्यवान संसाधन प्रदान करें। शिक्षा प्रणाली और अर्थव्यवस्था के सकारात्मक विकास का कारक बनें।

वे कहते हैं कि पार्टनरशिप लीडर्स 2023 के लिए एनएसआईएल समग्र राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा में प्रमुख पहलों पर चर्चा करने के लिए शैक्षणिक समूहों को एक साथ लाना है जो शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण जैसे लिकेज, स्थिरता, अनुसंधान नेतृत्व और राष्ट्रीय विकास के लिए प्रासंगिक हैं। और उन्हें उम्मीद है कि एनएसआईएल 2023 भारत और नेपाल के बीच अकादमिक संबंधों को मजबूत करेगा और छात्रों और शिक्षकों को वैश्विक नागरिक और नेता बनने के लिए तैयार करेगा।

दूसरा दिन

तकनीकी सत्र 4

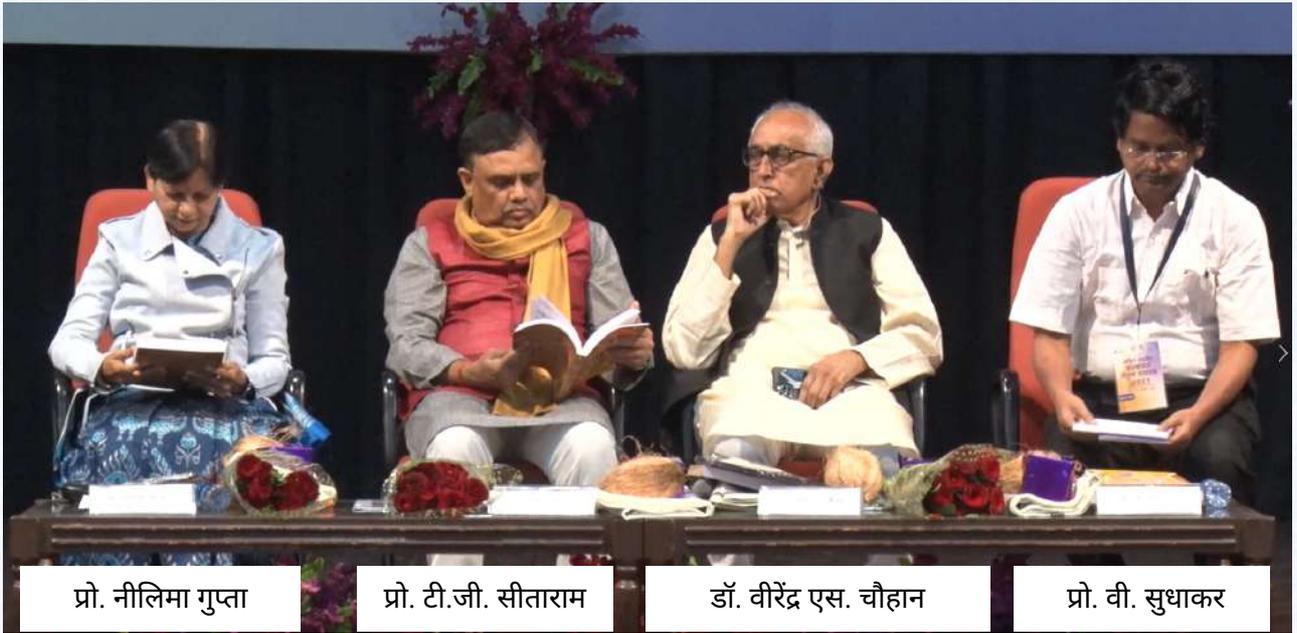
थीम: रिसर्च एंड इनोवेशन

सत्र अध्यक्ष: प्रो. वी. सुधाकर, प्रोफेसर, EFLU, हैदराबाद

वक्ता: प्रो. टी.जी. सीताराम, अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

डॉ. वीरेंद्र एस. चौहान, एमेरिटस वरिष्ठ वैज्ञानिक, आईसीबीजीई

प्रो. नीलिमा गुप्ता, कुलपति, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर



प्रो. टी.जी. सीताराम

अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

प्रोफेसर सीताराम ने अपने शैक्षिक और पेशेवर जीवन के हाइलाइट्स के माध्यम से भारत के अनुसंधान और नवाचार क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों का जिक्र किया। बंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान में 27 वर्षों तक अनुसंधान करने के कैरियर के साथ, उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के निर्देशक के रूप में भी अपनी अवधि का उल्लेख किया। उन्होंने अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय- जीईआरडी के कम हिस्से के बावजूद अनुसंधान में भारत की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी के साथ अपना सम्बोधन शुरू किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भले ही हमारा जीईआरडी दुनिया के सापेक्ष महत्वपूर्ण नहीं है, यह पिछले एक दशक में तीन गुना हो गया है। उन्होंने बात की है कि छात्रों की रुचि का मूल्यांकन करके एक मज़बूत अनुसंधान पारिस्थितिकी का निर्माण किया जा सकता है, जिससे हम वैज्ञानिक-पत्रों और पेटेंटों की संख्या में हमारा हिस्सा बढ़ा सकते हैं। उन्होंने छात्रों में अनुसंधान जागरूकता फैलाने के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण वाली नई शिक्षा नीति, 2020 की सराहना की और किसी विशेष विषय में उत्कृष्ट रुचि रखने वाले छात्रों की पहचान करने की सलाह दी।

उसके बाद, उन्होंने बताया कि कैसे पूरे भारत में आईआईटी आज केवल इंजीनियरिंग कॉलेजों से नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। अपने भाषण का समापन करते हुए, उन्होंने उस भूमिका का उल्लेख किया जो एक संगठन के रूप में एआईसीटीई हमारे अनुसंधान बुनियादी ढांचे के विकास में निभाता है। महामारी के दौरान 28 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और परिणाम-आधारित मॉडल पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, उन्होंने एआईसीटीई के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे एआईसीटीई ने अपने अनुवाद कार्यक्रम के साथ शिक्षा की पहुंच में भी सुधार किया है।

डॉ. वीरेंद्र एस. चौहान

एमेरिटस वरिष्ठ वैज्ञानिक, आईसीबीजीई

डॉ. वीरेंद्र एस. चौहान ने विज्ञान के क्षेत्र की तीन महत्वपूर्ण हस्तियों और उनके विचारों के बारे में बताकर अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने जॉन डेसमंड बर्नाल और उनकी किताब 'द सोशल फंक्शन ऑफ साइंस' (1939) के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बर्नाल ने इतिहास में विज्ञान की भूमिका पर लिखा है और उनको उद्धृत करते हुए कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान का उपयोग समाज की ओर निर्देशित होना चाहिए। जिस दूसरे व्यक्ति के बारे में उन्होंने बात की, वह माइकल पोलानी थे। पोलानी भौतिक रसायन, अर्थशास्त्र और फिलॉसफी के विद्वान थे। उन्होंने इस बारे में बात की कि विज्ञान तब सफल होता है जब वैज्ञानिकों को वह करने की अनुमति दी जाती है जो वे करना चाहते हैं। पोलानी का उल्लेख करते हुए, डॉ. चौहान ने इस बारे में भी बात की कि कैसे कभी कभी विज्ञानवाद विषैला हो सकता है और मनुष्य के रूप में हमारी उपलब्धियों को कमजोर कर सकता है। उनके द्वारा बताये गए तीसरे व्यक्तित्व का नाम ट्रॉफिम लिसेंको था, जो एक सोवियत कृषि विज्ञानी और जीवविज्ञानी थे। लिसेंको को मंडेलियन आनुवंशिकी की अस्वीकृति के लिए जाना जाता है, और कैसे कम्युनिस्ट चीन ने 1950 के दशक के अंत में उनके तरीकों का पालन किया, जिससे बड़े अकाल पड़े।

तदपश्चात् डॉ. चौहान ने मुख्य रूप से अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में खर्च की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भले ही भारत अनुसंधान और विकास के लिए आवंटित राशि का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम रहा हो, लेकिन 0.7% का योगदान अपने आप में पर्याप्त नहीं है। देश में जो शोध होता है वह बिखरा हुआ होता है और इसे उचित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता होती है, और इसलिए, उन्होंने प्रतिभागियों से विश्वविद्यालय स्तर पर इस मुद्दे को संबोधित करने का आग्रह किया।

प्रो. नीलिमा गुप्ता

कुलपति, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

प्रोफेसर नीलिमा ने इस शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को बधाई और धन्यवाद देकर अपना भाषण शुरू किया। वह इस तथ्य में प्रबल विश्वास रखती हैं कि अनुसंधान और नवाचार एक साथ जुड़े हुए हैं, और यह मानव मन की जिज्ञासु प्रकृति है जो अधिक से अधिक नवाचार को बढ़ावा देगी। वह पुष्टि करती हैं कि अनुसंधान और विकास हमारे देश की प्रगति के लिए आवश्यक हैं और हमें इस शोध का व्यवसायीकरण करने और इसे बाजार में लाने के तरीके विकसित करने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति के बारे में बोलते हुए और किस प्रकार यह हमारे देश में अनुसंधान एवं विकास को गति प्रदान करेगी, उन्होंने यूजीसी के स्ट्राइड (STRIDE), आईजीएसटीसी (IGSTC), आदि सहित हमारे देश में उपलब्ध विभिन्न अनुसंधान निधियों का उल्लेख किया। उन्होंने भारत के अनुसंधान और विकास क्षेत्र में कैरियर जागरूकता के बारे में भी बात की। और कैसे भारतीय विश्वविद्यालयों को हमारे देश में अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए, उस पर निर्देश दिया।

जब भारत की बात आती है तो उन्होंने विशेष रूप से अनुसंधान एवं विकास में लैंगिक अंतर की ओर इशारा किया। रेखांकन के माध्यम से, उन्होंने दिखाया कि शोध प्रकाशन विद्वानों के बीच कितना बड़ा अंतर है। उन्होंने यह भी बताया कि भले ही अंतर अभी भी है किन्तु यह कम हो रहा है। महिला वैज्ञानिक योजना, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिला भागीदारी (WISER), ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए जेंडर एडवांसमेंट (GATI), किरण (KIRAN) आदि कुछ योजनाएं हैं जिनका डॉ. नीलिमा ने अपने संबोधन में उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) श्रम शक्ति में 29% महिलाएं हैं, एसटीईएम (STEM) कंपनियों में बोर्ड के सदस्यों के रूप में हिस्सेदारी घटकर 19% हो जाती है और एसटीईएम (STEM) उद्योग में सीईओ के पद के लिए 3% हो जाती है।

डॉ. गुप्ता ने अनुसंधान एवं विकास में भारत के अल्प योगदान पर भी प्रकाश डाला, जो सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% हिस्सा ही है। यह बेहद कम हिस्सा भारत के अनुसंधान और विकास के उत्थान में एक बाधा है।

तकनीकी सत्र- 5

थीम: नेतृत्व और शासन

सत्र अध्यक्ष: प्रोफेसर केबी दास, कुलपति, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय

वक्ता: प्रो. सी. राजकुमार, कुलपति, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत

प्रो. एस. वैद्यसुब्रमण्यम, कुलपति, शास्त्र विश्वविद्यालय, तंजावुर

प्रो. योगेश सिंह, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय



प्रो. सी. राजकुमार,



प्रो. एस. वैद्यसुब्रमण्यम



प्रो. योगेश सिंह

प्रो. सी राज कुमार

कुलपति, ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत

प्रोफेसर कुमार ने विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान को एक ऐसा मंच प्रदान करने के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद देते हुए अपना संबोधन शुरू किया जो नेतृत्वकर्ताओं को अपने विचारों को इकट्ठा करने और साझा करने की अनुमति देता है। उनके संबोधन का विषय उच्च शिक्षा में नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसका शिक्षा के क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह नासा केंद्र में हुई थी, जो नेतृत्व की आंतरिक प्रकृति को दर्शाती है। कहानी एक चौकीदार के बारे में थी, जब वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जे. एफ. कैनेडी से मिला, उसने खुद को नासा में एक नेता और सूत्रधार के रूप में पेश किया। चौकीदार ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ रखकर उन्होंने वैज्ञानिकों को अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की, जिससे नासा के मिशन में योगदान मिला। यह स्वयं के नेतृत्व गुणों को पहचानने और हितधारकों के लाभ के लिए उनका उपयोग करने के महत्व पर जोर देता है। उनकी राय में, शैक्षिक नेतृत्वकर्ताओं में असाधारण अकादमिक उत्कृष्टता होनी चाहिए, छात्रों के लिए रोल मॉडल के रूप में काम करना चाहिए, सभी हितधारकों से सक्रिय रूप से भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए और नए नेतृत्वकर्ताओं को बनाने में भूमिका निभानी चाहिए। प्रक्रियाओं के लिए एक सुव्यवस्थित, कम नौकरशाही दृष्टिकोण और बढ़ी हुई व्यस्तता से शैक्षणिक संस्थानों के लिए तेजी से विकास और उत्थान हो सकता है। प्रोफेसर ने समय से दो कदम आगे रहने के लिए नेतृत्वकर्ताओं द्वारा परिवर्तन को गले लगाने और नवाचार को गले लगाने की आवश्यकता के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि शैक्षिक नेतृत्वकर्ताओं को नए विचारों और तकनीकों की खोज के लिए तैयार रहना चाहिए, और भविष्य की चुनौतियों का अनुमान लगाने में सक्रिय होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि, आज की तेजी से चलती और लगातार बदलती दुनिया में, नेताओं को अपने छात्रों और हितधारकों की जरूरतों का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए और तदनुसार अपनी नेतृत्व शैली को अपनाना चाहिए। प्रोफेसर ने नेतृत्व में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता के बारे में भी बताया। उन्होंने नेतृत्वकर्ताओं के अपने फैसलों, नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में पारदर्शी होने और अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा, यह हितधारकों के साथ विश्वास बनाता है, और शैक्षणिक संस्थान के भीतर एक सकारात्मक और सहयोगी वातावरण को बढ़ावा देने में मदद करता है।

प्रो. एस वैद्यसुब्रमण्यम

कुलपति, शास्त्र विश्वविद्यालय, तंजावुर

श्री वैद्यसुब्रमण्यम ने एक शैक्षिक संस्थान को आकार देने में नेतृत्व और शासन के महत्व पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए वीबीयूएसएस और डीएवीवी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना संबोधन शुरू किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उदय ने हाल के दिनों में युवा पीढ़ी और कामकाजी पेशेवरों दोनों के काम को आसान बना दिया है। लेकिन वह उसके बहुत बड़े समर्थक नहीं हैं। सत्र का मुख्य विषय नेतृत्व और शासन होने के कारण, उन्होंने सीधे इस विषय पर आगे बढ़कर सभी को संबोधित किया और बताया कि नेतृत्व और शासन के विभिन्न मॉडलों को कैसे परिवर्तित करने की जरूरत है, जो सभी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए उभरता हुआ आविष्कार है। इसलिए, इन परिवर्तनात्मक परिवर्तनों को समझाने के लिए, पहले व्यक्तिगत और संस्थात्मक स्तर पर एक कुशलता बोर्ड की आवश्यकता है। इस मॉडल के माध्यम से, उन्होंने यह व्यक्त किया कि अगली पीढ़ी को वैश्विक नेता बनाने के लिए भारत को व्यक्तियों और संस्थाओं से निरंतर योगदान की आवश्यकता है। ये निरंतर प्रयास उचित शैक्षणिक नेतृत्व कौशल्य विकसित करने में मदद करेंगे।

आगे बढ़ते हुए, उन्होंने समझाया कि प्रभावी नेतृत्व विकसित करना एक-चरणीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण श्रृंखला प्रक्रिया है, जिसमें संस्थान एक मूल्य-श्रृंखला के रूप में होते हैं। इसके लिए उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रभावी मॉडल के रूप में माइकल पोर्टर के 'वैल्यू ऑफ चैन' मॉडल का उदाहरण दिया। किसी संस्था को एक मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए, विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं जो खेल में आती हैं। पोर्टर के मॉडल में उल्लिखित चार महत्वपूर्ण प्राथमिक गतिविधियाँ हैं:

- आयातित रसद (Inbound logistics)
- संचालन (operations)
- बहिरगामी रसद (Outbound logistics)
- विपणन और बिक्री (marketing and sales)

इनके अलावा अन्य सहायक गतिविधियाँ, जिनकी देखभाल करने की आवश्यकता है वे नीचे सूचीबद्ध हैं:

- मजबूत अवसंरचना
- मानव संसाधन
- प्रौद्योगिकी विकास

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक शैक्षिक संस्थान के विकास के लिए प्राथमिक और सहायक गतिविधियों का संयोजन आवश्यक है। उन्होंने संस्थानों को मूल्यों के सुपरसेट के रूप में परिभाषित किया और स्थिरता और प्रतिकृति के बीच मजबूत कड़ी पर जोर दिया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने समझाया कि व्यक्ति और उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका/ रोल के बीच घनिष्ठ एकीकरण होता है। उन्होंने प्रभावकारिता के अर्थ को भी समझाया कि वह तब उत्पन्न होता है जब किसी संगठन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की संभावित प्रभावशीलता बढ़ जाती है। इस समग्र प्रभाव को भी दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है अर्थात व्यक्तिगत प्रभाव और भूमिका का प्रभाव। व्यक्तिगत प्रभाव किसी व्यक्ति की संभावित प्रभावशीलता है और भूमिका का प्रभाव किसी व्यक्ति पर किसी विशेष भूमिका की संभावित प्रभावशीलता है।

भूमिका के प्रभावकारिता की अवधारणा पर जोर देने और उसे बढ़ाने के लिए उन्होंने सभा को तीन आयामों से परिचित कराया:

- भूमिका सृजन बनाम भूमिका ग्रहण
- भूमिका केंद्रित/बुनियादी भूमिका समझना बनाम भूमिका में प्रवेश
- भूमिकाओं का परस्पर समायोजन बनाम भूमिका का संकुचन

1. **भूमिका सृजन आयाम:** उन्होंने रोल-मेकिंग आयाम को चार बिंदुओं की मदद से समझाया जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

- **स्व-भूमिका एकीकरण:** स्व-भूमिका एकीकरण में दो उप-भाग शामिल होते हैं जो भूमिका निभाने वाले व्यक्ति और उस भूमिका के तहत किए गए कार्य होते हैं। यह एकीकरण भूमिका में व्यक्तिगत ताकत का उपयोग करने और उच्च प्रभावकारिता उत्पन्न करने के अधिक अवसरों को बढ़ावा देने में मदद करता है।

- **सक्रियता:** सक्रियता में तत्काल कारणों को पार करने के लिए पहल करना शामिल है। उन्होंने प्रतिक्रियाशील और सक्रिय होने के बीच के अंतर को भी समझाया। प्रतिक्रियाशील होना दूसरों की अपेक्षाओं का जवाब देना है जबकि सक्रिय होना दूसरों की अपेक्षाओं का अनुमान लगाना है।
- **रचनात्मकता:** रचनात्मकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे किसी व्यक्ति की भूमिका विकसित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक संस्थान तेजी से उन्नति कर सकता है यदि उसके पास एक रचनात्मक नेतृत्वकर्ता है जो अलग हटकर सोचने की क्षमता रखता है और सीमित संसाधनों और स्रोतों तक बद्ध नहीं है। एक नेतृत्वकर्ता ऐसा होना चाहिए जो विस्तृत कार्यों को संभालता हो और सामान्य रूटीन से हटकर संस्थान से सर्वोत्तम नतीजे प्राप्त करने के लिए एक अलग मार्ग अपनाता हो।
- **टकराव:** एक संस्थान तब विकसित हो सकता है जब उसके पास एक ऐसा नेतृत्वकर्ता हो जो विकास के रास्ते में आने वाली समस्याओं का सामना करने या संस्थान के विकास के लिए निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। इसलिए संस्था में नेतृत्व और शासन को बढ़ाने के लिए समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए और उनका बचाव करने या उनसे बचने के बजाय समाधान निकालना चाहिए।

उन्होंने श्रोताओं को एक स्लाइड भी दिखाई जिस में रचनात्मकता समस्याओं का समाधान खोजने का एक तरीका था। उन्होंने ब्लू-ओशन रणनीति (Blue Ocean Strategy) की व्याख्या की, जिसमें किसी की रचनात्मक बुद्धि का लाभ उठाकर अस्पष्टीकृत विकल्पों की खोज करना शामिल है।

2. भूमिका केंद्रित आयाम: प्रोफेसर ने भूमिका केंद्रित आयाम को तीन उप-भागों की मदद से समझाया, वे इस प्रकार थे:

- **केंद्रीयता:** उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी संगठन में कोई भूमिका छोटी या बड़ी नहीं होती। अर्थात जब किसी संगठन में भूमिका निभाने की बात आती है तो चौकीदार सीईओ के बराबर होता है यानी जो भूमिका और जिम्मेदारियां दी जाती हैं उन्हें एक ही तरह से पूरा करने और सराहना देने की आवश्यकता होती है।
- **प्रभाव:** उन्होंने समझाया कि एक नेता का प्रभाव संगठन की रूपरेखा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगठन में एक प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता का होना वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उस के कार्य, कार्यबल के कार्यों को प्रभावित करते हैं।
- **व्यक्तिगत विकास:** एक नेता को अपने साथी कार्यकर्ताओं के लिए भी विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए क्योंकि "नेतृत्व एक सीखने और विकास के अवसर के रूप में होना चाहिए न कि एक स्थिर बिंदु के रूप में।"

3. भूमिकाओं का परस्पर समायोजन:

- **भूमिकाओं के मध्य सम्बन्ध स्थापित करना:** प्रोफेसर का मानना है कि उच्च शिक्षा संस्थान पूरी तरह से भूमिकाओं का एक नेटवर्क है और आज के युग में जितना अधिक आप नेटवर्क बनाते हैं उतना ही आप अपनी निवल संपत्ति में वृद्धि करते हैं।
- **सहायक संबंध:** उच्च शिक्षा संस्थान एक खुला स्रोत समुदाय है जो समाज के साथ आउटसोर्सिंग संबंधों को विकसित करने में मदद करता है। यह व्यक्तिगत स्तर पर एक लेन-देन संबंध विकसित करने में मदद करता है जो भूमिका-विशिष्ट है।
- **अधिष्ठापन:** यह परिप्रेक्ष्य की एक बड़ी तस्वीर पेश करने को संदर्भित करता है जो अधिक विस्तृत और आत्म-व्याख्यात्मक है।

सत्र का समापन करते हुए, प्रोफेसर वैद्यसुब्रमण्यम ने बताया कि उच्च संस्थागत स्तर पर, व्यक्तिगत और भूमिका दोनों के विकास की आवश्यकता होती है, जिस के चार अवयव हैं।

- पहला है 'दोहराव', जिसका अर्थ है पुराने व्यवहार को जारी रखना;
- दूसरा 'अवशोषण', मतलब जो दूसरे कर रहे हैं उसे आत्मसात करना;
- तीसरा 'दृढ़ संकल्प' यानी एक कठोर व्यवहार बनाना; और
- अंतिम एक अन्वेषण है जिसका अर्थ है नई चुनौतियों का सामना करना सीखना।

बहुत सारे ऐसे मॉडल पेश किए गए हैं जो वैश्विक शासन की देखभाल करते हैं, जो भारत और चीन को बहुत उच्च शैक्षणिक संस्थान पारिस्थितिकी तंत्र वाले देशों के रूप में भी पहचानते हैं। भारत ने हमेशा मिक्स-मैच दृष्टिकोण या संस्थागत डोमेन से बचने का पालन किया है और हमेशा नीति, प्रक्रिया और लोगों के बीच एक सुसंगत तालमेल स्थापित किया है। इसके साथ, उन्होंने अपना बहुमूल्य भाषण समाप्त किया और एक बार फिर आयोजकों को उन्हें आमंत्रित करने और उन्हें अपनी राय साझा करने के लिए धन्यवाद दिया।



प्रो. योगेश सिंह

कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय

श्री योगेश सिंह जी ने अपने सम्बोधन की शुरुआत आयोजकों को उन्हें यह मूल्यवान और अभिज्ञात मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देकर की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी भूमिका का वर्णन करते हुए बताया कि इसे उनके पेशेवर करियर में एक बहुत ही प्रशंसनीय काम के रूप में माना जाता है और किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के कुलपति होना एक गहन नेतृत्व और जिम्मेदारी का मामला होता है। उन्होंने कहा कि चूंकि उन्हें यहां नेतृत्व और शासन के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया है, इसलिए वे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर शुरुआत करना चाहेंगे, जो है कि- नेतृत्व और शासन क्या हैं?

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने शासन को प्रशासन की एक प्रणाली या उपकरण के रूप में और नेतृत्व को शासन के गठन में एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने नेतृत्व की अवधारणा पर विशेष महत्व दिया क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास है कि कुशल नेतृत्वकर्ता प्रभावी सफलता बनाने में मदद करते हैं। उसे टीम को आशा और आकांक्षा देनी चाहिए और टीम के बीच आत्मविश्वास और भरोसा पैदा करना चाहिए।

उन्होंने वर्णन किया कि एक नेतृत्वकर्ता दो प्रकार के दृष्टिकोण रख सकता है:

- जब भी वे इस मानसिकता के साथ जुड़ते हैं कि वे सिस्टम को क्या प्रदान कर सकते हैं, तो उनके कार्य - 'देने वाली प्रकृति' के होंगे।
- दूसरी मानसिकता यह हो सकती है कि वह सिस्टम से क्या ले सकता है तो उनके कार्य विपरीत होंगे यानी वे सिस्टम को देने के बजाय हमेशा सिस्टम से 'प्राप्त करना' चाहेंगे।

उन्होंने अधिवेशन में उपस्थित गणमान्यजन से पहली श्रेणी की मानसिकता का नेतृत्वकर्ता बनने का आग्रह किया जिसे सुशासन के सिद्धांत के रूप में भी लिया जाता है। उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध कहावत दी- "भगवान उसी व्यक्ति को शक्ति और कर्तव्य देते हैं, जो दृढ़ और मजबूत होता है और उनकी समस्या में व्यक्ति के साथ होता है"। आगे बढ़ते हुए उन्होंने वर्णन किया कि कैसे चार सी (Cs) नेतृत्व और शासन के एक महत्वपूर्ण तत्व बन गए हैं:

- Communication/ संचार
- Courage/ साहस
- Commitment/ प्रतिबद्धता
- Compassion/ करुणा

इन चार तत्वों के महत्व को समझाने के लिए, उन्होंने इन चार मापदंडों पर एडॉल्फ हिटलर और अब्राहम लिंकन के बीच तुलना की। उन्होंने बताया कि कैसे एडॉल्फ हिटलर संचार, साहस और प्रतिबद्धता में एक आदर्श व्यक्ति था, जबकि अब्राहम लिंकन इन विशेषताओं में औसत थे। लेकिन जब करुणा की बात आई तो हिटलर 0/10 थे जबकि लिंकन करुणा में 9/10 थे। इस तुलना के माध्यम से उन्होंने बताया कि करुणाविहीन नेता खतरनाक होता है। एक नेता होने के नाते आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं और यदि आप दयालु नहीं हैं तो आप अपनी टीम को वितरित नहीं कर सकते। एक मार्गदर्शक की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, उसे निर्णय लेने में निर्भीक होना चाहिए। एक अच्छा नेता वह है जो सुनता है और सभी से सलाह लेता है लेकिन जब निर्णय लेने की बात आती है तो वह सभी मापदंडों को ध्यान में रखता है और फिर अपने विवेक से निर्णय लेता है।

एक अच्छा नेतृत्वकर्ता होने की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उन्हें अपनी बातों का पालन करना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। नेतृत्व का असली सार तब महसूस होता है जब वह तूफान में भी मजबूत खड़ा होता है, इस बात की चिंता किए बिना कि उनका क्या होगा, बल्कि अपनी टीम की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। उन्होंने कहा, "महान नेतृत्व और अधिष्ठान के साथ, बड़ी जिम्मेदारी आती है, इस प्रकार एक नेतृत्वकर्ता को इन जिम्मेदारियों को गहराई से समझना चाहिए" उन्होंने कहा। इस कथन के साथ, वह इस तथ्य को संबोधित करना चाहते थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े हो जाते हैं, या आप किसी संस्था में एक मार्गदर्शक के रूप में कितने उच्च पद पर हैं, आपको हमेशा अपने मूल्यों पर टिके रहना चाहिए।

एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता होने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कारक यह है कि हमें अपने मानसिक क्षितिज को व्यापक बनाने की आवश्यकता है और संख्याओं के बजाय गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देना शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता संख्या में नहीं, लोगों में है, इसलिए आसपास के सभी लोगों पर ध्यान केंद्रित करें। अतएव जरूरी है कि गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू किया जाए, संख्या अपने आप बढ़ जाएगी।

एक अच्छे नेतृत्वकर्ता में धन्यवाद देने का गुण होना चाहिए अर्थात् परिणाम देने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करना और दूसरों के काम की सराहना करना चाहिए। यह टीम के बीच टीमवर्क और आत्मविश्वास बनाने में मदद करता है और टीम को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हमें प्रशंसा और अच्छाई की शक्ति विकसित करने की आवश्यकता है। यह सकारात्मक परिणाम और सफलता लाने में मदद करता है।

उनका कहना है कि अगर कोई नेतृत्वकर्ता अपनी टीम या लोगों के बड़े दायरे में निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, तो वह वो परिणाम नहीं दे पाएगा जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है। कड़ी मेहनत, निरंतरता और कभी हार न मानने का रवैया है जो जो एक व्यक्ति का एक कुशल मार्गदर्शक के रूप में आकार देता है। किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान का नेतृत्व करने से आपके और आपके फैसलों के खिलाफ जाने वाली एक बड़ी आबादी आपके पास आती है लेकिन हमेशा याद रखें कि एक हवाई जहाज हवा के विपरीत दिशा में उड़ान भरता है न कि उसके साथ। इसलिए जब सब कुछ आपके खिलाफ जाने लगे, विरोध की उस हवा का उपयोग अपनी शक्ति के रूप में करें। यही वह समय है जब किसी को अपनी क्षमता और प्रयासों को बढ़ाने और सर्वोत्तम परिणाम देने की आवश्यकता होती है।

उपसंहार में, योगेश जी ने चार्ल्स मॉरिस की एक सुंदर पंक्ति को उद्धृत किया, "मैं एक भेड़ के नेतृत्व वाली 100 शेरों की सेना की तुलना में एक शेर के नेतृत्व वाली 100 भेड़ों की सेना से अधिक डरता हूँ"। उन्होंने समझाया कि यह एक नेतृत्वकर्ता की शक्ति है। यदि वह अपनी टीम के सामने मजबूती से खड़ा होता है, टीम भी बिना शर्त काम करने और सर्वोत्तम परिणाम देने के लिए प्रेरित महसूस करती है और एक अच्छा नेतृत्वकर्ता हमेशा अपने शासन की एक प्रणाली बनाता है और मौजूदा प्रणाली में सुधार, संशोधन और निर्णय लेने पर भी काम करता है। वक्ता ने शैक्षिक संस्थानों को आकार देने में नेतृत्व और शासन पर अपने विचार साझा करने के अवसर के लिए वीबीयूएसएस और डीएवीवी को धन्यवाद देते हुए अपना संबोधन समाप्त किया।



समानांतर सत्र 2

समूह 1: विचारों का आदान प्रदान

सत्र अध्यक्ष: डॉ रेणु जैन, वी.सी , देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी), इंदौर



प्रो. आलोक कुमार चक्रवाल

प्रो. बी.आर. शर्मा,

डॉ रेणु जैन,

कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

डॉ रेणु जैन ने उच्च शिक्षा संस्थानों की सभा में मुख्य भाषण दिया, उन्होंने इन संस्थानों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अतिथियों का स्वागत किया और मध्यप्रदेश में शिक्षा क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने में सहयोग की भूमिका पर प्रकाश डाला। वक्ता ने सभी संस्थानों को एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जो नवाचार को बढ़ावा देगा और छात्रों को वर्तमान नौकरी बाजार के लिए प्रासंगिक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। डॉ रेणु ने शिक्षा क्षेत्र के विकास का समर्थन करने के लिए नई आर्थिक नीतियों को अपनाने के महत्व पर भी जोर दिया और मध्य प्रदेश को ऐसा करने वाला पहला राज्य बताया। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अद्वितीय बिक्री प्रस्तावों (यूएसपी) की पहचान करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ रेणु के भाषण ने शिक्षा क्षेत्र में हितधारकों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की, और उनकी सिफारिशें इस क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए विचार करने योग्य हैं।

प्रो. बी.आर. शर्मा,

कुलपति, श्री श्री विश्वविद्यालय, ओडिशा

प्रोफेसर शर्मा ने “भारतीय ज्ञान प्रणाली में भारतीय उच्च शिक्षा की जड़” के विषय पर एक व्याख्यान दिया। उन्होंने भारत में समग्र अनुसंधान और शिक्षा के लिए एक एकीकृत प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अपनी प्रस्तुति में एमबीबीएस कार्यक्रम में योग को शामिल कर उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया कि कैसे योग उनके चिकित्सा पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसने किस प्रकार छात्रों को मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान की बेहतर समझ विकसित करने में मदद की है। प्रोफेसर शर्मा ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से उनके एकीकृत अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली के विकास में मदद करने के लिए अनुदान की भी अपील की। उन्होंने जोर दिया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली पारंपरिक ज्ञान के अलावा अधिक अन्तर्विषयक अध्ययन और शोध के लिए हमें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए।

अंत में, उन्होंने यूनिवर्सिटी द्वारा पेश किए गए "शांति अध्ययन" कोर्स का जिक्र किया जो छात्रों को समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने का उद्देश्य रखता है।

प्रो. आलोक कुमार चक्रवाल

कुलपति, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर

प्रोफेसर चक्रवाल ने अच्छी तरह से स्नातक ग्रेजुएट्स को तैयार करने के तरीके पर अपने विचार साझा किए। उनके विचार में, छात्रों के लिए समग्र शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। और अच्छी तरह से स्नातक ग्रेजुएट्स को तैयार करने के लिए एक समग्र शिक्षा दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण में छात्रों को अकादमिक, सामाजिक और भावनात्मक सीख के सहित अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना शामिल है। उनका मानना है कि संज्ञानात्मक और गैर- संज्ञानात्मक कौशल दोनों पर ध्यान केंद्रित करने से छात्रों को अच्छी तरह से संपूर्ण व्यक्तियों में विकसित होने में मदद मिल सकती है।

पूर्ण विकसित स्नातक तैयार करने का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अंतःविषय शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इसमें एक पाठ्यक्रम या परियोजना में कई विषय शामिल हैं, जो छात्रों को जटिल मुद्दों की अधिक व्यापक समझ विकसित करने में मदद कर सकता है। प्रोफेसर चक्रवाल ने छात्रों को उनके चुने हुए क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। इसमें इंटरशिप, को-ऑप प्रोग्राम या रिसर्च प्रोजेक्ट शामिल हो सकते हैं। उनका मानना है कि हैंड्स-ऑन अनुभव छात्रों को महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने और उनके भविष्य के करियर में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

प्रो. पी. एस. शुक्ला,

कुलपति, एन.ई.एच.यू. शिलांग

प्रोफेसर शुक्ला ने विश्वविद्यालय को उद्भावना का क्षेत्र बताया जिस में हम आदिवासी शिक्षा पर बल दे सकते हैं और कोडिंग और कंप्यूटर में संस्कृत का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों को रचनात्मकता; नवाचार को बढ़ावा देने; जनजातीय शिक्षा का उपयोग सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने; समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देने के लिए, ज़रूरी वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने प्रोग्रामिंग भाषाओं के विकास में संस्कृत का उपयोग करने की दक्षता और प्रभावशीलता पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली को हमेशा शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए था ताकि छात्रों को देश की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत की सराहना करने में मदद मिल सके। प्रोफेसर शुक्ला के विचार सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए रचनात्मकता और समावेशिता को बढ़ावा देने और छात्रों को शिक्षित करने के लिए अभिनव दृष्टिकोण का उपयोग करने पर केंद्रित हैं। आदिवासी शिक्षा, संस्कृत और आईकेएस के महत्व पर उनका विस्तृत वक्तव्य भारतीय संस्कृति और ज्ञान की समृद्धि में उनके विश्वास को दर्शाता है।

समानांतर सत्र 2

समूह 2: विचारों का आदान प्रदान

सत्र अध्यक्ष: प्रो.भरत शरण सिंह, अध्यक्ष, निजी शुल्क नियामक आयोग



प्रो. भरत शरण सिंह

डॉ. गौरीशा जोशी

प्रो. मधुलिका कौशिक

प्रोफेसर भरत शरण सिंह

अध्यक्ष, निजी शुल्क नियामक आयोग

प्रोफेसर भरत एक प्रसिद्ध जीवविज्ञानी, एक स्थापित शिक्षाविद और प्रशासक हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में बड़े पैमाने पर प्रकाशित किया है। एनईपी 2020 के प्रकाश में, प्रोफेसर भरत ने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक - इंडिया 2020 - ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम को याद करते हुए शुरुआत की। उन्होंने कहा कि, उस समय डॉ. कलाम को नहीं पता था कि 2020 में क्या होगा, लेकिन उनके पास एक विज़न था। उस पुस्तक में, उन्होंने आंतरिक संस्थागत विकास और मुख्य रूप से बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों, कुलपतियों और प्रोफेसरों की भागीदारी सहित विभिन्न विचारों को साझा किया, जिनमें से सभी इस समिति में शामिल हैं। प्रोफेसर भरत ने डॉ कलाम के बारे में एक आवश्यक संदर्भ का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि एक बार, जब वह कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ भोजन कर रहे थे, तो रॉकेट के बारे में बातचीत शुरू हुई, और उन्होंने एक रॉकेट तकनीक का उल्लेख किया जो 1000 साल पहले चीन से आई थी और 13 वीं शताब्दी में भारत में इस्तेमाल की गई थी। बिना किसी संदर्भ के उन्होंने चीन को बातचीत में ला दिया। उन्होंने कहा कि वे बाद में एक संदर्भ देंगे, और कुछ समय बाद, एक कार्यक्रम में, उन्होंने सर बर्नार्ड लोवेल द्वारा लिखित पुस्तक - “द ओरिजिन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन” प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस किताब में पढ़ा कि वास्तव में इस तकनीक का इस्तेमाल भारत में सबसे पहले श्रीरंगपट्टनम में किया गया था। उन्होंने कहा कि हमारी औपनिवेशिक मानसिकता, हीनता की भावना हमारे बुद्धिजीवियों के मन में घर कर गई है कि जब कुछ अच्छा होता है तो हम उसका श्रेय लेने से कतराते हैं। हममें आत्मविश्वास की कमी है, भले ही इसका कोई कारण न हो। इसलिए, हमें इस गहरी औपनिवेशिक मानसिकता से छुटकारा पाने की जरूरत है।

प्रोफेसर भरत कहते हैं कि हम वही बुद्धिजीवी हैं जो अगली पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं और आईकेएस ऐसा करने का एक तरीका है। 2047 में जब सदी पलटेंगी तो भारत किसके हाथ में होगा? और जो लोग इसे धारण करेंगे उन्हें आज ही तैयार रहने की आवश्यकता है। हमें अपने कैपस और परिसरों को इस तरह से बनाने की जरूरत है कि वे हमारे छात्रों को बेहतर दिशा की ओर ले जाएं।

प्रो. मधुलिका कौशिक

उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, रांची

अपने सम्बोधन कि शुरुआत प्रोफेसर मधुलिका ने आयोजकों को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए की। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि उनका विश्वविद्यालय हाल ही में स्थापित किया गया है और एनईपी को एक साल पहले ही पेश किया गया है, इसलिए जल्द ही परिणाम साझा किए जाएंगे।

उन्होंने साझा किया कि वे शुरू से ही क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम प्रारूप, क्रेडिट हस्तांतरण, मिश्रित शिक्षा प्रणाली-फ्लिप क्लासरूम, बहु-प्रवेश व निकास बिंदु जैसे एनईपी-2020 पहलों को लागू कर रहे हैं। उनके पास एक छात्र सुझाव-प्रतिक्रिया तंत्र

और एक शिक्षक स्व-मूल्यांकन तंत्र है, जिसे वे तुलना करते हैं और शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग करते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के नए उपकरणों जैसे ओईआर, एमओओसी, और नए शिक्षाविदों पर संकाय क्षमता निर्माण और अनुदान के माध्यम से अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। इसके बाद उन्होंने अगले दो वर्षों के लिए अपनी कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत की। इसके हिस्से के रूप में इनक्यूबेशन और नवाचार केंद्र को सक्रिय करना, ओईआर (ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज) और स्वयं संसाधनों का अनुकूलन, अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रयास और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना और दोहरी डिग्री प्रावधान की तैयारी करना। उन्होंने आगे कहा कि एनईपी का लक्ष्य उन छात्रों को विकसित करना है जो गंभीर रूप से सोच सकते हैं और 21 वीं सदी में समस्याओं को हल कर सकते हैं और ओईआर स्व-निर्देशित सीखने को प्राप्त करने में सहायता करता है। उनके पास एक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल है, हालांकि, उन्होंने अपने संकायों का मूल्यांकन करने के लिए दोनों प्रथाओं के लिए अलग-अलग मानदंड देने के लिए अपने मिश्रित सीखने और औद्योगिक समर्थन सीखने के लिए आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन (आईक्यूए) प्रथाओं को लागू किया है। उन्होंने बताया कि वे नए और मौजूदा छात्रों दोनों के लिए कई प्रवेश बिंदुओं की पेशकश करने की इच्छा रखते हैं, और अनेक निकास बिंदुओं की स्थापना भी करने की योजना है, ताकि वे उनकी विविध आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

डॉ. गौरीशा जोशी

प्रोफेसर और निर्देशक सेंटर फॉर एजुकेशन एंड सोशल स्टडीज, बेंगलुरु

जैसा कि चाणक्य विश्वविद्यालय की स्थापना 2022 में हुई थी, इसलिए इसे एक एनईपी विश्वविद्यालय के रूप में निर्धारित किया गया था, और उन्होंने कॉलेज की योजना में एनईपी के मूल सिद्धांतों का पालन करने की कोशिश की। प्रोफेसर गौरीशा जोशी ने अपने संस्थान में एनईपी के लागू करने के अपने अनुभवों को साझा करना शुरू किया। साथ ही, वे अपने विश्वविद्यालय में सभी पहलुओं में एनईपी का लागू होने की इच्छा रखते हैं। वे 'लिबरल आर्ट्स' दृष्टिकोण का उपयोग करके अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक समग्र शिक्षा दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं। उन्होंने बहु-एंट्री-एक्जिट प्वाइंट्स, क्रेडिट ट्रांसफर और अपने कोर्स चुनने की लचीलापन जैसी सुविधाएं शामिल की हैं ताकि वे अपनी प्रोग्राम को तैयार कर सकें। उन्हें यूनिवर्सिटी में कोर्स का चयन नहीं करते हुए नामांकन करने का विकल्प भी दिया गया था और फिर बाद में वे विशेषज्ञता का चयन कर सकते थे। उनके छात्रों के लिए बहुविद्यालय द्वारा सम्मिलित एक विविध पोर्टफोलियो वाले कोर्सों का एक एकीकृत तरीके से अध्ययन होता है, जिसे वे अपने एकत्रित क्रेडिट प्वाइंट्स के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। उन्होंने अपनी अकादमिक सलाह प्रणाली का वर्णन किया, जो छात्रों को सिखाता है कि पाठ्यक्रम पोर्टफोलियो कैसे बनाएं और उनके द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों के आधार पर करियर का निर्माण करें। उनका विश्वविद्यालय एक शोध-उन्मुख विश्वविद्यालय बनने की इच्छा रखता है, लेकिन कुछ समय के लिए, वे भारतीय शिक्षा प्रणाली में निहित एक शिक्षण-उन्मुख विश्वविद्यालय बनना चाहते हैं। उन्होंने बहु-विषयक पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की, जिसमें छात्र एक ही क्रेडिट संरचना के भीतर विभिन्नछोटे विषयों के लिए जा सकते हैं।

वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों एवं उद्योग सलाहकारों के साथ छात्रों और संकाय के लिए नियमित बातचीत की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि उन्हें क्षेत्र में दृष्टिकोण और रुझान प्रदान किए जा सकें। छात्रों को समुदाय-उन्मुख गतिविधियों में संलग्न करने के लिए, उनके पास क्रेडिट संरचना में अंतर्निहित सेवा और एक ग्रामीण तल्लीनता कार्यक्रम है। उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि एनईपी लक्ष्य 2035 तक भारतीय शिक्षा लाना है, और उनका विश्वविद्यालय उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है।

इस सत्र को समाप्त करते हुए, प्रोफेसर भारत ने सभी वक्ताओं और उनके मूल्यवान भाषणों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भाषणों का फोकस संस्थागत होमवर्क की महत्ता, होमवर्क के साथ एक पथ बनाने और आगे बढ़ने पर था। सभी ने कौशल विकास, इंक्यूबेशन सेंटर, और आत्मनिर्भर भारत को जोर दिया।

उन्होंने छात्रों के बीच एक रुझान के बारे में भी बात की, जहाँ वे अंग्रेजी में पढ़ाई करते हैं और फिर विदेश में वीजा के लिए आवेदन करते हैं, उसके बाद वे बड़ी कंपनियों और नौकरियों की तलाश में रहते हैं। इस रुझान को बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि मांगा गया है, नौकरियों के निर्माता और रोजगार प्रदाता बनना चाहिए। उन्होंने इस सन्दर्भ में याद दिलाया जो गांधी जी ने कहा था, "बृहत् उत्पादन (मास प्रोडक्शन) नहीं, बल्कि बहुत लोगों द्वारा उत्पादन (मास द्वारा प्रोडक्शन)," उसी तरह से "विकासशील देश" का शब्द धीरे-धीरे "विकसित देश" से बदला जाना चाहिए। जी-20 की अध्यक्षता प्राप्त करने के द्वारा हम इसे करने की क्षमता और ऊर्जा रखते हैं। आईकेएस की आधारभूत बुनियाद का उपयोग करते हुए, हम "वसुधैव कुटुम्बकम्" की ओर बढ़ सकते हैं। उन्होंने सभी को अपने समय के लिए धन्यवाद दिया।

समानांतर सत्र 2

समूह 3: विचारों का आदान प्रदान

सत्र अध्यक्ष: प्रो. पंकज अरोड़ा, निर्देशक, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफलॉग लर्निंग, दिल्ली विश्वविद्यालय



प्रो. पंकज अरोड़ा,

प्रो. अखिलेश कुमार पांडेय

प्रो. आलोक कुमार राय

प्रो. पंकज अरोड़ा,

निर्देशक, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफलॉग लर्निंग, दिल्ली विश्वविद्यालय

पंकज अरोड़ा ने इस शिखर सम्मेलन को संरचना और सफल संचालन देने के लिए आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सत्र की शुरुआत की, जहां शीर्ष संस्थागत नेतृत्वकर्ता नई शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्र में शिक्षा के विकास पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने एनईपी 2020 के दिशानिर्देशों के अनुसार जुलाई 2020 में राष्ट्रीय कौशल समिति की स्थापना का उल्लेख किया। राष्ट्रीय कौशल समिति में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा,

तकनीकी शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के लिए उद्देश्यों और प्रावधानों को लागू किया गया है। उन्होंने कहा, “स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संरचना में भी सुधार किया गया है। स्कूलों में अब 5+3+3+4 साल का ढांचा होगा, और उच्च शिक्षा संस्थानों में 4+1 साल का ढांचा होगा जहां एमफिल को खत्म कर दिया जाएगा, और छात्र सीधे पीएचडी कर सकते हैं।” नई शिक्षा नीति के अनुसार, सभी संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम पहल को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने टिप्पणी की कि पाठ्यक्रम में नवाचारों की आवश्यकता है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए 100 मूल्यवर्धन पाठ्यक्रमों और 100 कौशल वृद्धि पाठ्यक्रमों के साथ 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत की नीति का भी उल्लेख किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में योग्यता वृद्धि योजना शुरू करने के बारे में भी बात की, जो अब दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के वयस्कों को अन्य छात्रों के बीच नियमित छात्रों के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम करने की अनुमति देगा। वयस्क किसी भी पृष्ठभूमि के हो सकते हैं यानी स्नातक, स्नातकोत्तर या यहां तक कि काम करने वाले पेशेवर भी। यह योजना एक सेमेस्टर में 8 क्रेडिट की पेशकश करने वाले 2 पाठ्यक्रमों को लेने की छूट प्रदान करेगी। इस योजना का एकमात्र उद्देश्य छात्रों को वयस्कों और कामकाजी पेशेवरों के अनुभवों से सीखने में मदद करना है। अरोड़ा ने एक बार फिर आयोजकों को धन्यवाद दिया और सत्र के लिए पहले वक्ता प्रोफेसर आलोक कुमार राय का मंच पर स्वागत किया।

प्रो. आलोक कुमार राय

कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय

प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने वीबीयूएसएस और डीएवीवी को इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने अपने सत्र की शुरुआत शैक्षणिक सत्र 2020-21 से एनईपी 2020 को लागू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बनकर हासिल किए गए महान मील के पत्थरों में से एक बताते हुए की। उन्होंने कहा, "विश्वविद्यालय ने उन सभी लक्ष्यों को हासिल कर लिया है जिन्हें संस्थागत स्तर पर हासिल किया जाना था, और नियामक और शासन की कार्यवाही चल रही है।" नीति के सफल समापन और कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय ने एक रूपरेखा का पालन किया है और पूरे पाठ्यक्रम को नया रूप दिया है और एनईपी 2020 खंड 11.9, बिंदु 37 और खंड 11.10 द्वारा प्रस्तावित प्रावधानों को अक्षरशः शामिल किया है। नीति की कई विशेषताएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ जिन पर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है, वे इस प्रकार हैं:

- सभी विषयों में समान क्रेडिट: इसके तहत योजनाओं की श्रेष्ठता को छोड़कर सभी विषयों में समान क्रेडिट स्कोर प्रदान किए जाएंगे। 4 साल के स्नातक कार्यक्रम के लिए छात्रों को 4 साल (48 * 4) की अवधि में कुल 192 क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे, जबकि छात्र स्नातकोत्तर में 96 क्रेडिट और पीएचडी कोर्स वर्क में 4 + 4 क्रेडिट अर्जित करने में सक्षम होंगे।
- प्रवेश और निकास की लचीली प्रक्रिया: छात्रों को उनकी सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रम से बाहर निकलने और किराए पर लेने की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने इसके लिए एक उदाहरण भी रखा, जहां 2 छात्र, एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग से और दूसरा जैव रसायन विज्ञान विभाग से है। उन्हें स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया और वे नए अध्यादेश के अनुसार 4 साल की अवधि में किसी भी समय अपने पाठ्यक्रम जारी रख सकते हैं।
- स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए इंटरनेट और शोध प्रबंध अनिवार्य कर दिए गए हैं।
- एनईपी 2020 में अंतर और अंतर विभागीय क्रेडिट ट्रांसफर, फ्रीज और ओपन इलेक्टिव कोर्स, क्रेडिट और नॉन क्रेडिट वैल्यू एडेड कोर्स, ऑनलाइन कोर्स प्रावधान भी प्रदान किए जाएंगे।
- एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि व्यावसायिक और सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम विभिन्न सेमेस्टर में 8 क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे।
- अब विश्वविद्यालय एक स्नातक कार्यक्रम में 32 पेपर एक्सपोजर प्रदान करेगा जो पीएचडी कार्यक्रम के लिए सीधा संबंध प्रदान करेगा।

विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई गई एक और महत्वपूर्ण बात एनईपी 2020 के खंड 12 के अनुसार छात्र सहायता प्रणाली है। समर्थन की विभिन्न श्रेणियों में सलाह, वित्तीय सहायता, कल्याण और परामर्श सहायता और महिला छात्रों के स्वास्थ्य और स्वच्छता शामिल हैं। इसके अलावा एनईपी 2020 के खंड 17 के अनुसार अनुसंधान संवर्धन योजनाओं को भी ध्यान में लाया गया है। विश्वविद्यालय ऑनलाइन शिक्षा को भी बढ़ावा दे रहा है, जिसके लिए उठाया गया पहला कदम परिवर्तनकारी शिक्षा के लिए अपनी स्वयं की शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) और रणनीतिक शिक्षण अनुप्रयोगों का शुभारंभ है, जिसके लिए विश्वविद्यालय अपने कॉपीराइट के मालिक हैं। विभिन्न हितधारकों के बीच अधिक जागरूकता पैदा करना, समान आधारीक संरचना का विकास करना और एनईपी 2020 के प्रस्तावों के अनुरूप छात्र-केंद्रित पहल शुरू करना। विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में 7 अंतःविषय अनुसंधान संस्थानों की शुरुआत के साथ भी आया है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में अनुसंधान के विद्रोह पर भी जोर दिया और इस प्रकार उन्होंने एनईपी 2020 और अन्य विश्वविद्यालयों की सराहना करके अपना सम्बोधन का समापन किया, जो नीति के सफल कार्यान्वयन की दिशा में बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं।

प्रो. अखिलेश कुमार पांडेय

कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

प्रोफेसर अखिलेश ने विश्वविद्यालयों में बहुभाषा के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। उज्जैन विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश पर बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। विश्वविद्यालय में नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों से प्रवेश प्राप्त हुए और इसलिए विश्वविद्यालय ने सभी छात्रों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम साझा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे विश्वविद्यालय ने मौजूदा छात्रों के साथ नए छात्रों को समायोजित करने पर जोर दिया है, इसलिए अधिकारियों को कोई नयी भूमिकारूप व्यवस्था नहीं बनानी पड़ी।

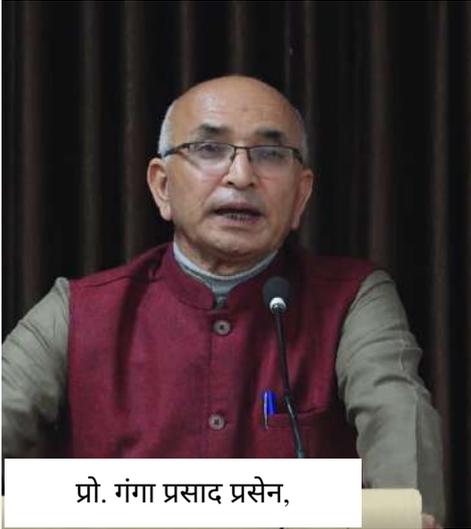
उन्होंने यह भी विस्तार से बताया कि छात्रों को उनके घर से ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है और वे कई भाषाओं में कोर्स लेकर प्रमाणपत्र हासिल कर रहे हैं। इन बहुभाषिक कोर्स और प्रमाणपत्रों को हासिल करके, छात्र पर्यटन के प्रोत्साहन में एक कार्यकारी के रूप में सेवा कर सकते हैं क्योंकि उज्जैन शहर एक महान पर्यटक स्थल है और यहां पर्यटक गाइड की अधिकतम आवश्यकता होती है। यह पाठ्यक्रम छात्रों में आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करेंगे जिससे वे गाइड बन सकते हैं", उन्होंने जोड़ा।

प्रोफेसर अखिलेश का मानना है कि छात्रों को ज्ञान की विविधता प्रदान करना महत्वपूर्ण है, लेकिन जड़ों यानी जातीयता और मूल्य को कभी पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस प्रकार विषय और पाठ्यक्रम के बावजूद सभी पाठ्यक्रमों में जातीय और पारंपरिक ज्ञान को शामिल किया गया है। उनका मानना है कि हर विषय में वैल्यू एडिशन यानी व्यावहारिकता होनी चाहिए। उन्होंने ग्रीन ग्रेजुएट अवधारणा को भी सामने रखा यानी जो छात्र अपने विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, उन्हें पर्यावरण का कुछ बुनियादी ज्ञान होना चाहिए और उनके प्रवेश पर उन्हें अंकुर अभियान के तहत एक पौधा दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें अपने स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान देखभाल करनी होगी और जब वे अपनी डिग्री सफलतापूर्वक पूरी कर लेंगे तो उनके पास अपनी डिग्री पर ग्रीन ग्रेजुएट्स का खिताब होगा। छात्रों को 'लर्न बाय अर्न' पहल का हिस्सा बनने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, जहां वे मशरूम की खेती और जैविक खेती का हिस्सा बन सकते हैं और छात्रों को कमाई का एक हिस्सा मिलेगा और इसके लिए एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा। आगे बढ़ते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय की कुछ उपलब्धियों का उल्लेख किया, जिसमें लगभग 270 कौशल आधारित पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करना, 2024 तक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कृषि के लिए स्नातक पाठ्यक्रम और बागवानी और कृषि विज्ञान के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम होने वाला पहला विश्वविद्यालय बनना शामिल है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय ने एक शोध फाउंडेशन की स्थापना की है जो विश्वविद्यालय से धन प्राप्त करेगा और पिछले विद्वानों से धन प्राप्त करेगा और वे मासिक बैठकों के माध्यम से आस-पास के उद्योगपतियों से इनपुट भी लेंगे। अभी विद्वानों/शोधार्थी को 8000 रुपये का वेतन प्रदान किया जाता है जिसे विश्वविद्यालय उनकी मदद के माध्यम से विस्तारित करने के लिए तत्पर है। अपने भाषण का समापन करते हुए, उन्होंने सरकार के प्रयासों की सराहना की और यह सुनिश्चित किया कि वे नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

समानांतर सत्र 2

समूह 4: विचारों का आदान प्रदान

सत्र अध्यक्ष: प्रो. रवींद्र कन्हरे, अध्यक्ष, प्रवेश और शुल्क नियामक समिति, मध्य प्रदेश



प्रो. गंगा प्रसाद प्रसेन,



प्रो. के. बी. दास,



प्रो. अरुण भटनागर (आईआरएस)

प्रो. रवींद्र कन्हरे,

अध्यक्ष, प्रवेश और शुल्क नियामक समिति, मध्य प्रदेश

विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान और देवी अहिल्या बाई विश्व विद्यालय के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में प्रोफेसर कन्हरे ने श्रोताओं का अभिवादन किया और उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के बाद, हम अब 2023 में हैं, और नीति के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में नीति का कार्यान्वयन पहले ही शुरू हो चुका है। इसके अतिरिक्त, देश भर के कई विश्वविद्यालयों ने भी इस नीति को लागू करना शुरू कर दिया है। कई विश्वविद्यालयों ने इसके कार्यान्वयन के साथ चुनौतियों की सूचना दी है, चाहे बहु-अनुशासनात्मक उद्देश्यों, निरंतर मूल्यांकन या भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए। इन कठिनाइयों के बावजूद, कई विश्वविद्यालयों ने सराहनीय प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि कुछ विश्वविद्यालयों ने केवल योजनाएं बनाई हैं, जबकि अन्य ने उन्हें लागू भी किया है। वे बताते हैं कि इसके अलावा, उन्होंने कुछ चयनित विश्वविद्यालयों के सम्मानित कुलाधिपतियों के लिए सत्र तैयार किया, जो इस रणनीति को निष्पादित करने में आने वाली प्राथमिक चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। प्रोफेसर कन्हरे कहते हैं कि वे न केवल इन चुनौतियों को गिनाएंगे, बल्कि उनसे पार पाने के लिए किए गए उपायों पर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने निम्नलिखित सवाल पर भी विचार करते हुए कहा कि

- इस रणनीति को किस हद तक सफलतापूर्वक निष्पादित किया है, और
- भविष्य में किन संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है?
- क्या इस रणनीति के कुछ प्रमुख तत्वों में बदलाव की आवश्यकता होगी?
- कार्यान्वयन की निरंतरता के बारे में क्या चर्चा चल रही है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, और क्या कोई तैयारी की गई है या नहीं?
- इसी तरह, जब कार्यान्वयन से कोई बाधा या विचलन होता है, तो किन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है?

इन पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, उन्होंने विभिन्न केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का आह्वान किया जो नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे।

प्रो. गंगा प्रसाद प्रसेन,
कुलपति, त्रिपुरा विश्वविद्यालय

प्रोफेसर प्रसेन ने त्रिपुरा विश्वविद्यालय की ओर से श्रोताओं का अभिवादन किया और संस्थागत नेताओं के लिए राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी के अपने संयुक्त उद्यम के लिए विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ की, जिसे 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था- जब कोविड-19 महामारी अपने चरम पर थी। प्रोफेसर प्रसेन ने कहा, “हमने दो दिवसीय ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें हमने पूर्वोत्तर भारत के विश्वविद्यालयों के कई विशेषज्ञों और कुलपतियों को बुलाया और एनईपी के कार्यान्वयन पर गहराई से चर्चा की।” हालांकि, उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के माननीय शिक्षा मंत्री रतन लाल ने त्रिपुरा के तीन प्रमुख विश्वविद्यालयों त्रिपुरा विश्वविद्यालय (एक केंद्रीय विश्वविद्यालय), महाराजा वीर विक्रम विश्वविद्यालय (एक राज्य विश्वविद्यालय) और आईसीएफएआई (एक निजी विश्वविद्यालय) के कुलपतियों को बुलाया और हमें 2022 में राज्य में एनईपी लागू नहीं करने के लिए कहा। उन्होंने हमें एक पाठ्यक्रम बनाने और अंतिम रूप देने और जुलाई 2023 में नए सत्र से इसे लागू करने के लिए कहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का उद्देश्य भारत में सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और एक नई शिक्षा प्रणाली के आधार पर नौकरियां पैदा करना है। त्रिपुरा में, नया पाठ्यक्रम एक नई क्रेडिट प्रणाली के साथ तैयार किया गया था, लेकिन 12 दिसंबर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी नए परिपत्र के प्रकाश में इसकी समीक्षा की गई थी। त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने अनियमित पाठ्यक्रमों के लिए उपायों को आंशिक रूप से लागू किया है, और 2023 शैक्षणिक वर्ष में कॉलेजों में पूर्ण कार्यान्वयन शुरू होगा। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते, यह केंद्रीय विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग टेस्ट (सीयूईटी) में शामिल हो गया है, और प्रवेश प्रक्रिया और पाठ्यक्रम तदनुसार तैयार किए गए हैं। भारत में, 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 441 राज्य-वित्त पोषित विश्वविद्यालय और लगभग 500 निजी विश्वविद्यालय हैं। सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार होनी चाहिए। एनईपी का उद्देश्य कौशल आधारित और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रों को शिक्षित करके रोजगार निर्माता बनाना है। त्रिपुरा में, जहां केवल सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं और औद्योगिक विकास की आवश्यकता है, उद्यमिता को बढ़ावा देना चुनौतीपूर्ण है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा की सुविधा के लिए आईटीआई जैसी अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से, त्रिपुरा के साथ-साथ मणिपुर और नागालैंड जैसे अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कक्षाओं, पुस्तकालयों और शिक्षकों सहित अधिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। शिक्षकों के लिए कई रिक्तियों के बावजूद, त्रिपुरा लोक सेवा आयोग द्वारा केवल 86 की भर्ती की गई है, जबकि 200 पदों को अभी भी भरने की आवश्यकता है। अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति व्याप्त है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने यह कहते हुए अपने भाषण का समापन किया कि त्रिपुरा में नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन इस साल शुरू होगा, और हितधारकों के सभी सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने एनईपी के निर्बाध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे और शिक्षक भर्ती की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रोफेसर ने एक बार फिर आयोजकों का आभार व्यक्त किया और अपना संबोधन समाप्त किया।

प्रो. के. बी. दास,
कुलपति, झारखंड विश्वविद्यालय

प्रोफेसर दास ने आयोजकों को धन्यवाद दिया और झारखंड राज्य को सम्बोधित करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की, जो जनजातियों के प्रभुत्व में है और केवल 22 साल पुराना है। उन्होंने 2009 में विश्वविद्यालय की स्थापना और मुद्दों को हल करने के लिए चल रहे प्रयासों का उल्लेख किया। इसके बाद उन्होंने उन पांच “आर”; पर प्रकाश डाला जिन्हें वह एक कुलपति के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं मानते हैं:

- **भर्ती (Recruitment):** उन्होंने भर्ती की चुनौती को स्वीकार किया, यह बताते हुए कि सबसे अच्छे उम्मीदवार अक्सर अवसर आने पर बीएचयू और जेएनयू जैसे बेहतर और अधिक प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में चले जाते हैं।
- **अवधारण (Retention):** अच्छे उम्मीदवारों को बनाए रखने का महत्व।

- **अनुसंधान (Research):** अनुसंधान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता, जिसमें धन प्राप्त करना और प्रस्तावों के लिए समर्थन की पेशकश करना शामिल है।
- **रिश्ते (Relationship):** राज्य सरकार और स्थानीय समुदायों, जैसे आदिवासियों के साथ अच्छे संबंधों को बनाए रखने का महत्व।
- **प्रासंगिकता (Relevance):** प्रासंगिक रहने और प्रगति करने की आवश्यकता।

बाधाओं और संसाधन सीमाओं के बावजूद, प्रोफेसर दास ने जोर देकर कहा कि उन्होंने संसाधन अनुकूलन के बारे में सीखा है और गतिविधियों के लिए एक समयरेखा बनाई है, स्थिरता की निगरानी और रखरखाव के लिए नोडल एजेंसियों को सौंपा है। उन्होंने पांच साल के पाठ्यक्रम को विकसित करने में कठिनाइयों पर भी चर्चा की और विशेषज्ञों से इनपुट लेने और यूजीसी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम को लचीला बनाने सहित उपयोग की जाने वाली परामर्श प्रक्रिया का वर्णन किया। उन्होंने शिक्षार्थी-केंद्रित शैक्षणिक तकनीकों और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर संकाय को उन्मुख करने के महत्व को संबोधित किया। प्रोफेसर दास ने करियर निर्णयों और परीक्षा सुधारों के कार्यान्वयन के साथ छात्रों की सहायता के लिए प्रत्येक विभाग में अकादमिक परामर्शदाताओं और सलाहकारों की नियुक्ति का भी उल्लेख किया। उन्होंने परिसर विकास के लिए समिति पर चर्चा करके निष्कर्ष निकाला, जो आधारभूत संरचना के मुद्दों को संबोधित करता है और पहल के सुचारू कार्यान्वयन में विश्वास व्यक्त करते हैं।

प्रो. अरुण भटनागर (आईआरएस)

महानिदेशक, आईआईएसटी-आईआईपी-आईआईएमआर

प्रोफेसर भटनागर ने इस अवसर के लिए मेजबानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और सम्मेलन में उपस्थित लोगों को अपना सम्मान देते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने शिक्षा के लिए अपने संस्थान के दृष्टिकोण में हालिया प्रगति पर जानकारी दी। संस्थान का मुख्य ध्यान हमेशा छात्रों को एक पूर्ण शिक्षा प्रदान करना रहा है जो उन्हें बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं और आंतरिक स्वयं की चुनौतियों दोनों के लिए तैयार करता है। उन्होंने उल्लेख किया कि संस्थान का मानना है कि शिक्षा को छात्रों के लिए शांति, सद्भाव और आनंद की भावना लानी चाहिए और उन्हें अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करने के लिए उपकरणों से लैस करना चाहिए। उन्होंने छात्रों के आईक्यू, ईक्यू और मुख्यालय (हैप्पीनेस कोशंट) को बढ़ाने के लिए संस्थान द्वारा की गई पहलों पर भी चर्चा की। संस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है और अपने शैक्षिक प्रयासों के लिए 10 आयामों को लागू किया है। इन आयामों में 4.2 या 5.0 युग के लिए उद्योग के लिए तैयार होना, प्रभावी संचार, शारीरिक स्वास्थ्य, प्रकृति के साथ जुड़ना, सामाजिक जिम्मेदारियां, तकनीकी खेल और गैर-शैक्षणिक क्लब, छात्रों को अपने आराम क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करना, योग्यता-आधारित शुल्क संरचनाएं और प्रदर्शन-आधारित छात्रवृत्ति, स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन, और आत्म-खोज और व्यक्तिगत विकास पर एक मजबूत जोर देना शामिल है। प्रोफेसर भटनागर ने क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों के बारे में भी बात की और बताया कि कैसे सब कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उन्होंने हर्ट्ज पैमाने पर विभिन्न भावनाओं के कंपन को दर्शाते हुए एक ग्राफ प्रस्तुत किया और समझाया कि कैसे नकारात्मक विचारों का हमारे दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, और छात्रों को शिक्षित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने यह कहते हुए अपने भाषण का समापन किया कि उनका संस्थान छात्रों को एक पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जो उन्हें जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है।

प्रो. गोपाल पाठक,

सरला बिड़ला विश्वविद्यालय, रांची

प्रोफेसर पाठक ने अपने संबोधन की शुरुआत शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए की, जिन्हें वह समाज के सबसे सम्मानित सदस्य और अगली पीढ़ी के निर्माता मानते हैं। इसके बाद उन्होंने डॉ. के. कस्तूरीरंगम की प्रभावी अध्यक्षता में 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के शुभारंभ के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि एनईपी के शुभारंभ के साथ, भारत को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मिला, और भारत के सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को एक नया आकार लेने और पिछली शैक्षिक नीतियों द्वारा छोड़ी गई कमियों को भरने का अवसर मिला। प्रोफेसर पाठक ने भारत के समृद्ध इतिहास और सनातन धर्म की शक्ति को स्वीकार किया, जो भारतीयों के लिए जीवन का तरीका रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एनईपी के नए पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा पर जोर दिया गया है। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले के साथ किए गए एक समझौते के बारे में बात की, जिसके तहत छात्र प्रशिक्षण के लिए वहां जा सकते हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के संदेश का भी उल्लेख किया, जिन्होंने हर तरफ से ज्ञान लेने और अपने विचारों को बेहतर बनाने की बात कही, और उस बैठक के बारे में बात की जहां स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 7500 लोगों को संबोधित किया था। प्रोफेसर पाठक ने कहा कि सरला बिड़ला विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न तरीकों के माध्यम से अखंडता, राष्ट्रीयता, समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रीय समझ पर आधारित एक समतावादी वैश्विक समाज का निर्माण करना है। उन्होंने इंजीनियरिंग छात्रों के लिए संस्कृत भाषा को अनिवार्य बनाने, अनिवार्य योग कक्षाएं शुरू करने, छात्रों के चरित्र निर्माण और प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने सहित विश्वविद्यालय द्वारा की गई कुछ पहलों का भी उल्लेख किया। प्रोफेसर पाठक ने विश्वविद्यालय के अच्छी तरह से प्रेरित वैश्विक नेताओं को विकसित करने के दृष्टिकोण को दोहराते हुए अपने बहुमूल्य संबोधन को समाप्त किया, जो बौद्धिक रूप से सक्षम, नैतिक रूप से ईमानदार, सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध, आध्यात्मिक रूप से प्रेरित होंगे और वसुधैव कुटुम्बकम् के दर्शन का प्रचार करेंगे।

समानांतर सत्र 2

समूह 5: विचारों का आदान प्रदान

सत्र अध्यक्ष: प्रो. चंद्र चारु त्रिपाठी, निदेशक, एनआईटीटीआर, भोपाल



प्रो. (डॉ.) विनीता के. सलूजा

प्रति उपकुलपति, मंगलायतन विश्वविद्यालय

मंगलायतन विश्वविद्यालय में एनईपी के कार्यान्वयन और इसे क्रियान्वित करने के लाभों के बारे में प्रोफेसर विनीता ने विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने इक्कीसवीं सदी में प्रमुख हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एनईपी की आवश्यकता पर जोर दिया। एनईपी के मूलभूत सिद्धांतों का छात्र के पाठ्यक्रम पर सीधा प्रभाव पड़ता है, वे हैं

- प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना।
- छात्रों के लिए उनके सीखने के मार्ग को ट्रैक करने और अपना रास्ता चुनने की सुविधा।
- विज्ञान, कला, मानविकी और खेल में बहुआयामी शिक्षा
- भारत और इसकी समृद्ध, विविध, प्राचीन, आधुनिक संस्कृति, भाषाओं और ज्ञान प्रणाली में निहितता और गौरव।

इसलिए, उन्होंने साझा किया कि उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भारतीय मूल्यों और इतिहास को जोड़ा है, और बताया कैसे उन्होंने भगवद्गीता से प्रबंधन प्रतिमान पढ़ाया है।

छात्रों के बौद्धिक क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए छात्रों को प्राचीन अवधारणा और समकालीन अवधारणाओं से अवगत कराने के लिए परिवर्तनकारी पहल।

- सामुदायिक जुड़ाव में क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम
- मानवतावादी नैतिक, सत्य के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के विकास के लिए पर्यावरण शिक्षा और मूल्य-आधारित शिक्षा।
- स्थानीय उद्योग और व्यापार के साथ इंटरशिप के अवसर

उन्होंने जोर देकर कहा कि एनईपी 2020 के तहत, विश्वविद्यालय ने यूजीसी, नई दिल्ली पर आधारित उच्च शिक्षा संस्थानों में दिए गए यूजी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों में कई प्रवेश और निकास बिंदु स्थापित किए। इसके अतिरिक्त, छात्र विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के बीच चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं, ताकि वे अपनी रुचियों का अनुसरण कर सकें। एक बार एक छात्र ने 120 क्रेडिट अर्जित कर लिए - या ऑनर्स छात्रों के लिए 160 क्रेडिट - वे अपना प्रमाणन प्राप्त करेंगे।

प्रोफेसर विनीता ने अपने निष्कर्ष में साझा किया कि एनईपी ने छात्रों और शिक्षकों दोनों के दृष्टिकोण को बदल दिया है। इसके अतिरिक्त, यदि एनईपी को सभी संस्थानों द्वारा अपनाया जाता है, तो इसमें राष्ट्र को नया रूप देने की शक्ति है।

प्रो. एस. पी. बंसल

कुलपति, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश

प्रोफेसर बंसल ने एनईपी 2020 का अवलोकन करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की, इसे एक महत्वाकांक्षी और भविष्यवादी नीति बताया, जिसका उद्देश्य कठोर सीमाओं को हटाकर और सभी हितधारकों के लिए नई संभावनाएं पैदा करके नए भारत की आकांक्षाओं को पूरा करना है। यह नीति भारत में उच्च शिक्षा परिदृश्य को बदलने और उच्च शिक्षा को अधिक परिणाम-आधारित बनाने के लिए कई बदलावों का प्रस्ताव करती है। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएचपी) 2021-2022 के शैक्षणिक सत्र से सभी विभागों में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर एनईपी 2020 की सिफारिशों को लागू करने वाला पहला भारतीय विश्वविद्यालय था। प्रोफेसर बंसल ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में सीयूएचपी द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी विस्तार से बताया, जिसमें शामिल हैं: उच्च शिक्षा को बहु-विषयक बनाना, समग्र स्नातक शिक्षा का निर्माण, एक रचनात्मक, विचार-आधारित अनुप्रयोग और व्यावसायिक शिक्षा और कई प्रविष्टियों के माध्यम से एक लचीला पाठ्यक्रम और बहु-निकास प्रणाली। सीयूएचपी ने भारत को विश्वगुरु के मार्ग पर स्थापित करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली की विशिष्ट विशेषताओं को भी पेश किया। विश्वविद्यालय ने प्रत्येक विषय में एक मूल्य प्रणाली, विषयों के बहु-विषयक एकीकरण और एक समग्र शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की और अकादमिक बैंक क्रेडिट (एबीसी) प्रणाली को भी अपनाया, जिसमें क्रेडिट संचय, क्रेडिट पहचान, क्रेडिट ट्रांसफर और क्रेडिट रिडेम्पशन शामिल हैं।

प्रोफेसर बंसल ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के दौरान सीयूएचपी के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। इन चुनौतियों में छात्रों पर बढ़ता बोझ, ध्यान भंग, अनिर्णय और पारंपरिक मुख्य विषयों की कीमत पर बहु-विषयक शिक्षा का चुनाव करने की कठिनाई शामिल थी। इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए, सीयूएचपी ने बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए पाठ्यक्रम और कार्यभार-वितरण की फिर से जांच और पुनर्विचार करने के लिए एक समिति गठित की। विश्वविद्यालय ने विषयों के सम्मिश्रण और छात्रों के लिए करियर के अधिक अवसर पैदा करके बहु-विषयक शिक्षा को और अधिक व्यवहार्य बना दिया है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य बहु-विषयक शिक्षा के सफल निष्पादन के लिए शिक्षार्थियों के बीच विचारों की विविधता विकसित करना है।

प्रो. सरोज शर्मा

अध्यक्ष, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस), नोएडा

प्रोफेसर शर्मा ने अपना भाषण एनआईओएस के जनादेश को साझा करते हुए शुरू किया, जो दुनिया में सबसे बड़ी ओपन स्कूलिंग प्रणाली है, क्योंकि यह हाई स्कूल दूरस्थ शिक्षा में काम करने वाले स्कूल बोर्डों में से एक है। उन्होंने स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर जोर दिया।

इसके बाद उन्होंने जन शिक्षण संस्थान के साथ एनआईओएस के सहयोग पर प्रकाश डाला, जिसके माध्यम से वे लगभग 34 लाख असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को प्रशिक्षण, कौशल और शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस पहल में शिक्षण वयस्कों को भी शामिल किया गया है जो COVID-19 महामारी के दौरान विस्थापित हुए थे। यूनेस्को ने एनआईओएस को शिक्षा में नवाचार के लिए साक्षरता पुरस्कार देकर इस प्रयास को मान्यता दी।

जैसा कि एनईपी 2020 में कल्पना की गई थी, एनआईओएस भी पिछले दशक में बहु-विषयक और अंतःविषय दृष्टिकोण का पालन कर रहा है। उनके पास कौशल मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) है, जो उन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने और आईटीआई में अध्ययन केंद्र स्थापित करने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, उनके पास एक क्रेडिट ट्रांसफर पद्धति है जो सभी स्कूल बोर्डों और आईटीआई पर लागू होती है।

एनआईओएस ने अग्निवीर प्रमाणन प्रदान करने के लिए सभी तीन रक्षा संगठनों के साथ समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। एक प्रमुख परियोजना के हिस्से के रूप में, वे महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र के दूसरे अवसर पहल के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा, एनआईओएस कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग से पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जो उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को और बढ़ाता है। उन्होंने एनआईओएस की उन विशेषताओं का उल्लेख किया जो एनईपी 2020 के अनुरूप हैं जैसे कि विषय की पसंद की सुविधा, शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के साथ एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संयोजन, आभासी कक्षाएं और ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली (ओडीईएस)।

उन्होंने एनआईओएस की लैंगिक नीतियों/समावेशी नीतियों पर जोर दिया, जिनका उल्लेख एनईपी 2020 में भी किया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति और विरासत, लॉजिस्टिक्स, आईएसएल और टूर गाइड प्रशिक्षण पर पाठ्यक्रम भी विकसित किए हैं।

अंत में, उन्होंने सुनिश्चित किया कि हम समृद्ध और विकसित होंगे जो "सबका साथ, सबका विकास" के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। जैसा कि पुरानी कहावत है, "तलवार जीत नहीं लाती है, यह ज्ञान है जो हमें दुनिया जीतने में मदद करता है," उन्होंने कहा कि 2030 तक, हम महाशक्ति (प्रमुख शक्ति) प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

प्रो. राघवेंद्र पी. तिवारी,

कुलपति, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, बठिंडा

उन्होंने एनआईओएस पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु प्रदान करने के लिए पूर्व वक्ता प्रो. सरोज शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रारंभ किया। उन्होंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटकों पर चर्चा की, जिनका उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा एनईपी के कार्यान्वयन से वास्तविक प्रभाव पैदा करने के लिए किया गया।

उन्होंने दावा किया कि हम वर्तमान में "शिक्षा 4.0" युग में रह रहे हैं, जिसमें सीखना अब परिणाम-आधारित है, जैसा कि एनईपी 2020 में भी जोर दिया गया है, यानी एक छात्र को एक डोमेन-आधारित ज्ञान या कौशल कैसे शिक्षित किया जाएगा, वे क्या करेंगे इससे सीखें, और इसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा।

उन्होंने परिणामों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया: कार्यक्रम के परिणाम और पाठ्यक्रम के परिणाम और दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से अधिकांश ने अपने सीखने के परिणामों को अपनी वेबसाइटों पर सूचीबद्ध किया।

सभी पाठ्यक्रमों के लिए सीखने के परिणामों को परिभाषित करने में पहला कदम परिणाम आधारित शिक्षा सुनिश्चित करना है। दूसरा चरण पाठ्यक्रम सामग्री को सीखने के परिणामों के साथ मैप करना है। तीसरा चरण प्रत्येक पाठ्यक्रम मॉड्यूल के लिए उपयुक्त शिक्षाशास्त्र प्रदान करना है ताकि अधिक से अधिक छात्रों को लाभान्वित किया जा सके। अंतिम चरण यह आकलन करना है कि शिक्षार्थियों ने लागू सीखने के परिणामों को प्राप्त किया है या नहीं।

उन्होंने कहा कि उनका विश्वविद्यालय बुनियादी अनुसंधान निधि के साथ-साथ संकाय सदस्यों के लिए एक शोध बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। शामिल होने के 15 दिनों के भीतर, वे अध्ययन प्रस्तावों का अनुरोध करेंगे, जिसका मूल्यांकन किया जाएगा और एक समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। प्रत्येक संकाय सदस्य जो एक वर्ष में 50 से अधिक पत्र प्रकाशित करता है, उसे 5 लाख रुपये का पुरस्कार मिलता है जिसका उपयोग वे शैक्षिक उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं।

जैसा कि एनईपी 2020 में कल्पना की गई है, वे सर्टिफिकेट कोर्स की पेशकश करेंगे और भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन के लिए एक केंद्र भी स्थापित करेंगे। वे एनईपी 2020 और इसके पिछले संस्करणों में भेद करते हैं क्योंकि यह अधिक राष्ट्र-केंद्रित और छात्र-केंद्रित है।

उन्होंने इस बात पर बल देते हुए व्याख्यान का समापन किया कि इन सभी प्रथाओं को लागू करने से छात्र प्लेसमेंट में वृद्धि हुई है और उनके विश्वविद्यालय की दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हुई है।

विशेष व्याख्यान

विषय- शिक्षा और राष्ट्रीय विकास

वक्ता: डॉ कृष्ण गोपाल, सह सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

डॉ कृष्ण गोपाल

सह सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

डॉ कृष्ण गोपाल द्वारा दिया गया विशेष व्याख्यान, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास में उसकी भूमिका से संबंधित था। उन्होंने राष्ट्र के विचार के बारे में बात करते हुए अपना व्याख्यान शुरू किया, और यह बताया कि पश्चिम में विकसित यह विचार भारत के 'राष्ट्र' के विचार से कैसे भिन्न है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका को देखने से पहले इस परिभाषा को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रीय पहचान के लिए जर्मन संघर्ष में हुई थी और यह विशिष्टता के विचार पर आधारित था। अर्थात् राष्ट्र एक ऐसी कड़ी के आधार पर विकसित होते हैं जो लोगों को एक साथ बांधती है। यह कड़ी भाषा, संस्कृति, जाति आदि हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह 'विशिष्टता' पश्चिमी सभ्यता की आधारशिला है। दूसरी ओर, भारत एक 'राष्ट्र' है जो समावेशिता को बढ़ावा देता है। हमारी विविधता के बावजूद, हम सद्भाव में एक साथ रहने में सक्षम हैं।

डॉ. गोपाल के अनुसार इसका श्रेय भारतीय परंपरा में निहित आध्यात्मिकता को जाता है। एक राष्ट्र के रूप में काम करने वाले भारत के प्रति विंस्टन चर्चिल के अविश्वास का मुकाबला करते हुए, उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि कैसे भारत ने पिछले कुछ वर्षों में प्रगति की है। 1950 और 60 के दशक में बड़े पैमाने पर खाद्य संकट का सामना करने के बाद, आज हम दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान निर्यातक हैं। वे हम भारतीयों से हमारी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए भारत के गौरवशाली अतीत में जाने का आग्रह करते हैं। यह इतिहास, विशेष रूप से प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था के कामकाज, समकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली द्वारा उपेक्षित किया गया है। और इसलिए, अपनी आध्यात्मिकता के साथ फिर से जुड़ने के लिए, हमें किसी विशेष विषय के इतिहास और उसके सिद्धांत में गहराई से जाने से पहले भारत के योगदान को पढ़ाना चाहिए। यह सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के आत्मसात को बढ़ावा देगा।

डॉ कृष्ण गोपाल ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि प्राचीन भारत में शिक्षा मुफ्त थी और यह लोगों के बीच भेदभाव नहीं करती थी। यह गुरुकुल प्रणाली का सच था। यह प्रणाली, उन्होंने कहा, छात्रों और समाज के बीच जिम्मेदारियों की पारस्परिकता पर आधारित थी। यह समाज की जिम्मेदारी थी कि वह सभी छात्रों को शिक्षा आसानी से उपलब्ध कराये, और यह छात्रों की जिम्मेदारी थी कि वे प्राप्त ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए करें। इसके बाद उन्होंने उस महत्व और सम्मान के बारे में बात की जो अतीत में भारतीय शिक्षा को देते थे। महाभारत से दुष्यंत का उदाहरण देते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे राजाओं ने भी शिक्षण संस्थानों की पवित्रता का सम्मान करते थे, और कैसे आध्यात्मिक ज्ञान ने इन मूल्यों को विकसित करने में भूमिका निभाई। यह आध्यात्मिक ज्ञान करुणा, सहानुभूति, दया आदि जैसे मूल्यों का आधार है जो एक छात्र को उसकी सीख का उपयोग करने के संबंध में सही दिशा में प्रेरित करता है।



डॉ कृष्ण गोपाल

भारतीय ज्ञान प्रणाली और पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर सहिष्णुता का स्तर है। जबकि प्रारंभिक पश्चिमी ज्ञान बाइबिल के विचारों तक ही सीमित था, और इनमें से कोई भी विचलन चर्च द्वारा नियंत्रित किया गया था, भारत के लिए ऐसा नहीं था। सीखने की प्रक्रिया को परिष्कृत करने के लिए, भारतीय ऐतिहासिक ज्ञान प्रणालियों ने विरोधाभासी विचारों और विचारधाराओं के प्रवाह को प्रतिवाद के रूप में अनुमति दी। इसके विपरीत पूरे यूरोप में चर्च की असहिष्णुता और विरोध का मुख्य कारण था- शिक्षा से चर्च को अलग करने, शिक्षा प्रणाली को और अधिक 'धर्मनिरपेक्ष' बनाना।

आखिरकार, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का यह विचार यूरोपियों द्वारा भारत में लाया गया और उनके द्वारा सख्ती से प्रचारित किया गया। हालाँकि, डॉ. गोपाल ने ध्यान दिया कि भारत के इस धर्मनिरपेक्षीकरण ने आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को शिक्षा से अलग कर दिया। तदनुसार, जैसा कि राष्ट्रवादियों ने इसे महसूस किया, वे ओरिएंटलिस्ट शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों के साथ आए, जो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ सैद्धांतिक ज्ञान को संश्लेषित करते थे। पं. मदन मोहन मालवीय का हवाला देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि साहित्यिक प्रशिक्षण और शिक्षा जो नौकरियों को अंतिम लक्ष्य के रूप में देखती है, नैतिक ऊंचाई में एक इंच भी नहीं जोड़ती है, और और इस समस्या को कैसे सुधारा जाना चाहिए। अपने व्याख्यान का समापन करते हुए, डॉ. गोपाल ने अध्यापन को एक आध्यात्मिक और शैक्षणिक कर्तव्य माना और अपने विश्वास को दोहराया कि तकनीकी और आध्यात्मिक शिक्षा एक साथ मिलकर राष्ट्रीय विकास कर सकती है।



समापन सत्र

मुख्य अतिथि: रमेश बैस, झारखंड के माननीय राज्यपाल

विशिष्ट अतिथि: डॉ मोहन यादव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार;

सुश्री उषा ठाकुर, माननीय पर्यटन मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार

प्रो. टी.जी. सीताराम, अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)

गरिमामय उपस्थिति: प्रो. नरेंद्र कुमार तनेजा, राष्ट्रीय महासचिव, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान



श्री रमेश बैस

झारखंड के माननीय राज्यपाल

माननीय राज्यपाल, श्री रमेश बैस जी ने अपने संबोधन की शुरुआत इस बात पर जोर देकर कहा कि शिखर सम्मेलन संपूर्ण भारत के शिक्षाविदों के लिए 'महाकुंभ' की तरह है। जो भारत की शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण और विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आए हैं। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए इस तरह के विचार-विमर्श के फलदायी होने की आशा व्यक्त की। उनके अनुसार, हमें भारत में शैक्षिक संस्थानों की संख्या के बजाय शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने झारखंड विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी पर जोर दिया। जहाँ 65 प्रतिशत शिक्षकों की कमी थी। विश्वविद्यालय और कॉलेज अभी भी बिना कर्मचारियों के काम कर रहे हैं जिसे छात्रों के शिक्षा से समझौता के रूप में देखा जाना चाहिए। छात्र राज्य के लिए मूल्यवान हैं लेकिन वे उच्च शिक्षा के उद्देश्य से राज्य छोड़ देते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधाओं के निर्माण पर बल दिया ताकि शिक्षा के उद्देश्य से छात्रों के दूसरे राज्यों में पलायन को रोका जा सके। इसके अलावा, उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 के महत्व और हमारी शिक्षा प्रणाली की बेहतरी के लिए इसे लागू करने की प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने परिवर्तनों को शामिल करते समय आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की लेकिन इन परिवर्तनों के सफल कार्यान्वयन के बाद शिक्षा प्रणाली की बेहतरी के प्रति आशा व्यक्त की। माननीय राज्यपाल ने कुलपतियों की बैठकों की बात कर सरकारी और निजी शिक्षा के बीच के अंतर को रेखांकित किया। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों के फायदों को सरकारी विश्वविद्यालयों में शामिल करने की आवश्यकता को रेखांकित किया ताकि हम बेहतर शिक्षा की दिशा में काम कर सकें। शिक्षक-छात्र अनुपात अभी भी उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है और हमें इस अनुपात की बेहतरी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने नई शिक्षा नीति के उन प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित किया जो सिद्धांत और व्यवहार को एक साथ लाते हैं ताकि युवाओं के कौशल विकास की दिशा में कदम उठाए जा सकें। माननीय राज्यपाल ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि अन्य भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है लेकिन हमारे युवाओं को अपनी संस्कृति पर गर्व करने और पश्चिम को मूर्तिमान करने से रोकने की आवश्यकता है। उनके अनुसार, इस तरह का व्यवहार परिवर्तन एक राष्ट्र के रूप में भारत के वास्तविक विकास में सहायक होगा। हमारी शिक्षा को जनसांख्यिकीय लाभांश की जरूरतों और कौशल के अनुरूप होना चाहिए और इस शिखर सम्मेलन के निर्णयों से विशेष रूप से छात्रों और सामान्य रूप से समाज को लाभ होगा।

डॉ. मोहन यादव

माननीय शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार

माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक विश्वविद्यालय की विशेषताओं और एक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के बारे में अपने विचारों से अतिथियों को अवगत कराते हुए अपना व्याख्यान शुरू किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य छात्र का समग्र विकास है और इसका प्रयोजन छात्रों को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित करना है। अपने व्याख्यान में, उन्होंने उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश सरकार अपने नए शिक्षा प्रारूप में प्राचीन इतिहास से महत्वपूर्ण अंशों को शामिल करने की कोशिश कर रही है, और इस तरह के अनुबंध सम्मेलन शिक्षा को प्रभावित करने वाले सूक्ष्म मुद्दों को कम करने में सहायक रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलन समान मनोवृत्ति वालों को जोड़ने में मदद करते हैं जो शिक्षा के विस्तृत लक्ष्य हासिल करने के लिए निस्सवार्थ भाव से मेहनत करते हैं। इसके बाद उन्होंने इस तरह की चर्चाओं का हिस्सा होने के लिए सभी को आभार व्यक्त किया।

शुश्री उषा ठाकुर

माननीय पर्यटन मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार

माननीय पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने दर्शकों का स्वागत करते हुए और इस अवसर के लिए अपना आभार व्यक्त करते हुए, विनम्र अनुग्रहपूर्ण अभिवादन के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने पुरानी शिक्षा नीति की स्थिति और नई शिक्षा नीति की संभावनाओं पर सारगर्भित व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि भारत जैसी धरती दुनिया में कहीं नहीं है। यह "देवभूमि" 75,000 प्रकार की पौधों की प्रजातियों से आच्छादित है, और जीवों की 45,000 प्रजातियाँ अपना संतुलन बनाए रखती हैं। इसका कण-कण भगवान शंकर है, और बूँद- बूँद गंगाजल है। हमने इसे कभी जमीन का टुकड़ा नहीं माना बल्कि एक जीवित और जागरूक राष्ट्र-पुरुष माना। भारत की वे सभी विशेषताएँ जो वैदिक संकल्प से थीं, सैकड़ों वर्षों की गुलामी में खो गईं और नई शिक्षा प्रणाली ने बेहतर भविष्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विदेशी शिक्षा व्यवस्था ने हमारे महानतम मूल्यों को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसके नकारात्मक परिणाम भी हमें भुगतने पड़े हैं। आज जहाँ बच्चों में युवा शिक्षार्थियों के रूप में जोश और देशभक्ति का जज्बा भरा होना चाहिए, वहीं हम देखते हैं कि आजादी के 75 वर्षों में पूरे राष्ट्र की भावना और नैतिक मूल्य, जो कभी सिद्धांतों और परंपराओं के साथ मजबूती से स्थापित थे, कहीं पीछे छूट गए हैं। शिक्षा प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि युवाओं मशीनों की भांति बना देता है, भावनाओं से रहित और हताशा और निराशा से भरा हुआ। जबकि पाठ्यक्रम के अनुसार सफलतापूर्वक अपनी शिक्षा पूरी करने वाले छात्र अत्यधिक सक्षम हो सकते हैं, किन्तु उनमें अक्सर आत्मविश्वास, जीवन के प्रति जुनून और व्यक्तित्व और मानवीय मूल्यों के महत्व की समझ की कमी होती है।



श्री रमेश बैस



डॉ. मोहन यादव



शुश्री उषा ठाकुर

माननीय मंत्री ने दावा किया कि यदि भारत के गौरवशाली इतिहास को पढ़ाया जाए, तो वह गारंटी देती हैं कि मृत व्यक्ति भी गर्व के साथ खड़े होंगे और अपने देश के सम्मान और आदर के लिए लड़ेंगे। इतिहास को मुगल और पूर्व-मुगल शासन के नाम पर पढ़ाया जाता है, जहां हम पीड़ित थे और दूसरों द्वारा शासित थे। उन्होंने कहा, "जरा सोचिए कि अगर आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा इतिहास सिखाया जाता है, जो आत्म-पतन की भावना पैदा करता है, तो वे भारत के गौरवशाली इतिहास को कैसे समझ सकते हैं और उसमें अपनी भूमिका कैसे स्थापित कर सकते हैं?" आगे उन्होंने विद्या भारती संस्था के प्रति गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि जब भारत पर इस तरह के अत्याचार किए जा रहे थे जब हमारे क्रांतिकारी नायकों को अपमानित करने के लिए तथ्यों और सबूतों को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा था, तब विद्या भारती नेतृत्व ने उन्हें अदालत में चुनौती देने और देश की देशभक्ति का सम्मान करने की पहल की थी। इसके माध्यम से सिर्फ क्रांतिकारियों को ही नहीं बल्कि आने वाली पूरी पीढ़ी को गर्व होगा। अंत में, मंत्री ने व्यक्त किया कि वह नई शिक्षा प्रणाली के लिए कभी भी पर्याप्त रूप से आभारी नहीं हो सकती हैं जो भारत और भारतीयता से भरी हुई है और भारतीय संस्कृति को एक बार फिर दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार करती है।

प्रो. टी. जी. सीताराम

अध्यक्ष, एआईसीटीई

प्रोफेसर सीताराम ने विशाल क्षमताओं के बावजूद अनुसंधान और विकास क्षेत्र में धन की कमी पर प्रकाश डाला। उन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने मौजूद कमियों का पता लगाने और उन्हें दूर करने की दिशा में कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने शिक्षा की रूपरेखा को सार्वभौमिक बनाने के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली, एकात्मक शैक्षणिक संस्थानों की क्लस्टरिंग और सामुदायिक जुड़ाव पर जोर दिया। और इंजीनियरिंग कॉलेजों में छोटे विषयों के रूप में डेटा साइंस, आईओटी और ब्लॉकचैन जैसे उभरते क्षेत्रों के समावेश के बारे में बताया। उन्होंने छात्रों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अनिवार्य इंटरशिप और योग को शामिल करने के महत्व पर भी जोर दिया। वह शिक्षक प्रशिक्षण के महत्व के बारे में बात करते हैं और एआईसीटीई टीचिंग एंड लर्निंग एकेडमी (एटीएएल) जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हैं जो शिक्षकों को प्रशिक्षित, प्रेरित और सक्रिय करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। पुस्तकों को और अधिक सुलभ बनाने के लिए भाषा अनुवाद, व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने की सुविधा, और तकनीकी शिक्षा पर रोक हटाना भी सही दिशा में कुछ कदम हैं। उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि सरकार जरूरतमंद संस्थानों का समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही, शैक्षिक वातावरण को निर्देशित करने के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया बनाए रखेगी।



प्रो. नरेंद्र कुमार तनेजा



डॉ. अजय वर्मा



प्रो. टी. जी. सीताराम

प्रो. नरेंद्र कुमार तनेजा

राष्ट्रीय महासचिव, वीबीयूएसएस

प्रो. तनेजा ने झारखंड राज्य के माननीय राज्यपाल रमेश बैस, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, विद्या भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश शर्मा, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन सहित अन्य सम्मानित अतिथि को धन्यवाद ज्ञापन के साथ अपना भाषण शुरू किया। फिर उन्होंने इस बारे में बात की कि कैसे विद्या भारती, भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए काम कर रही है। प्रो. तनेजा ने आध्यात्मिक शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए यह भी कहा कि आध्यात्मिक शिक्षा तकनीकी शिक्षा की पूरक है। अपने संबोधन का समापन करते हुए, उन्होंने इंदौर घोषणा के बारे में बात की और बताया कि कैसे एनईपी, अपने बहु-विषयक और बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ, भारत को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की दिशा में प्रयास करने में मदद करेगा।



इंदौर घोषणा

हम, प्रतिनिधि, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अंतर-संस्थागत विकास और सहयोग पर एक संवाद को आगे बढ़ाने के लिए संस्थागत नेताओं के राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए इंदौर में एकत्रित हुए; हम अपने विश्वविद्यालयों में इस घोषणा को लागू करने के लिए असीमित ऊर्जा और पूर्ण समर्पण के साथ खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों, कुलपतियों, प्रतिकुलाधिपतियों, वाइस चांसलरों और प्रमुख प्रोफेसरों के रूप में, हम स्पष्ट रूप से इस घोषणा और इसके सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। हम 'प्रगति पथ के नौ आयाम' के प्रति अपने समर्पण की घोषणा करना चाहते हैं। हमारे व्यक्तिगत संस्थानों में, हम स्पष्ट अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्राथमिकताओं के साथ मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों के संदर्भ में इसे परिभाषित करते हैं। हमारे संस्थानों के नेताओं के रूप में, हम उल्लिखित पथ के प्रति अपनी निष्ठा को रेखांकित करते हैं।

सुधार की संस्कृति (Culture of Reforms)

नई शिक्षा नीति 2020 को लागू हुए दो साल हो गए हैं। उच्च शिक्षा परिदृश्य में कई प्रगतिशील उपाय शुरू किए गए हैं, और निकट भविष्य में कई अन्य उपायों की कल्पना की गई है। सुधारों की गति स्थिर रही है और उच्च शिक्षा संस्थानों के नेताओं की ओर से एक मजबूत प्रतिबद्धता देखी गई है। इसे मजबूत और समन्वित करने की जरूरत है। हम 'सुधारों की संस्कृति' लाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा में प्रतिमान विस्थापन लाने के लिए साहसिक, प्रगतिशील, दूरगामी और व्यापक सुधारों की परिकल्पना की गई है। हमें इसे ऐसे समझना होगा की एनईपी 2020 सुधार की संस्कृति के तहत लाया गया एक सुधार ही है।

जबकि सुधार की संस्कृति हमारे द्वारा स्थापित संरचनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में है, यह मूल रूप से दृष्टिकोण के बारे में है। संस्कृति विश्वासों और प्रथाओं के बारे में है। यह सिस्टम के डीएनए का हिस्सा होने वाली भूमिकाओं, अपेक्षाओं और विश्वसनीयता के बारे में है।

सीखने के लिए शिक्षण

नई शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा में 'पढ़ाने से लेकर सीखने' में एक महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में है। जब सब कुछ कहा और किया जाता है, तो अकादमिक और संगठनात्मक नेतृत्व एनईपी 2020 को अक्षरशः और भावना दोनों में लागू करने की कुंजी है। जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने 'उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार' सम्मेलन में छात्रों को 'क्या सोचें' के बजाय 'कैसे सोचें' से लैस करने की बात पर जोर दिया था तो नेतृत्व द्वारा नीति का कार्यान्वयन और शासन की शैली, इस बदलाव को लाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम इस परिवर्तन का नेतृत्व करने और अपनी कक्षाओं को 'शिक्षण के क्षेत्र' से 'सीखने के स्थान' में बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसमें हमारे एंडरगॉंजी - स्व-प्रेरित सीखने की सुविधा में सुधार शामिल होंगे। संकाय और शिक्षार्थियों के लिए बहु-विषयक शिक्षा और अंतःविषय बातचीत के अवसरों को मजबूत करने के लिए नेतृत्व भी खुद को प्रतिबद्ध करता है।

टॉप-डाउन को बॉटम-अप एप्रोच के साथ जोड़ना

एनईपी 2020 (विभिन्न चरणों में) के कार्यान्वयन की वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं को सभी हितधारकों को रेखांकित करने वाले नेतृत्व के संदर्भ में एक टॉप-डाउन रूपरेखा आदर्श होगी। हितधारक परिवर्तनों के नट और बोल्ट पर विचार-मंथन कर सकते हैं और अंतिम निर्णय लेने और प्रासंगिक अधिसूचनाएं और नियम जारी करने से पहले नेतृत्व को प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा दृष्टिकोण सभी हितधारकों को एनईपी 2020 के तहत परिकल्पित परिवर्तनों और सुधारों का स्वामित्व लेने की अनुमति देगा।

सहयोगात्मक निर्णय लेना

यह लक्ष्य पिछले लक्ष्य का स्वाभाविक परिणाम है। एनईपी 2020 का मूल सहयोग है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं कि सहयोग की भावना हमारी विचार प्रक्रियाओं और हमारे संस्थागत ढांचे को डिजाइन करने के तरीके में व्याप्त हो। यदि एनईपी 2020 सीखने की प्रक्रिया में सहयोग को प्रोत्साहित करती है, तो सहयोग की भावना उच्च शिक्षा संस्थानों की संरचनाओं और प्रक्रियाओं में परिलक्षित होनी चाहिए।

भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) की प्रधानता

एनईपी 2020 का मूल / 'जड़' है - भारतीय लोकाचार और मूल्यों में मजबूती से स्थापित होना। यह घोषणा प्राचीन भारतीय ज्ञान के साथ-साथ 21वीं सदी के सीखने के ढांचे को तैयार करते समय इसे प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता के प्रति सचेत है। यह 'जड़' हमें वर्तमान चुनौतियों का समाधान करते हुए देश की समृद्ध परंपराओं और विरासत का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। अकादमिक नेता उसी के प्रति प्रतिबद्धता का पुरजोर समर्थन करते हैं। आईकेएस के पास उच्च शिक्षा संस्थानों के अकादमिक नेतृत्व के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण है जिसमें सामाजिक विज्ञान में एक मौलिक आधार शामिल है और स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राथमिकता भी शामिल है। प्राचीन ज्ञान प्रणालियों ने पांच तत्वों - पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष के प्रभाव और उनका सम्मान करने की आवश्यकता की बात की। अकादमिक नेताओं के रूप में, हम पांच तत्वों के महत्व को स्वीकार करने के लिए सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। स्वदेशी भाषाओं पर ध्यान देने के साथ भाषाओं के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना एक प्रतिबद्धता है, जिसे हम एनईपी 2020 के जनादेश को पूरा करने के लिए करते हैं।

परिणाम-आधारित शिक्षा को प्रधानता

एनईपी 2020 इनपुट्स और इंटेक्ट से अधिक आउटपुट और आउटकम पर केंद्रित है। हम विश्वविद्यालयों के रूप में, हमारी विभिन्न गतिविधियों और जिम्मेदारियों के परिणामों को अधिकृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एनईपी 2020 को लॉन्च करते समय प्रधानमंत्री की अपील में नतीजों का महत्व सबसे अहम था। हम परिणामों के आधार पर अपने प्रदर्शन का आकलन करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। जब सीखना कुंजी है, सीखने के परिणाम और हमारे शिक्षार्थियों को कुशल चिकित्सकों और पेशेवरों के रूप में बदलने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। हम समानता और करुणा के साथ इस दिशा में आगे बढ़ने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। परिणाम-आधारित शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के लिए हमें शिक्षा और उद्योग/समाज के बीच बेहतर संबंध सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।

मूल्यांकन के लक्ष्यों को पुनर्परिभाषित करना

जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हम शिक्षाविदों से अपील की कि वे अपने शिक्षार्थियों को 'क्या सोचें' के बजाय 'कैसे सोचें' के कौशल से लैस करने पर ध्यान केंद्रित करें, हमारे मूल्यांकन मापदंडों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। क्या हम सीखने की मात्रा या सीखने के अनुप्रयोग का आकलन कर रहे हैं? क्या मूल्यांकन केवल औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से होता है? क्या आकलन शिक्षार्थियों की बेंचमार्क के लिए होना चाहिए या उनकी ताकत और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में उनकी सहायता करने के लिए चाहिए? ये प्रमुख प्रश्न हैं जिन्हें अकादमिक नेताओं के रूप में हमें संबोधित करने और हल करने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों है कि परीक्षाओं में 'हाई अचीवर्स' जरूरी नहीं कि जीवन में 'बेस्ट परफॉर्मर' ही हों? क्या हम अपने शिक्षण संस्थानों में जीवन और जीवन जीने के लिए एक नई पीढ़ी तैयार करते हैं, और क्या हमारी मूल्यांकन प्रणाली इसकी अनुमति देती है? यह एक मूल्यांकन प्रणाली के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है जो पारदर्शी है और सीखने वाले का आकलन करती है न कि शिक्षार्थी का।

जवाबदेही मानदंड और सुशासन

अकादमिक नेताओं के रूप में, जवाबदेही मानदंडों और सुशासन प्रथाओं का हमारा पालन एनईपी 2020 की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। एनईपी-2020 एक नियामक प्रणाली का वादा करता है जो 'हल्का लेकिन चुस्त' है। जैसा कि हम एनईपी 2020 को लागू करते हैं, हम संदर्भ-विशिष्ट जिम्मेदारियों को लागू करने में नम्यता सुनिश्चित करने के लिए गैर-परक्राम्य मानदंडों और 'हल्केपन' पर 'कठोरता' के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। सुशासन केवल नियमों और विनियमों के पालन के बारे में नहीं है। यह उन लोगों तक 'पहुंच' के बारे में है जिनके लिए उच्च शिक्षा प्रणाली आवश्यकताओं को पूरा करती है। सुशासन सभी हितधारकों के प्रति नेतृत्व की जवाबदेही और उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा अपनी बड़ी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बारे में है। हम इस लक्ष्य के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। हम कैम्पस में सामाजिक रूप से संवेदनशील और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं।

नेतृत्व, जो परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है

उच्च शिक्षा संस्थानों के नेताओं के रूप में, हम एनईपी 2020 को लागू करने की सच्ची भावना के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। यह एक ऐसा संकल्प है जो किसी जनादेश के कारण नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण का परिणाम है। हम जुनून के साथ काम करने, करुणा के साथ नेतृत्व करने और दृढ़ विश्वास के साथ हासिल करने की प्रतिबद्धता देते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति ने 'गुरु' और उनके 'मार्गदर्शन' के महत्व को दर्शाया है। हम उस दिशा में काम करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं।

SOME SNIPPETS FROM THE SUMMIT







Vikram University
Ujjain, M.P

उज्जैन शैक्षणिक
सम्मेलन
18 जनवरी 2023

उज्जैन शैक्षणिक सम्मेलन

इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में 'अकादमिक नेतृत्व की राष्ट्रीय कार्यशाला' के सफल आयोजन के उपरांत मध्यप्रदेश के उज्जैन में स्थित विक्रम विश्वविद्यालय के प्रांगण में 'द उज्जैन एजुकेशन समिट' का आयोजन किया गया। आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र व प्रख्यात उज्जैन नगरी में 18 जनवरी 2023 को एक-दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा समागम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस समागम का उद्देश्य भारतीय शैक्षिक संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्वानों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों व देश-विदेश के अन्य गणमान्यों को चर्चा-परिचर्चा के माध्यम से समान मंच उपलब्ध कराकर भारत के गौरवशाली ज्ञान परंपरा को वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था से जोड़कर राष्ट्र के वैभव को पुनर्प्राप्त करने के योजना पर मंथन करना था।

कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान के आशीर्वाद के साथ अत्यंत उत्साह व उल्लासपूर्वक वातावरण में हुआ। तत्पश्चात, विक्रम विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलसचिव श्री डॉ० प्रशांत पौराणिक जी द्वारा अपने उद्बोधन के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित समस्त गणमान्यों व मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात विक्रम विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रो० अखिलेश कुमार पाण्डेय ने स्वागत भाषण के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा पर अपने मत प्रस्तुत करने के लिए पधारे विद्वानों व इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए उपस्थित हुए सभी गणमान्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। माननीय कुलपति ने भारत के पारंपरिक भाषाई संस्कृति के आवश्यकता पर जोर देते हुए भारत में इसके तत्काल पुनरुद्धार की बात कही। तत्पश्चात, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रचित पुस्तक 'परीक्षा वीर' का सम्मानित महानुभावों द्वारा लोकार्पण किया गया। हिन्दी व अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में अनुवादित व प्रकाशित यह पुस्तक भाषा आधारित अवरोधों को तोड़ने के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित भी करती है। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री जी के द्वारा परीक्षा विषय पर दिए गए समस्त उद्बोधनों का संग्रह है। यह पुस्तक परीक्षा को लेकर तनावग्रस्त रहने वाले युवाओं व अभिभावकों को परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव से बुद्धिमतापूर्वक सामना करने में मानसिक सहायता मिलेगी।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रो० एन.के तनेजा (राष्ट्रीय महासचिव, विद्या भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान) को कार्यक्रम में सम्मिलित हुए गणमान्यों को सम्मेलन के विषयवस्तु से संक्षिप्त परिचय कराने के लिए आमंत्रित किया गया, जिससे वे कार्यक्रम के लक्ष्यों व उद्देश्यों से परिचित हो सकें। प्रोफेसर तनेजा के उद्बोधन के उपरांत मध्यप्रदेश सरकार के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉ० मोहन यादव को अपने विचार व्यक्त करने हेतु मंच पर आमंत्रित किया गया। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भारतीय ज्ञान परंपरा विषयक पर किए जा रहे शैक्षणिक सम्मेलन के लिए विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान व विक्रम विश्वविद्यालय के प्रयासों की प्रशंसा की गयी। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का पूर्ण मत है कि, भारतीय ज्ञान परंपरा का भारतीय शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सकारात्मक बढ़ोत्तरी देखी गयी। उन्होंने कहा "हम हजारों वर्षों से भाषा व बोली के अवरोध के बिना आपसी संवाद स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। डॉ० यादव ने मध्यप्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वित करने में संस्थानों द्वारा अपनाए गए श्रेष्ठ कार्यप्रणाली की सराहना भी की।



डॉ. मोहन यादव



श्री मंगुभाई पटेल



प्रो प्रकाश मणि त्रिपाठी



प्रो. अखिलेश कुमार पांडेय



डॉ कैलाश चंद्र शर्मा

कार्यक्रम की शोभा को और अधिक विस्तार देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा माननीय राज्यपाल(मध्यप्रदेश), श्री मंगुभाई पटेल जी को आमंत्रित किया गया। माननीय राज्यपाल द्वारा मध्यप्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हुए नवाचारों व सुधारों के बारे में उपस्थित जनसमूह को अवगत कराया गया। उनके द्वारा मध्यप्रदेश के शिक्षा विभाग के कार्यों का सिंहावलोकन भी प्रस्तुत किया गया। अपने उद्बोधन में नए शिक्षा नीति की उपयुक्तता को बताते हुए उन्होंने कहा कि, “नई पीढ़ी को विदेश का इतिहास तो मालूम है लेकिन उन्हें अपने देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। नई शिक्षा नीति इस समस्या के समाधान को ध्यान में रखकर बनाई गयी है।” अपने उद्बोधन को आगे बढ़ाते हुए माननीय राज्यपाल ने उज्जैन के गौरव का बखान किया, उन्होंने कहा उज्जैन शहर भारत की शैक्षिक और सांस्कृतिक विरासत में एक अद्वितीय स्थान रखता है। यह वही स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने विद्या ग्रहण की, उज्जैन नगरी महाकवि कालिदास व राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों के लिए भी जाना है, जिसमें महान खगोलविद वराहमिहिर का भी नाम आता है। भारतीय ज्ञान प्रणाली के प्राचीनता को स्वीकार करते हुए माननीय राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि, “भारत की एक समृद्ध ज्ञान परंपरा है जिसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित किया गया है। भारत में तक्षशिला व नालंदा दो ऐसे शिक्षा के केंद्र रहे हैं, जिनके बारे में आजतक चर्चा की जाती है।” माननीय राज्यपाल ने भारत के समृद्धि का वर्णन करते हुए कहा कि, “एक समय भारत में ‘दूध-दही की नदियां’ प्रवाहित हुआ करती थी। हालांकि, अब इसके पतन के संकेत समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं।”

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, ‘भारत बोध तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली’ विषयक से प्रथम सत्र का आगाज़ किया गया। विद्वान वक्ताओं से सुसज्जित पैनल जिसमें प्रोफेसर सरोज शर्मा ,(अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान) डॉ रितेंद्र शर्मा, (अध्यक्ष- CIS इंडस यूनिवर्सिटी ,अहमदाबाद) डॉ रमन सोलंकी, (पुरातत्व विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय)तथा प्रोफेसर N.K तनेजा, (राष्ट्रीय महासचिव VBUSS) की गरिमामयी उपस्थिति रही। विद्वान वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि, “इंडिया, यानी भारत, केवल मजबूत नागरिक संबंधों के आधार पर टिका हुआ देश नहीं है, बल्कि यह तो युगों से निरंतर चली आ रही प्राचीन सभ्यता का प्रतिफल है।” भारत का विचार इसमें निहित है कि, भिन्न बोली, भाषा, मत, संप्रदाय व वेशभूषा होने के पश्चात भी हम एक ही सभ्यता से उपजे हुए लोग हैं, तथा समान सभ्यता के कारण एक ही प्रकार के गुण-तत्व को धारण करते हैं। विद्वान वक्ताओं ने समझाया कि भारत केवल राज्य या भौगोलिक आधार पर विभाजित भूमि का टुकड़ा नहीं है बल्कि यह विश्व का वह प्राचीन भू-भाग है जो समान नागरिक सभ्यता व परंपरा के आधार पर रचा-बसा है। हजारों वर्षों से उद्भावित होती आ रही भारत और भारत की ज्ञान प्रणाली यहाँ के समृद्ध संस्कृति व बौद्धिक विरासत को संदर्भित करती है। भारत की ज्ञान परंपरा विभिन्न मत, दर्शन व सांस्कृतिक परंपराओं के सम्मिश्रण का प्रतिफल है। ‘भारतीय ज्ञान परंपरा’ सृष्टि को समग्रता के दृष्टिकोण से देखने की विशेषता धारण की हुई है, तथा तर्क व रहस्य के अंतर्दृष्टि को जोड़ती है। वक्ताओं ने कहा कि, भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण अवयव ‘आत्मचेतना’ व ‘आध्यात्मिक जागृति’ पर केंद्रित है। भारतीय ज्ञान परंपरा का गणित और विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उदाहरणार्थ- प्राचीन भारतीय गणितज्ञों के द्वारा बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान किए गए तथा भारतीय खगोल वैज्ञानिकों के द्वारा एक सौर वर्ष की लंबाई का सटीक गणना किया जाना विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित करता है।

प्रथम सत्र का समापन-

इस सत्र को संचालित कर रहे समस्त विद्वानों द्वारा संबंधित विषय से जुड़े तर्कों को सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत किया गया तथा यह निष्कर्ष निकाला गया कि, भारत बोध तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली के माध्यम से भारत द्वारा विज्ञान, साहित्य, कला, शिल्प सहित ज्ञान के विभिन्न आयामों में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है, जिससे विश्वसमुदाय युगों-युगों तक प्रेरणा प्राप्त करता रहेगा।

कार्यक्रम पुनः दूसरे सत्र के साथ प्रारंभ होता है। इस सत्र का उद्देश्य भारतीय भाषाओं को एक ऐसे तत्व के रूप में प्रस्तुत करना था, जो भारत को ‘एक राष्ट्र’ के रूप में संगठित रखने के कारक बनें। विद्वान वक्ताओं के परिचय के साथ सत्र की शुरुआत की जाती है, पैनल में उपस्थित विद्वानों में प्रोफेसर धनंजय सिंह (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) श्री अशोक कदल(अध्यक्ष, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, मध्यप्रदेश) प्रोफेसर अवधेश कुमार मिश्र (भारतीय भाषा समिति) तथा प्रोफेसर किरण हज़ारिका(नॉमिनी, भारतीय भाषा समिति) की गरिमामयी उपस्थिति रही।

संबंधित विषय पर बोलते हुए मंचासीन विद्वानों के कहा कि, भारत सांस्कृतिक विविधता को धारण किया हुआ बहुभाषिक राष्ट्र है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत कुल 22 भाषा व 1600 बोलियों वाला देश है। भाषाई विविधता भारत की एक अनन्य विशेषता मानी जाती है, जिसने भारत को संगठित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जिसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है।

पहला, भारतीय संविधान देश के भाषाई विविधता वाले चरित्र के संरक्षण व संवर्धन का प्रबल पक्षकार है, तथा भाषा के अधिकार को मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करता है। इस अधिकार से भाषाई बहुलतावाद को बढ़ावा मिलने तथा यह सुनिश्चित करने में सहायता मिली की प्रत्येक भारतीय अपने मातृभाषा को स्वंत्रतापूर्वक बोल व सीख सकें। भारतीय इतिहास ऐसे उदाहरणों से पटा पड़ा है, जिसमें भाषाओं ने देश को संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। स्वंत्रता का आंदोलन इसका प्रमुख उदाहरण है। वक्ताओं ने बताया कि, भाषा की शक्ति ने आंदोलन के नेताओं और जनता के बीच एक सेतु का कार्य किया। जनता को संगठित करने के लिए तत्कालीन स्वतन्त्रता सेनानी नेतृत्वकर्ताओं ने भाषा को एक प्रभावी हथियार के रूप में प्रयोग किया। स्वाधीनता आंदोलनों के दौरान विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रसारित किए गए देशभक्ति गीत व ओजस्वी भाषणों ने जनता के राष्ट्रीय भावनाओं को झकझोर के रख दिया, जिससे उनके भीतर एकता की भावना उत्पन्न हुई और वे स्वाधीनता प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध हुए।

तीसरा, देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैले जनसमुदाय के मध्य सांस्कृतिक विनिमय व व्यवहार को बढ़ावा देने में भाषा एक प्रमुख तंत्र के रूप में उभरा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में फैले लोग देशज भाषाओं में संवाद कर सकने में सक्षम हुए। परिणामस्वरूप इससे भाषाई अवरोधों को तोड़ने के साथ ही अंतर-सांस्कृतिक व्यवहारों को समझने में बढ़ावा मिला।

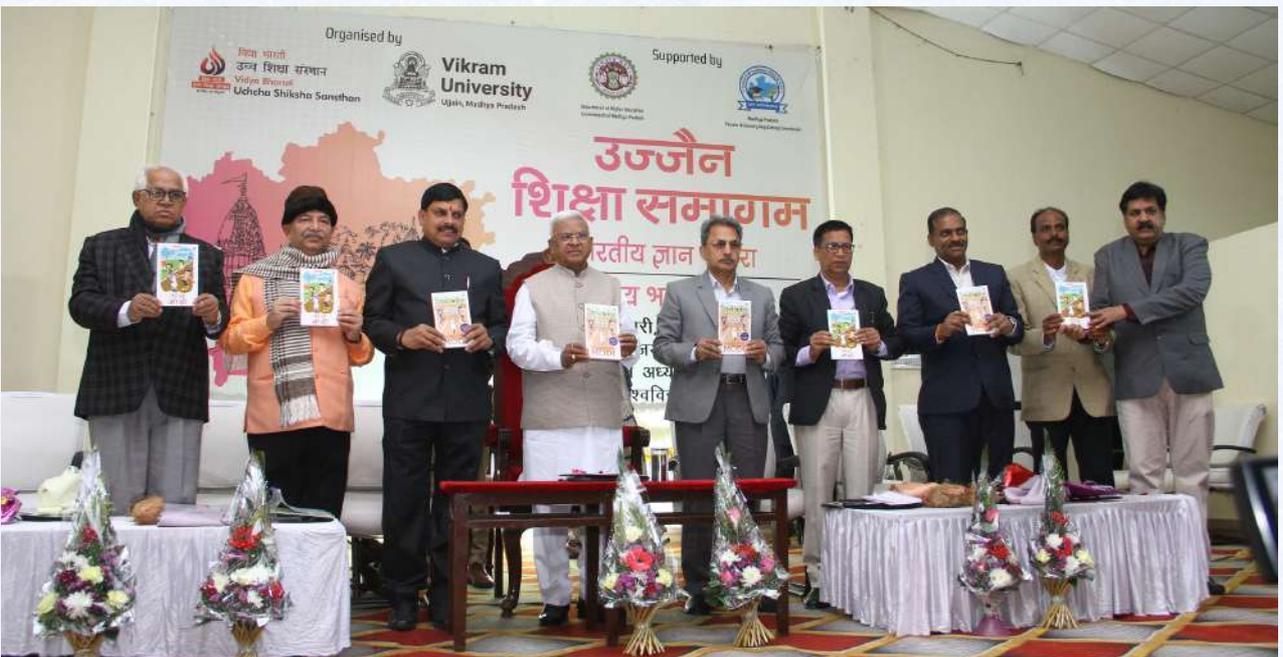
चौथा, भारत की भाषाई विविधता ने साहित्य, संगीत व कला के क्षेत्र में देश को अनमोल धरोहर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सत्र इस कथन के साथ समाप्ति की ओर बढ़ा कि, प्रत्येक भाषा स्वयं में विशिष्टता को धारण किए हुए है, तथा प्रत्येक की अपनी साहित्यिक परंपरा व कलात्मक अभिव्यक्ति है, जिसने भारत के सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित व संवर्धित करने का कार्य किया है।

यह सत्र इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि, भाषाई विविधता को बढ़ावा देकर, राष्ट्रीय पहचान का निर्माण, अंतर-सांस्कृतिक विनिमय तथा भारत के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने में भारतीय भाषाओं की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर शैक्षणिक सम्मेलनों के माध्यम से सम्मानित विद्वानों, शोधार्थियों तथा विचारकों को समान मंच उपलब्ध कराकर सारगर्भित विचार मंथन का यह शैक्षणिक सम्मेलन प्रत्येक दृष्टिकोण से सफल रहा है।

सम्मेलन में विद्वतजनों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न दृष्टिकोण, चिंतन व सामूहिक मंथन ने विषय से संबंधित ज्ञान व बोध को समृद्धि प्रदान की तथा पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधियों की जिज्ञासापूर्वक सक्रियता, विषय से जुड़ाव व ज्ञानवर्धक चर्चाओं ने इस कार्यक्रम के सफलता व इसके गंभीर विषयवस्तु के महत्व को और अधिक सिद्धि प्रदान की।



Organised by



विद्या भारती
उच्च शिक्षा संस्थान
Vidya Bharati
Uchcha Shiksha Sansthan



Supported by

